हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

18 मार्च, 1983

खंड 1, अंक 10

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भुक्रवार, 18 मार्च, 1983

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(10)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(10)27
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(10)36
विभिन्न विशयों का उठाया जानाः–	
1. राज्य में सिविल विमानन पट्टियों में कुप्रबन्ध सम्बन्धी	(10)42
2. सहकारी बैंक सिरसा में हरिजनों की नियुक्तियों में आरक्षण सम्बन्धी	(10)42
वाक आउट	(10)42
अध्यक्ष द्वारा रूलिंगः–	
बजट के अभिकथित लीक होने के बारे में ब्रीच आफ प्रिविलिज के प्र न सम्बन्धी	(10)43
ध्यानाकर्शण प्रस्तावः–	

महिला आश्रम, करनाल में रह रहे बंगला दे ा के भारणार्थियों की मांगों सम्बन्धी	(10)44
वक्तव्यः—	
समाज कल्याण मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी	(10)44
वर्श 1983—84 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(10)47
राज्यपाल से सन्दे ा	(10)53
वर्श 1983—84 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(10)54

हरियाणा विधान सभा

भुक्रवार, 18 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़, में. प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज अब सवाल होंगे।

Share of Haryana in Thein and Pong Dam

***71. Smt. Chandravati:** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state:-

(a) the date on which the construction work on Thein Dam and Pong Dam was started together with the details of progress so far made in the construction thereof and the time by which the aforesaid Dams are likely to be completed;

(b) the share of water allotted to the Haryana State from the said Dams as referred to in part(a) above together with the details of yearly amount being paid by the Haryana Government for the construction thereof; and

(c) the number of officers, officials belonging to Haryana State working on these Dams?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला):

(क) पोंग डैम के निर्माण का कार्य 1965 में भुरू हुआ और मई, 1974 में पूरा हुआ। थीन डैम के निर्माण का कार्य, पंजाब सरकार के अधीन, पूरी गति से चालू नहीं हुआ तथा इसके पूरा होने की तिथि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ख) हरियाणा को पानी का हिस्सा प्रत्येक डैम को अलग अलग लेकर एलोकेट नहीं किया गया है। थीन डैम और पोंग डैम के जला ाय में कुल जमा पानी, ब्यास के फालतू पानी को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जम्मू क मीर तथा देहली में बांटने के लिए ध्यान में रखा जाता है, फिर भी हरियाणा राज्य को रावी–ब्यास के फालतू पानी का हिस्सा जो 3.5 एम0ए0एफ0 है, उस पानी में से, जो ब्यास सतलुज लिंक के माध्यम से ब्यास का पानी भाखड़ा में डाला जाता है, से मिलता है। थीन डैम के न बनने से 0.617 एम0ए0एफ0 पानी माधोपुर के नीचे पाकिस्तान को व्यर्थ चला जाता है। थीन डैम के बनने पर यह व्यर्थ जाने वाला पानी भी बंद हो जायेगा तथा हरियाणा व दूसरे संबंधित राज्यों को इसका फायदा होगा।

पौंग डैम तथा संबंधित कार्यों के निर्माण के लिये वार्शिक रा ि ा का विवरण जो कि हरियाणा सरकार द्वारा अदा की गई है, निम्न प्रकार है:–

वर्श	रा ि ा (रूपये लाखों में)
1979–80 तक	3374
1980–81	144
1981–82	132
1982–83 (अनुमानित)	140

थीन डैम के लिये अभी तक हरियाणा सरकार ने कोई रा ि ा अदा नहीं की और न ही पंजाब सरकार ने कोई रा ि ा मांगी।

(ग) ब्यास परियोजना जिसमें पौंग डैम भी भाामिल है, पर हरियाणा राज्य के निम्मनलिखित अधिकारी/कर्मचारी कार्य कर रहे है:–

पौंग डैम

अधिकारी	79
कर्मचारी	440
कुल	519

थीन डैम पर हरियाणा का कोई अधिकारी/कर्मचारी कार्य नहीं कर रहा है।

श्रीमती चंद्रावतीः जनाब स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब मैं बताया है कि पौंग डैम के लिए इतनी रकम दी है। मैं मंत्री महोदय से इसका ब्रेक–अप जानना चाहती हूं कि किस चीज पर कितना–कितना रूपया खर्च हुआ क्योंकि हमें डर है कि इसमें बहुत ज्यादा एम्बेजलमैंट हुई है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः बहिन जी, आपन ईयरवाइज ब्रेक–अप मांगा था वह मैंने दे दिया है। इस डैम पर लगभग 300 करोड़ रूपया खर्च हुआ है। यह डैम ज्वायंट पंजाब में बनना भाुरू हुआ था, उसके एक साल बाद हरियाणा और पंजाब अलग–अलग हो गए। इसे ब्यास कंसट्रक ान बोर्ड ने बनवाया है।

श्रीमती चंद्रावतीः मैं इसकी हिस्ट्री नहीं जानना चाहती। मैं अलग अलग आइटम्ज के बारे में जानना चाहती हूं कि कितना कितना रूपया खर्च हुआ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः इस वक्त आडिटिड अकाउंट्स की कापी मेरे पास नहीं है। अगर वह मिल गई तो उसे भी भिजवा दूंगा। आपने जो कुछ सवाल में पूछा था वह मैंने बता दिया है, इससे ज्यादा ब्यौरा मैं क्या दे सकता हूं?

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अपने जवाब के (ख) भाग में फरमाया है कि प्रत्येक डैम से हरियाणा को पानी

का हिस्सा अलग अलग एलोकेट नहीं किया गया है। लेकिन सवाल यह पूछा गया था कि थीन बांध और पौंग बांध में कितना कितना हिस्सा मिल रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि थीन डैम और पौंग डैम से भाखड़ा जला ाय में कितना पानी आता है और उनमें से हरियाणा को कितना हिस्सा मिलता है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः थीन डैम के पानी में हरियाणा का सैपरेटली कोई हिस्सा नहीं है लेकिन बिजली में है। थीन डैम में जब पानी 17.17 एम0ए0एफ0 से ज्यादा होगा उस वक्त हमें पानी मिलेगा और साल में सात–आठ महीने 17.17 एम0ए0एफ0 से ज्यादा ही पानी होता है। थीन डैम का पानी हरेक बांध से 3.5 एम0ए0एफ0 से ऊपर मिलेगा।

श्री मंगल सैनः मैंने यह पूछा है कि भाखड़ा में थीन डैम और पौंग डैम का सारा पानी चला जाता है, उसमें से हमे कितना पानी मिलता है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब थीन डैम का पानी भाखड़ा में तो आ ही नहीं सकता, इस बात को डाक्टर साहब भी समझते होंगे। इन्होंने यह पूछा था कि पौंग डैम और थीन डैम से हरियाणा को कितना कितना पानी मिलता है। मैंने जवाब दिया है कि अलग अलग पौंग डैम और थीन डैम से पानी में हिस्सा नहीं है क्योंकि यह सारा पानी भाखड़ा

रिजरवायर में इक्ट्ठा हो जाता है। वहां से हरियाणा अपना भोयर 3.5 एम0ए0एफ0 ड्रा करता है।

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने सवाल के जवाब में बताया है कि थीन डैम की कंस्ट्रक ान का काम केवल पंजाब वाले कर रहे है। न हमारे कर्मचारी काम कर रहे है और न ही हमारी रा ाी गई। पंजाब वाले यूनिलेटरली कैसे काम भाुरू कर रहे है? क्या इससे हमारा हिस्सा नहीं रह जाएगा?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः हरियाणा का हिस्सा सैंट्रल गवर्नमैंट और पंजाब गवर्नमैंट ने माना हुआ है और रिकगनाइजड है। लेकिन यह अभी डिटरमिन करना है कि कितना हिस्सा है। उसके लिए लगातार प्रैस कर रहे है। जब चौधरी बीरेंद्र सिंह जी मंत्री थे, उस समय का इनको पता है।

श्री बीरेंद्र सिंहः यह रा ि ा क्यों नहीं दी जा रही है।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः हम सैंट्रल गवर्नमैंट से इन–टच है और हर मीटिंग में प्रैस करते है कि इस मामले को जल्दी से निपटारा करवाए।

श्री नेकी रामः स्पीकर साहब, थी डैम और पौंग डैम में हरियाणा के हिस्से का है कि हमें बिजली और पानी का कितना कितना हिस्सा मिला है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ब्यास परियोजना यूनिट–1 से और ब्यास परियोजना

यूनिट–2 में कितनी बिजली पैदा होती है और हमें उसमैं से कितना हिस्सा मिलता है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः हमें दोनों से बिजली का पूरा हिस्सा मिल रहा है।

श्री नेकी रामः मैं मैगावाट में जानना चाहता हूं कि कितने मैगावाट बिजली मिल रही है।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः देहर बिजली घर में 990 मैगावाट की इंस्टाल्ड कैपेसिटी है, उसमे से राजस्थान को 58.5 परसैंट और ज्वायंट पंजाब को 41.5 परसैंट हिस्सा मिलता था। हरियाणा और पंजाब बनने के बाद 40 और 60 के रे ाों में बांटा गया था। हरियाणा को सोलह परसैंट बिजली का हिस्सा बनता है। हमें पूरा हिस्सा मिल रहा है। पानी का भी पूरा भोयर ले रहे है।

श्री हीरा नंद आर्यः क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि थीन डैम में कितने परसैंट हिस्सा कलेम किया है और कितने परसैंट रा ि ा देने का विचार है? पाकिस्तान को 0.617 एम0ए0एफ0 पानी जा रहा है, क्या पाकिस्तान से इस पानी का मुआवजा कलेम किया है।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः थीन डैम की इन्स्टालड कैपेसिटी 480 मैगावाट के करीब होगी। हमारा कलेम

चालीस और साठ की रे ाों से बनता है लेकिन अभी डिटरमिन नहीं हुआ है।

श्री फतेह चंद विजः मंत्री महोदय ने यह बताया है कि अभी तक थीन डैम के लिए कोई रा ाी पंजाब सरकार को नहीं दी गई है। हरियाणा को बने हुए 17 साल हो गये है। इतने सालों तक यह रा ि ा न देने से क्या हरियाणा के क्लेम को नुकसान नहीं पहुंचेगा।

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य महोदय को यह बताना चाहता हूं कि यह डैम तो अभी बनना भी भारू नहीं हुआ। इसलिये 17 साल का सवाल ही कहां पैदा होता है?

श्री कंवल सिंहः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि थीन डैम कब तक बनकर कम्पलीट हो जायेगा और बनने के बाद उसका रेगुले ान और कंट्रोल बी0बी0एम0बी0 के पास रहेगा या पंजाब सरकार के पास रहेगा।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय, से मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस थीन डैम के पूरा होने की कोई तिथि या टाईम जो अनुमानित हो, बता सकते है अगर नहीं बता सकते तो इसके क्या कारण है?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, थीन डैम के कम्पलीट होने का जहां तक ताल्लुक है, यह तो पंजाब

गवर्नमैंट ने बनाना है। दूसरी बात यह है कि इस पर अभी तक फुल स्विंग से काम भाुरू नहीं हुआ है। तीसरे अभी फाइनैंि ायल स्ट्रेजैंसीज है। हमने इसकी टैटेटिव डेट के बारे में दूसरी स्टेटस से पता किया है, उसके मुताबिक यह 1989 तक पूरा होने की आ ाा है।

श्रीमती चंद्रावती: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो 0.617 एम0ए0एफ0 पानी पाकिस्तान को बेकार जा रहा है, इसके बारे में उन्होंने किन तिथियों को और कितने पत्र सैंट्रल गवर्नमैंट को या पंजाब गवर्नमैंट को लिखे है ताकि इसका कोई न कोई बंदोबस्त जल्दी से जल्दी किया जाये?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, इन्होंने जो पत्रों की तिथियां पूछी है, वह मैं जुबानी बता सकता। हां, इतना जरूर बता सकता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने और मैंने अकेले ही नहीं बल्कि कई बार साथ–साथ भी इस बारे में काफी स्ट्रौंगली प्रेस किया है कि इसका बंदोबस्त जल्दी किया जाये। (व्यवधान व भाोर)

श्रीमती चंद्रावती: तिथि नहीं बता सकते तो कोई साल या महीना ही बात दो जब आपने चिट्ठी लिखी हो? (व्यवधान व भाोर)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: जुबानी कुछ नहीं बताया जा सकता।

Loans for the development of small scale or cottage industries

***89. Chaudhri Balbir Singh Grewal:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) whether there is any scheme for the grant of loans by the Government for the development of small scale or cottage industries in the backward areas in the State; and

(b) if so, the districwise total amount of loans advanced for the said purpose during the years, 1979-80, 1980-81 and 1981-82, separately?

Industries Minister (Shri Lachhman Singh):

(a) Yes.

(b) Statement containing the relevant information is placed on the Table of the House.

STATEMENT

Statement showing district-wise total amount of loans advanced in the backward areas

Sr. No.	District	1979-80	1980-81	1981-82
1	Hissar	3,93,000	2,12,470	2,03,000
2	Bhiwani	2,10,000	1,24,500	1,25,000
3	Jind	2,48,000	2,27,230	1,75,000

4	Mohindergarh	3,15,000	1,54,000	53,000
5	Ambala (Naraingarh & Kalka Tehsil)	23,400	4,000	37,000
6	Rohtak (Nahar Tehsil)	13,000	-	12,000
7	Mewat	-	17,22,000	20,00,000

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः स्पीकर साहब, हरियाणा में अनएम्पलायमैंट की बड़ी जबरदस्त प्रोब्लम है। वैसे तो सारे दे ा में ही यह प्रोब्लम है और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को एंकेजमैंट देने से ही यह प्रोब्लम हल हो सकती है। इसलिए मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो स्माल स्केल या कोटेज इंडस्ट्रीज के लिए दी जाने वाली रा ाी प्रति वर्श घटती चली जा रही है, इसके क्या कारण है?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, भाायद इनका यह सवाल पूछने का मतलब नहीं था। इन्होंने सिर्फ गवर्नमैंट एजेंसी से पूछा है कि क्या कोई ऋण देने की योजना है। स्टेट गवर्नमैंट अपने रिसोर्सिज से लिमिटिड पैसा ही दे सकती है। इस मकसद के लिये हमने सिर्फ दस लाख रूपया रखा हुआ है। 1935 में यह एक्ट बना था। उस समय आप अंदाजा लगा सकते है कि कितनी इंडस्ट्रीज लगी हुई होंगी

और अब कितने फाइनैंि ायल इंस्टीच्यू ांज मार्किट में आ गये है जहां से इंडस्ट्री लगाने वाला ऋण ले सकता है। कारपोरे ांज हैं, बैंक्स है और दूसरे अदायरे है जहां से लेागों को काफी लोन मिल जाता है। सरकार की तरफ से जो दस लाख रूपया रखा जाता है, वह भी पूरी तरह से डिस्बर्स नहीं हो पाता क्योंकि लोग लेने के लिये नहीं आतें। जहां तक हमारी फाइनैंि ायल कारपोरे ान का ताल्लुक है, उसने इस साल 22 करोड़ रूपया लोन दिया है। दरअसल इनसे सवाल पूछने में गलती हो गयी है। सवाल जो इन्होंने पूछा है, वह यह है–

"Whether there is any scheme for the grant of loans by the Government."

इनका मकसद यह था कि जितना भी लोन फाइनैंि ायल इंस्टीच्यु ान्ज द्वारा दिया जाता है, उसके बारे में बताया जाए। इन्होंने तो यह गलती से पूछ लिया और मैंने भी बता दिया है कि गवर्नमैंट बहुत ज्यादा लोन नहीं देती है। (व्यवधान व भाोर)

श्री भले रामः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय, से यह पूछना चाहता हूं कि जो लोन काटेज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को दिया जाता है, इस पर रेट आफ इंट्रैस्ट क्या चार्ज किया जाता है?

श्री लछमन सिंहः सर, रेट्स मुख्तलिफ है। स्पीकर साहब, 25,000 रूपये तक के लोन के लिए रेट आफ इंट्रैस्ट दस

प्रति ात है और 25,000 से ले कर 50,000 रूपये तक के लिए बारह प्रति ात है। अगर कोई लोनी टाईम पर लोन अदा कर देता है तो उसको चार प्रति ात रिबेट दिया जात है।

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, जो फाइनैंि ायल इंस्टीच्यू ांज है, जो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए लोन देते है इन्होंने, 1981–82 और 1982–83 में कितना कितना लोन इंडस्ट्रीज को दिया है, कया वे इसकी ब्रेक–अप देने की कृपा करेंगे?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, इस सवाल में तो इन्होंने यह इंफर्मे ान मांगी नहीं है, अगर मांगते तो मैं दे देता।

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय जी ने जो जवाब दिया है, उसके मुताबिक 1979–80 में 3,15,000, 1980–81 में 1,54,000 और 1981–82 में केवल 53,000 रूपया महेंद्रगढ़ जिले में लोन दिया गया है। क्या वे यह बताने की कृपा करेंगें कि हर साल लोन की फिगर में कमी, लोन वालों को दरख्वास्तों में कमी होने की वजह से है या विभाग का व्यवहार ऐसा है जिसकी वजह से लोन लेने वाले निरूत्साहित होकर दूसरी एजेंसीज के पास लोन के लिए चले जाते है? इस में कहां पर गड़बड़ है?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके फाजिल दोस्त को यह बताना चाहता हूं कि महेंद्रगढ़ जिले के लिए 1979–80 में चार लाख सत्तर हजार रूपया एलोकेट किया गया

था लेकिन लोगों ने सिर्फ 3.15 लाख रूपये के लिए लोन लिए। इसी तरह से 1980–81 में हमने एलोकेट किया था 4.51 लाख रूपया और यूज हुआ सिर्फ 1.54 लाख। आप ही देखिये, इसमें स्टेट गवर्नमैंट का तो कोई कसूर नहीं हैं। फिर 1981–82 में हमने एलोकेट किया 3.38 लाख रूपया और यूज हुआ सिर्फ 53,000 रूपया। जैसे कि मैंने बताया कि दूसरे फाइनैंि ायल इंस्टीच्यु ान्ज भी आजकल ऐसे है जो लोगों को पैसा देते है और उन से इजीली पैसा मिल जाता है, इसलिए इस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। (व्यवधान व भाोर)

श्री मंगल सैनः इनका कहना यह है स्पीकर साहब, कि इनके डिपार्टमैंट के बारे में कोई भी सवाल पूछ लें, he is prepared for that. मैं इनके इसी जवाब से सवाल पूछने के लिये प्रेरित हुआ हूं। मैं इनसे एक बात जानना चाहता हूं कि क्या इनके नोटिस में यह बात है कि लोग रूरल इंडस्ट्रीज स्कीम के तहत कर्जा लेने के लिये धक्के खाते फिरते है, लेकिन उनकों बैंक्स कर्जा नहीं देते, अगर ऐसा है तो गवर्नमैंट ने इस का क्या उपाय किया है?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, मैं इस बात से इंकार नहीं करता। यह कभी कभार सुनने में आता है कि किसी को डिफीकल्टी है। इसमें कोई भाक की बात नहीं है कि बैंक्स ने भी अपनी फार्मेलिटीज पूरी करनी होती है। After all, it is the people's money which they have to advance. यह किसी का

अपना पैसा तो है नहीं। कई बार लोग फार्मेलिटीज को फुलफिल नहीं करते, कई जगह कोई और फार्मेलिटी पूरी करनी होती है। अगर स्टेट गवर्नमैंट के पास ऐसी कोई ि ाकायत आती है तो गवर्नमैंट लोन दिलाने के लिए लोगों की मदद करती है। मैंने कई जगह पर टैलीफोन भी किया है और लोगों के केसिज थ्रू करवाये है। अगर किसी का केस पैंडिंग हो, तो डाक्टर साहब बता दें, हम पूरी–पूरी कोि ा ा करेंगे कि उसको जल्दी जल्दी लोन दिलवा दें।

श्री निहाल सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय, ने बताया है कि इंडस्ट्रीज लगाने के लिए लोन दिया जाता हैं मैं उन से यह पूछना चाहता हूं कि क्या बैकवर्ड एरियाज के लिए लोन के साथ–साथ कोई सबसिडी वगैरा भी दी जाती है, अगर हां तो वह कितनी होती है? अगर लोन में सबसिडी होने के बावजूद भी लोग आगे नहीं आते तो गवर्नमैंट उन्हें इन्वाईट करने के लिए कदम उठा रही है ताकि जो टार्गेट गवर्नमैंट फिक्स करती है, वह पूरे हो सकें? अगर इस काम में किसी अधिकारी की गलती हो तो उसके खिलाफ एक ान लिया जाना चाहिए।

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, अगर कोई आदमी लोन लेने के लिए नहीं आता तो उसके लिए किसी भी अधिकारी के खिलाफ एक ान नहीं लिया जा सकता। लोग अपने आप नहीं आये होंगे, इसलिए हम पूरा लोन नहीं बांट सके। मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या इसके अंदर सबसिडी है। मैं यह बताना चाहता हूं

कि लोन के अंदर कोई सबसिडी नहीं है, लेकिन इन्वैस्टमैंट के अंदर सबसिडी मिलती है। इनका मकसद स्टेट सबसिडी से है या सैंट्रल सबसिडी से है। यस मैं समझ नहीं सका। (व्यवधान व भाोर)

श्री निहाल सिंहः मेरा मतलब स्टेट सबसिडी से है।

श्री लछमन सिंहः आर0आई0 स्कीम के तहत हम मेवात एरिया में 15,000 रूपये तक सबसिडी देते है। वहां हमने सैंट्रल सबसिडी का प्रिंसीपल एडौप्ट किया हुआ है।

श्री फतेह चंद विजः मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि रूरल इंडस्ट्रीज केग लिए इतने लाख रूपया ऐलोकेट किया हुआ है लेकिन लोग लेने नहीं आते है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कहीं इसका कारण यह तो नहीं हे कि रूरल इंडस्ट्रीज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज द्वारा जो माल तैयार होता है, उसको खरीदने वाला कोई नहीं होता और सरकार उस माल के खरीदने में उनकी कोई मदद नहीं करती है?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, आप जानते है कि स्माल स्केल इंडसट्रीज लार्ज स्केल इंडसट्रीज को तो कम्पीट कर नहीं सकती है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की तरह वह माल भी नहीं बनाती हैं इनका इ ाारा पानीपत में हैण्डलूम इंडस्ट्रीज की तरफ हो सकता है। उसके बारे में मेरा कहना है कि हैंडलूम इंडस्ट्री का कम्पीटी ान कोई मिल के साथ तो है नहीं। यह हो

सकता है कि किसी का माल न बिका हो क्योंकि जब कभी मार्किट में मंदा आता है तो माल कम बिकता है। यह स्थिति तो मिल के माल के साथ भी हो जाती है और उस समय हर इंडस्ट्री को धक्का लगता है, स्माल स्केल इंडस्ट्री ही अकेली नहीं है।

श्री नेकी रामः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जितना रूपया इंडस्ट्री के लिए अलाट किया गया है, उसमें हरिजनों का कितना हिस्सा है और उसमें से कितना दे दिया गया है और कितना बकाया है।

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, इसमें हरिजनों के लिए रिजर्वे ान का सवाल नहीं है। यह तो इंडस्ट्री को लोन देने का सवाल है। अगर कोई हरिजन इंडस्ट्री लगाना चाहे तो हम उसको भी एट पार ट्रीट करते है। यह तो हो सकताह ै कि उसको पहले लोन दे दिया जाए लेकिन लोन में रिजर्वे ान नहीं है।

चौधरी कुंदल लालः स्पीकर साहब, जिला जींद जो पिछड़ा हुआ घोशित किया हुआ है और उसमें सफीदों सब से ज्यादा पिछड़ा हुआ सब–डिविजन है। क्या मंत्री महोदय इस पर ध्यान देकर इस इलाके को आगे लाने के लिए प्रयत्न करेंगे? (इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, इस मंहगाई के जमाने में एक हरिजन अकेले कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। ंइसलिए चौधरी देवी लाल के जमाने में एक स्कीम चलाई गई थी कि अगर

चार हरिजन मिलकर कोई इंडस्ट्री लगाएं तो उनको कुछ फैसिलिटीज दी जाती थी। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वह स्कीम दुबारा भाुरू की जाएगी या नहीं?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, आप जानते है कि आज के युग में दो भाइयों की भी इक्ट्ठी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, तो जनरल के साथ एक हरिजन का सांझा कैसे कामयाब हो सकता है। अगर कोई हरिजन किसी के साथ भाामिल होकर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे तो कोई पाबंदी नहीं है और यह बड़ी खु ाी की बात है।

श्री देवी दासः स्पीकर साहब, रूरल इंडस्ट्री के नाम से जितनी भी इंडस्ट्री लगी है और खासकर सोनीपत के इलाके में जो भी इंडस्ट्री लगी है, उनका माल कोई खरीदता नहीं है जबकि सरकार यह कहती है कि उन इंडस्ट्रीज का माल वह खरीदेगी लेकिन आजतक किसी एक इंडस्ट्री का भी माल सरकार नहीं खरीदती है? क्या मंत्री महोदय उनका माल खरीदने पर विचार करेंगे?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, उनका माल खरीदने के लिए एक कार्पोरे ान है जिसका नाम स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एंड ऐक्सपर्ट कार्पोरे ान है। यह कार्पोरे ान, रूरल इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक ान होती है उस माल को खरीदने की कोि ा ा करती है। यह बात दूसरी है कि कोई माल गलत बना हो या

स्पेसिफिके ान के मुताबिक न बना हो। अगर आनरेबल मैम्बर के नोटिस में कोई ऐसी बात है तो वे लिखकर भेज दें, ऐक ान ले लिया जाएगा।

श्री भले रामः अध्यक्ष महोदय, भाुरू में जो कोई इंडस्ट्री लगाता है उसको तजरूबा नहीं होता और उसकी इंडस्ट्री फेल हो जाती है और उससे लोन भी रिकवर नहीं होता। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह के सिक यूनिट्स की मदद करने की सरकार की कोई स्कीम है?

श्री लछमन सिंहः अध्यक्ष महोदय, जहां तक लोन रिकवर करने का सवाल है, वह तो इंडस्ट्री को नीलाम करके वसूल किया जा सकता है। सिक यूनिट की मदद सरकार क्या कर सकती है यह तो डिपैंड करता है कि किन हालात में वह सिक हुई है।

श्री बीरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि इस लाख रूपया रूरल इंडस्ट्रीज के लिए ऐलोकेट करते है लेकिन लोग उसको भी लेने के लिए नहीं आते है। दूसरे इंस्टीच्यु ांज से लोग लोन ले लेते है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि लोगों के दूसर इंस्टीच्यू ांज की तरफ अैट्रक्ट होने का कारण यह है कि उनका रेट आफ इंट्रैस्ट कम होता है या इनके महकमें वाले लोगों को इतना तंग करते है कि वे इधर आते ही नहीं है?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, लोगों को तंग करने वाली कोई बात नहीं है। बात यह है कि स्टेट गवर्नमैंट के बजट में पैसे का इतना प्रोवीजन नहीं होता। सरकार भी आई0डी0बी0आई0 से पैसा लेती है। बैंक्स का रेट आफ इंटैस्ट तो ज्यादा है इसमें कोई भाक वाली बात नहीं है। उनके पास डिमांड बहुत ज्यादा है और इतनी डिमांड बैंक्स ही पूरी कर सकते है।

चौधरी हुक्म सिंह फौगाटः स्पीकर साहब, देहात के लोग स्माल स्केल इंडस्ट्री लगाने के लिए बैंक्स के छः महीने तक चक्कर लगाते रहते है लेकिन उनको कर्जा नहीं मिलता और वे घर बैठ जाते है। क्या मंत्री महोदय बस बारे में लोगों की तकलीफ दूर करने की कृपा करेंगे ताकि बैंकों से कर्जा आसानी से मिल जाए?

श्री लछमन सिंहः अध्यक्ष महोदय, गाहे बगाहे चीफ मिनिस्टर साहब, बैंक्स के जनरल मैनेजर्ज और उनके औफिसर्ज और अपने औफिसर्ज की मीटिंग बुलाते रहते है। अध्यक्ष महोदय रिसैंटली एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है और इंडस्ट्रीज की समस्या को हल करने के लिए वन विंडों सर्विस भी भुरू की है। इस तरह से इंडस्ट्रीज की सारी की सारी तकलीफों को हल किया जा रहा है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, रूरल इंडस्ट्रीज के लिए सरकार ने कुछ फैसिलीटज प्रोवाइड की हुई थीं जैसे कर्जे की फैसिलिटी, सबसिडी की फैसिलिटी, दो साल तक सेल्ज टैक्स एग्जैम्ट करने की फैसिलिटी, आकट्राय की फैसिलिटी रा–मैटीरियल प्रोवाइड करने तथा माल को खरीदने की फैसिलिटी इत्यादि। अब इनमें से कुछ फैसिलिटीज को विदड्रा किया जा रहा है। इस वजह से कुछ फैक्टरीज बंद हो रही है और उनका प्रोडक ान आप का डिपार्टमैंट नहीं उठा रहा है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बारे में उनके पास कोई रिप्रैजेनटे ान आया है?

श्री लछमन सिंहः सारी फैसिलिटीज विदड्रा करने की बात नहीं है। सेल्ज टैक्स की बात है और उसके बारे में रिप्रैजेनटे ान आई है। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वैस्ट की है कि दो साल का जो पीरियड रखा है वह थोड़ा कम है, इसको बढाना चाहिए। रूरल इंडस्ट्रीज की तकलीफों को दूर करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड चाहिए। रूरल इंडस्ट्रीज की तकलीफों को दूर करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है और उसका चेयरमैन सैक्रेटरी इंडस्ट्री है। वह कमेटी इन बातों पर विचार करेगी कि उनको पैसा कैसे दिया जाए, उनका माल कैसे डिस्पोज औफ किया जाए। रूरल इंडस्ट्रीज का माल खरीदने के लिए हमारे पास स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एंड ऐक्सपोर्ट कार्पोरे ान है। वही इन इंडस्ट्रीज का माल खरीदती है। अगर

इनके इलावा रूरल इंडस्ट्रीज की और कोई दिक्कत होगी तो उन पर भी यह हाई पावर्ड कमेटी ही विचार करेगी।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्वायंट को और क्लीयर कर देना चाहता हूं। **(10.00 बजे)** हम लोगों को बिजली की, आक्ट्राय की और सेल्ज टैक्स की फैसिलिटीज सब को दे रहे है, हमने कोई विदड्रा नहीं की है और जहां तक सबसिडी देने का प्र न है, वह भारत सरकार एक करोड़ पर 15 लाख रूपये की सबसिडी देती है।

Depots of Haryana Roadways

***169. Shri Bhagi Ram:** Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) the present total number of depots and sub-depots of the Haryana Roadways in the State;

(b) the number of buses allotted to each depot, during the period from January, 1982 to January, 1983; and

(c) the depot-wise number of buses plying at present, separately?

Transport Minister (Col. Rao Ram Singh):

(a) Depots 14

Sub-depots 16

(b) The statement at Annexure I is laid on the Table of the House.

(c) The statement at Annexure II is laid on the Table of the House.

Depot-wise number of buses allotted to each depot during January, 1982 to January, 1983

Sr. No.	Name of depot	Number of buses allottted during the period from January, 1982 to January, 1983
1	Ambala	5
2	Chandigarh	16
3	Karnal	29
4	Jind	13
5	Kaithal	32
6	Sonepat	46
7	Yamunanagar	10
8	Gurgaon	35
9	Rohtak	19
10	Hissar	48
11	Rewari	19
12	Bhiwani	21
13	Sirsa	15

14	Faridabad	68
	Total	**376**

ANNEXURE II

Depot-wise number of buses plying as on 31.1.1983

Sr. No.	Name of depot	Number of buses plying
1	Ambala	187
2	Chandigarh	212
3	Karnal	228
4	Jind	178
5	Kaithal	193
6	Sonepat	189
7	Yamunanagar	182
8	Gurgaon	253
9	Rohtak	195
10	Hissar	239
11	Rewari	192
12	Bhiwani	188

13	Sirsa	147
14	Faridabad	155
	Total	**2738**

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने अपने लिखित जवाब में यह कहा है कि जनवरी, 1982 से जनवरी, 1983 की अवधि में अलाट की गयी बसों की कुल संख्या 376 है जिनमें से हिसार में 48, फरीदाबाद 68 और सिरसा में केवल 15 बसें अलाट की गयी है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन बसों को अलाट करने का क्या काइटेरिया है? सिरसा में इतनी थोड़ी बसें और फरीदाबाद में इतनी ज्यादा बसें अलाट करने के क्या कारण है?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर सर, बसिज अलाट करने के दो तरीके है। एक तरीका है पुरानी बसों की रिप्लेसमैंट। जो पुरानी बसें 6 लाख किलोमीटर तक चल चुकी है, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है और दूसरा तरीका यह है कि नई अलाटमैंट होने पर पुरानी बसें बदली जाती है और यह देख कर बदली जाती है कि उस इलाके की सड़कें बन गयी है या नहीं, और साथ ही नये रूट्स बगैरह का भी ध्यान रखा जाता है तब यह अलाटमैंट होती है। दूसरा माननीय सदस्य ने बसों की अलाटमैंट के काइटेरिया के बारे में पूछा और कहा कि फरीदाबाद में इतनी ज्यादा बसें कैसे अलाट कर दीं? फरीदाबाद एक नया डिपो बना

था इसलिए ज्यादा बसों की जरूरत थी। जो पुरानी बसें हो गयी थीं उनको चेंज ओवर किया था। गुड़गांव डिपों को सपलिट करके कुछ बसें वहां भेजी गयी थी। इसलिये डिपों के लैवल को दूसरे डिपोजके लैवल के बराबर लाने के लिये फरीदाबाद में 68 बसें अलाट की गयी है। हिसार में भी कुछ नये रूट्स चालू किये थे, इसलिये वहां पर ज्यादा बसों की जरूरत थी। दूसरी वि ोश बात हिसार के बारे में यह है कि राजस्थान रोड़वेज के पास भी कई रूट्स थे। लेनि उनके पास कुछ कम बसें थी। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि वे इतने रूट्स पर अपनी बसें चला लें, इसलिये इन रूट्स को चालू रखने के लिये हमने हिसार में और बसें दी।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने रिप्लाई में बताया कि हरियाणा के 14 डिपोज में 31.3.1983 तक कुल 2738 बसें सप्लाई की गयी। क्या वे बताने का कश्ट करेंगे कि इन बसों में से कितनी ऐसी बसें है जोकि चालू हालत में है?

कर्नल राव राम सिंहः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा रोड़वेज बसिज की यूटीलाईजे ान सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। एग्जैक्ट फिग्र्ज तो मैं नहीं दे सकता कि इस वक्त कितनी चालू हालत में है, क्योंकि अगर एक बस आज आफ रोड हो जाती है तो रिपेयर होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर वह आन रोड हो सकती है। इसलिए स्पीकर साहब, इस बात को तो आप स्वयं ही मानेंगे कि इन हालात में एग्जैक्ट फिगर्ज देना कठिन है लेकिन मैं यह फिगर्ज देना चाहता हूं कि हमारी बसिज की यूटीलाइजे ान

कितनी है। हरियाणा की बसिज की यूटीलाइजे न फलीट स्ट्रैंथ के हिसाब से 95 परसैंट आन रोड रही है। मद्रास 92 परसैंट, बंगाल की 63 परसैंट, गुजरात की 85 परसैंट, बम्बई की 86 परसैंट, पंजाब की 91 परसैंट, पटियाला 93 परसैंट आन रोड रही है। इन सब को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस वक्त हरियाणा रोडवेज टाप पर रही है।

श्री बीरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, ने जो 376 बसों को अलग अलग डिपो–वाइज डाटा बताया है, क्या उसको देखते हुए यह समझा जाए कि जनवरी 1982 से जनवरी, 1983 तक ये बसें नई खरीदी गई है?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर सर, इनका सोचना दुरूस्त है।

श्री हीरा नंद आर्यः मंत्री महोदय, ने बताया कि अलग–अलग डिपोज को जो बसें अलाट की गई है, उनकी संख्या 376 है। कुछ जगहों पर नई बसें भी भेजी गयी और कुछ जगहों पर रिप्लेसमैंट की गई। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि रिप्लेस कितनी की गयीं और किस–किस डिपों में की गयीं और कितनी नई बसें अलाट की गई? जिन पुरानी बसों की जगह पर नई रिप्लेस की गयीं, क्या वे पुरानी बसें सरकार द्वारा निर्धारित समय की अवधि को समाप्त कर चुकी थीं या नहीं?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर सर, मैं आनरेबल मैम्बर को जिलावार सारी पोजी ान बता देता हूं। अम्बाला में 6 बसें रिप्लेस की गयी और नई कोई नहीं। करनाल में 8 रिप्लैसमैंट और 21 नई, चंडीगढ में 10 रिप्लेसमैंट और 6 नई, जींद में 12 रिप्लेसमैंट ओर 1 नई, कैथल में 17 रिप्लेसमैंट, और 15 नई, सोनीपत में 5 रिप्लेसमैंट और 41 नई, यमुनानगर में 6 रिप्लैसमेंट और 4 नई, गुड़गांव में 7 रिप्लेसमैंट और 28 नई, रोहतक में 11 रिप्लेसमैंट और 8 नई, हिसार में 10 रिप्लैसमैंट और 38 नई, रिवाड़ी में 5 रिप्लेसमैंट और 14 नई, भिवानी में 6 रिप्लैसमैंट और 15 नई, सिरसा में 6 रिप्लैसमैंट और 9 नई और फरीदाबाद में 11 रिप्लेसमैंट और 57 नई बसें दी गई है। टोटल 119 रिप्लेस की गयीं और 257 नई बसें दी गई है, मतलब एडी ान की गई है।

श्रीमती बसंती देवीः स्पीकर साहब, बसिज में अमूमन यह लिखा होता है कि यहां पर बीड़ी सिग्रेट पीना मना है, दो या तीन बच्चे, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार होगी, पेट्रोल और मिट्टी का तेल ले जाना मना है, बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री से दस गुणा किराया लिया जाएगा, वगैरह–वगैरह। क्या इन बातों पर अमल भी होता है या केवल लिखने के लिए लिखी गई है?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने एडवर्टाइजमैंटस के बारे में कहा हैं। कई बसों पर लिखा हुआ है 'दो या तीन बच्चे', इस बात को इम्पलीमेंट करना तो रोडवेज का

काम नहीं है। हमने इसलिए लिखा है कि लोग इन बातों को फौलो करें क्योंकि ये बातें अच्छे कुनबे के लिये यूजफूल है। जहां तक सिगरेट पीने का सवाल है, कोई ड्राइवर या कंडक्टर कभी–कभी पी लेता होगा। मैंने बहन जी को कहा कि आप लिखकर दो तो वे कहने लगीं कि चलो जाने दो, कोई गरीब आदमी यू ही ससपैंड हो जाएगा।

श्री देवी दासः क्या मंत्री महोदय के नोटिस में है कि इतिहाद रोडवेज के दो ग्रुप है और वह दिल्ली से सोनीपत रूट पर चलते है। मैं जानना चाहता हूं कि उनकी कितनी बसें चलती है। एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि सारे हरियाणा में बसों का राश्ट्रीयकरण कर दिया गया है, तो फिर इतिहाद वालों की बसें कैसे चल रही है।

श्री अध्यक्षः इस सप्लीमेंटरी की मेन सवाल से कोई रैलेवैंसी नहीं है।

चौधरी धीर पाल सिंहः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बस को रिप्लेस करने का क्या काइटेरिया है? दूसरे हरियाणा रोड़वेज की बसों में क्या वि ोश खूबी है जो हमें देखने को मिलती है?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, जहां तक बस को रिप्लेस करने का सवाल है, वह मैं पहले बता चुका हूं कि जब कोई बस 6 लाख किलोमीटर चल लेती है तो उसको रिप्लेस कर

दिया जाता है। उससे पहले रिप्लेसमैंट तभी होती है अगर किसी बस का सीरियस एक्सीडेंट हो जाए और वह बिल्कुल खराब हो जाए।

चौधरी धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं आया। बसों में न तो भाी ो है न खीड़की है और न इंजन है, इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्षः चौधरी धीरपाल जी आप जो कह रहे है, वह सारा लिखा जा रहा है। आप यह बताएं कि बगैर इंजन के बस कैसे चल सकती है? (हंसी)

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, जब चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की सरकार थी, तब बसें बगैर इंजन के भागा करती थीं, अब तो बसें इंजन के साथ चल रही है। दूसरे इन्होंने कहा कि किसी बस के भाी ों नहीं, उसके बारे में यह हो सकता है कि जो विलेज रूट्स पर बसें चलती है, उनमें कोई एक आध बस ऐसी होगी जिसके भाी ों टूटे होंगे। अगर कोई पर्टिकुलर इंस्टास मेरे नोटिस में लाया जाता है तो मैं उसके बारे में देख लूंगा। हरियाणा रोडवेज की वर्क ाप डे एंड नाइट खुली रहती है और हर बस को जल्द से जल्द ठीक करने की कोि ा ा की जाती है।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, सिरसा से गंगा नगर का रूट खुलने के बाद गांवों के सारे रूट बंद कर दिए गए है, क्या यह सही है? दूसरा मेरा सवाल यह है कि सिरसा ही एक ऐसा

डिपो है जहां बसों की हालत सब से खराब है। क्या मंत्री महोदय उस डिपों को चैक करने या सिरसा डिपों की खुद देखने की तकलीफ करेंगे, अगर हो तो तारीख बताने का कश्ट करें कि किस दिन चैक करेंगें?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, जहां तक कोई बस रूट बंद करने की बात है, उस बारे में ये आज ही बता रहे है, पहले मेरे नोटिस में नहीं लाए। हरियाणा रोडवेज एक कमर्ि ायल आर्गेनाइजे ान है लेकिन उसके साथ साथ यह सो ाल सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इसलिए, केवल प्रोफिट बनाना ही आधार नहीं है बल्कि सो ाल सर्विस भी देते है। इस वक्त हरियाणा रोडवेज के आप्रे ान की कास्ट 2.80 रूपये पर किलोमीटर आती है। जहां तक विलेज रूटस का संबंध है, अगर वहां की बस डेढ़ रूपया पर किलोमीटर की कमाई भी देती है तब भी उसे चालू रखा जाता है लेकिन अगर किसी रूट पर डेढ रूपया से नीचे कमाई होती है तो उसको बंद करदिया जाता है। जहां तक सिरसा में विजिट करने कीबात है, भागी राम जी मेरे 6 साल से अच्छे दोस्त रहे है लेकिन इन्होंने मेरे को कभी नहीं बुलाया। अगर ये कभी बुलाने का कश्ट करेंगे तो मैं जरूर हाजिर हूंगा।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि जिस बस के भाी ो टूटे हुए होंगे, भाायद वह गांव को जाने वाली बस होगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गांव और भाहर में जाने वाली बसों मैं कोई अंतर है? गांव में जाने वाली

बस के भी ें टूटे होंगे, खिड़कियां टूटी होगी, सीटें उखड़ी होंगी। उनमें एक आदमी तो स्टेयरिंग पर बैठा होगा और एक आदमी गियर बाक्स पकड़े बैठा होगा? (विघ्न)

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, डा0 मंगल सैन जी स्टेटमैंट को टविस्ट करने में एक्सपर्ट है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। स्पीकर साहब, ये मुझे खुद मिले और कहा कि भाहरों में बसें बढ़िया होनी चाहिएं। (हंसी)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इनसे गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई थी, उसके बाद मैं इनको कभी नहीं मिला।

श्री अध्यक्षः यह बात तो मैं भी कह सकता हूं कि आप रोज मिलते है। (हंसी)

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः क्या मंत्री जी के नोटिस में यह बात है कि कई जगहों पर पचास प्रति ात से भी ज्यादा बसें बस स्टैंड के आगे पीछे रूकती है। क्या इसको बंद करवाएंगे?

कर्नल राव राम सिंहः आप किसी खास जगह का केस मेरे नोटिस में लाएं, उस जगह पर मैं एक इंस्पैक्टर को पोस्ट कर दूंगा ताकि वह चैक करें कि बसें बस स्टैंड के आगे पीछे तो नहीं रूकती।

श्री निहाल सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने डिपोज और सब डिपोज की लिस्ट दी है, इसमें से 12 जिलों में से दस जिलें ऐसे है जिन के जिला हैड क्वार्टर पर इनके डिपों बने हुए हैं लेकिन आपका और मेरा ये दो जिले ऐसे है जहां डिपों नहीं है। क्या वहां पर भी डिपों खोलने का विचार करेंगे? दूसरा सवाल यह है कि इन्होंने रिवाड़ी में सिर्फ 19 नई बसें दी है। इन्हें रिवाड़ी से क्या नाराजगी है, वहां 19 की बजाये 91 क्यों नहीं दी गई?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, डिपो खोलने का क्राइटेरिया यह है कि वह जगह सैंटर आफ कम्युनिके ान हो या डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर हो। जहां तक कुरूक्षेत्र का सवाल है, मेरा ख्याल है जब कैथल डिपो खोला गया था उस समय कुरूक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर नहीं बना था। यानी उस जिले में डिपों पहले बन गया था और कुरूक्षेत्र जिला बाद में बना था। मैं मानता हूं कि कुरूक्षेत्र एक अच्छी जगह है और हमारा धार्मिक स्थान भी है। वहां पर मेलों को केटर करने के लिए दो तीन बस स्टैंडों का प्रबंध किया जा रहा है। जहां तक नारनौल का सवाल है, नारनौल सब डिपों में इस वक्त 60–70 बसिज है। अगर सिचुए ान और डिमांड करती है तो उसे डिपार्टमैंट एग्जामिन करेगा। मैं समझता हूं कि कुरूक्षेत्र और नारनौल में डिपों बनाने के लिए मजबूत केस है। अगर जस्टीफाईड होगा तो जरूर बनाएंगे।

ठाकुर बहादुर सिंहः क्या मंत्री जी के नोटिस में यह बात है कि बस स्टैंडज पर पीने के पानी का प्रबंध नहीं है और वहां पर जो कमर्ि ायल दुकानें है वह पानी की बोतल तीन रूपए में देती है। कई जगहों पर नलके लगे हुए थे लेकिन उनको तोड़ दिया गया है। क्या इस बात की तरफ ध्यान दिया जाएगा?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, जहां तक पीने के पानी की बात है, इस बारे में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि गर्मियों के मौसम में हर बस स्टैंड पर हरियाणा रोडवेज डिपार्टमैंट की तरफ से एक प्याउ लगायी जाती है। इसके अलावा भाहरों के बस स्टैंडज पर म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा वाटर सप्लाई के टैप्स भी लगाये जाते है लेकिन गर्मी के मौसम में वह पानी गर्म हो जाता है इसलिए प्याउ लगायी जाती है ताकि लोग ठंडा पानी पी सकें। यदि माननीय सदस्य किसी खास जगह के बारे में बताएंगे कि फलां बस स्टैंड पर पीने के पानी की सुविधा नहीं है तो हम वहां पर स्पै ाल प्याउ लगावा देंगे क्योंकि प्यासे को पानी पिलाना धर्म का काम है। इसके अलावा जहां तक कमर्ि ायल भााप्स की बात है इस बारे में मेरे पास बहुत सी ि ाकायतें आई है कि बस स्टैंडज पर चाय और कोका–कोला वगैरह बहुत मंहगा दिया जाता है और हर बस स्टैंड पर जितनी भी चाय की दुकानें है वे लोगों से चाय और कोका–कोला वगैरह के बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते है। इस बारे में मैं यह बताना चाहताह हूं कि हरियाणा रोड़वेज ने यह फैसला किया है कि हर

बस–स्टैंड पर रोडवेज की तरफ से एक चाय वगैरह की दुकान खोली जायेगी जहां पर आम आदमी को चाय का प्लाला 40 पैसे में मिलेगा। (थम्पिंग)

Pay fo the employees of the National College Sirsa

***158. Shri Ram Bilas Sharma:** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the pay of some of the employees of the Government National College, Sirsa, has not been paid to them for the last so many moths; and

(b) if so, the reasons therefor togetherwith the action. If any, taken by the Government in the matter?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा):

(क) दो कर्मचारियों का वेतन दो मास के लिए रोका गया था, परन्तु अब उनके वेतन की अदायगी कर दी गई है।

(ख) एक लिपिक के विरूद्ध कुछ वितीय अनियमितताएं करने का आरोप था तथा दूसरा लिपिक तदर्थ आधार पर कार्य कर रहा था और छः मास के प चात् उसकी लगातार नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। पहले केस में जांच पूर्ण होने तक तथा दूसरे केस में स्वीकृति होने तक सरकार ने वेतन की अदायगी के आदे ा दे दिये है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने उस कर्मचारी का वेतन रोका था क्या उसको वेतन रोकने का अधिकार था? इसके साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस अधिकारी ने उस कर्मचारी का वेतन रोकने के बारे में हैडक्वार्टर को सूचना दी थीं?

श्री जगदी I नेहरा: स्पीकर साहब, उस बारे में हैडक्वार्टर पर कोई जानकारी नहीं दी गई। उस कालेज के प्रिंसिपल महोदय ने लोकल एडमिस्ट्रेटिव ग्राउडज पर उसका वेतन रोका था।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मंत्री जी सवाल के जवाब देने में बहुत कम्पीटैंट है इसलिए मैं इनसे एक सवाल जींद के बारे में पूछना चाहूंगा। क्या मंत्री जी की नालेज में यह बात है कि सर छोटू राम किसान कालेज, जींद के कर्मचारियों को 7–8 महीनें से तनख्वाह नहीं मिली है।

Mr. Speaker: This has no relevance with this question.

Rest House Built by Market Committees in the State

***164. Chaudhri Kulbir Singh Malik:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) the present number of rest house built by Market Committees for the farmers in the State;

(b) the details of facilities being provided to the farmers in the said rest house;

(c) Market Committee-wise daily charges for staying in such rest houses prescribed for farmers and other persons;

(d) the number of persons/farmers who stayed in each of the rest house during the period from 1.1.1982 to 31.1.1983.

(e) the total amount earned by each Market Committee from their rest houses during the period referred to in part (d) above;

(f) the number of rest houses, out of those referred to in part (a) abvove, which are air-conditioned toghethewith the charges per room/suite per day thereof;

(g) whether any beer bar is being run at Dadri rest house; and

(h) the total amount of expenditure incurred on furniture and other items of furnishing for Dadri rest house?

Agriculture Minister (Chaudhri Surender Singh): From (a) to (h), A statement is laid onthe Table of the House.

STATEMENT

Statement regarding Rest House built by Market Committees in the State.

(a) 34 Rest Houses have been built by the Board/Market Committees for the farmers in the State.

(b) The facilities provided to farmers in the rest houses are:-

1. Cots and Beds.

2. Drinking water.

3. Light.

4. Toilet facilities.

5. Fans.

6. Utensils etc.

In addition to these facilities, some of the rest houses also provide room coolers, air conditioner, geysers, radios, refrigerator etc.

(c) Reply is given in Column 3 of Annexure-I.

(d) Reply is given in Column 4 of the attached Annexure-I.

(e) Reply is given in Column 5 of the attached Annexure-I.

(f) Reply is given in Annexure-II.

(g) No.

(h) Rs. 88,212.00

ANNEXURE I

Statement of showing the number of Rest Houses maintained by the Market Committees in Haryana alongwith daily charges for stay, the number of persons/farmers stayed and the total amount earned by each Market Committee

Sr. No.	Name of the Market Committee	Market Commiittee-wise daily charges for staying in such rest houses prescribed for farmers and other persons (part-c) (Non-airconditioned) Farmers Government other Servants	Number of persons/farmers who stayed in each of the rest houses during 1-1-82 to 31-1-83 (Part-d)	Total amount earned by each Market Committee from their rest houses during the period referred ot in	Remarks

						part (d) (Part-e)	
Distt. Ambala							
1	Sadhaura	1/-	5/-	10/-	60	195/-	
Distt. Bhiwani							
2	Bhiwani	0.50 /-	5/-	5/-	28	172/-	
3	Ch. Dadri	Free	5/-	25/-	367	7240/-	
4	Tosham	-do-	25/-	25/-	7	125/-	
5	Satnali	2/-	2/-	2/-	54	138/-	
Distt. Faridabad							
6	Ballabgarh	Free	4/-	4/-	-	-	This rest house is being furnishe

							d.
7	Gurgaon	Free	4/-	4/-	218	92/-	
8	Pataudi	Free	5/-	5/-	52	523/-	
Distt. Hissar							
9	Hissar	2/-	4/-	20/-	138	1232/-	
10	Hansi	0.50 /-	2/-	2/-	83	275/-	
11	Adampur	0.50 /-	2/-	2/-	90	232/-	
12	Jakhal	0.50 /-	2/-	4/-	-	218/-	
13	Tohana	0.50 /-	2/-	5/-	65	320.50/-	
14	Bhattu Kalan	2/-	2/-	2/-	29	82/-	

Distt. Jind							
15	Jind	Free	2/-	4/-	192	848/-	
16	Jullana	Free	2/-	4/-	40	376/-	
17	Safidon	Free	20/-	20/-	1	20/-	
18	Kalayat	Free	2/-	2/-	37	164/-	
19	Narwana	0.50	2/-	10/-	225	885/-	
Distt. Karnal							
20	Karnal	0.50	4/-	8/-	31	486/-	
21	Panipat	1/-	2/-	10/-	480	4437/-	
Distt. Kurukshetra							
22	Shahbad	1/-	2/-	4/-	26	396/-	
23	Dhand	Free	2/-	4/-	140	283/-	

24	Kaithal	0.50	2/-	10/-	52	636/-	
25	Cheeka	Free	-	4/-	86	666/-	
26	Ladwa	0.50	2/-	4/-	148	473/-	
Distt. Mohindergarh							
27	Narnaul	Free	3/-	3/-	73	444/-	
28	Rewari	Free	2/-	2/-	54	108/-	
29	Kanina	Free	2/-	2/-	18	32/-	
Distt. Rohtak							
30	Rohtak	Free	2/-	4/-	47	131/-	
Distt. Sirsa							
31	Sirsa	2/-	2/-	2/-	84	748/-	
32	Ellendabad	0.50	2/-	2/-	46	376/-	

33	Dabwali	0.50	2/-	2/-	-	-	
34	Kalanwali	0.50	2/-	2/-	-	-	
	Total:				2968	22,353/-	

Note- The daily charges for Air Conditioned suits are given separately in part (f) of the reply.

ANNEXURE II

Statement showing the number of rest houses out of those referred to in part (a) of the question which are air-conditioned togetherwith the charges per room/suit per day thereof.

Sr. No.	Name of Rest House	Charges		
1	Dadri	(i) Others Rs. 100/- and Rs.75/- (ii) Officers on duty Rs. 10/- for Ist and 2nd floor respectively		
2	Tosham	(i) Others	Rs. 75/-	
		(ii) Officials	Rs. 10/-	
3	Adampur		**Winter**	**Summer**
		(i) Others	Rs. 25/-	Rs. 30/-
		(ii) Officials	Rs. 20/-	Rs. 22/-
4	Pataudi	(i) Others	Rs. 10/-	
		(ii) Officials	Rs. 5/-	
5	Hissar		**Winter**	**Summer**
		(i) Growers	Rs. 2/-	Rs. 6/-
		(ii)	Rs. 4/-	Rs. 8/-

		Haryana/Central Govt. employees/ Semi Govt. Board etc.		
		(iii) Private, Coop. Bank & other Organisations	Rs. 20/-	Rs. 25/-

चौधरी कुलबीर सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पांच एयर कंडी ानज रैस्ट हाउसिज मार्किट कमेटी द्वारा बनाए गए है, क्या ये प्रोफिट कमाने के लिए बनाए गए है या किसानों को ठहरने की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाए गए है क्योंकि इन रैस्ट हाउसिज में 100 रूपये डेली रैट चार्च दिखाया गया है?

चौधरी सुरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, दादरी, तो ाम, आदमपुर, पटौदी और हिसार में मार्किट कमेटी द्वारा पांच एयर कंडी ानड रैस्ट हाउसिजज बनाए गए है जिनमें किसानों के ठहरने के लिए भी सुविधा है। इन एयर कंडि ानड रैस्ट हाउसिजज में किसानों से अलग रेट चार्ज किया जाता है और आफिसर्ज तथा दूसरे प्राईवेट लोगों से अलग रेट चार्ज किया जाता है। स्पीकर साहब, हमने यह इंस्ट्रक ान जारी की हुई है कि सारे प्रांत में मार्किट कमेटीयों द्वारा जितने भी एयर कंडी ांड

रैस्ट हाउसिज बनाए हुए है उनमें किसानों के लिए दो रूपए और चार रूपए से ज्यादा रूम रैंट न हो।

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, मेन सवाल में यह पूछा गया है कि 1–1–1982 से 31–1–1983 तक मार्किट कमेटियों द्वारा बनाए गए रैस्ट हाउसिज में कितने लोग ठहरे है, और मंत्री जी ने उसका जवाब दिया है कि सारे रैस्ट हाउसिज में 2968 टोटल आदमी ठहरे है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इनमें से गैर–किसान कितने है और किसान कितने है?

चौधरी सुरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, हरियाणा के अंदर मार्किट कमेटियों द्वारा जितने भी रैस्ट हाउसिज बनाए हुए है उनमें 1–1–1982 से 31–1–1983 तक कुल 2968 आदमी ठहरे थे, इनमें ज्यादातर किसान ही ठहरे थे। स्पीकर साहब, हमने दादरी के रैस्ट हाउस में रैंट के चार्जिज कुछ ज्यादा रखे हुए है। वह इसलिए रखें हुए है क्योंकि वहां पर सीमेंट फैक्टरी है जिसको गवर्नमैंट आफ इंडिया चला रही है। वहां पर ज्यादातर आफिसर्ज ही ठहरते है इसलिए उनसे वही चार्जिज लिए जाते है जो प्राईवेट होटलों में चार्ज किए जाते है। इसके अलावा मैं हाउस की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि तमाम हरियाणा प्रांत में एयर कंडि ान्ड रैस्ट हाउसिज को छोड़ कर बाकी सारे रैस्ट हाउसिज में किसानों को फ्री आफ कास्ट ठहरने का प्रबंध करने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

डा0 भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, सवाल के जवाब में मंत्री जी ने रैस्ट हाउसिज की आमदनी के बारे में बताया हैं। किसी रैस्ट हाउस की सालाना आमदनी 32 रूपए है, किसी की 92 रूपए है और किसी की 313 रूपए है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन जगहों पर सालाना आमदन बहुत थोड़ी है क्या उन जगहों पर रैस्ट हाउसिज बनाते समय मार्किट कमेटियों ने यह नहीं देखा कि यहां पर एनुअल आकुपैसी कितनी होगी? मार्किट कमेटियों ने उन रैस्ट हाउसिज को बनाने पर करोड़ों रूपया खर्च किया है और लाखों रूपए उनकी मैंटीनैंस पर खर्च होते है, क्या मार्किट कमेटियों ने उन जगहों पर रैस्ट हाउसिज बनाने की समझदारी की है?

चौधरी सुरेंद्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंडियों में किसानों के ठहरने के लिए रैस्ट हाउसिज बनाना बहुत ही जरूरी था। किसानों को फैसिलिटिज देने के बारे में जब भी सदन में कोई बात आती है तो सारे सदस्य इस बात की पूरी कोि ा ा करते है कि किसानों को भी दूसरी क्लासिज के लोगों के बराबर पूरी फैसिलिटिज दी जाएं। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हमने कुछ रैस्ट हाउसिज में किसानों के लिए खाने का प्रबंध किया हुआ है। दादरी के रैस्ट हाउस को रैस्तरां के तौर पर भाुरू किया है क्योंकि वहां पर दूसरे प्रांतों से आकर टूरिस्ट ठहरते है और औसतन आमदन सात और आठ हजार होती

है। इस रैस्ट हाउस में किसानों को सबसिडाइज्ड रेट पर डाइट दी जाती है।

चौधरी हुक्म सिंह फौगाटः स्पीकर साहब, दादरी रैस्ट हाउस में किसानों के ठहरने की पूरी सुविधा है लेकिन जब किसान अपना अनाज बेचने के लिये मंडी में आते है तो उनके बैल या ऊंट बांधने का वहां कोई स्थान नहीं है। मैं मंत्री मजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या दादरी को मंडी में किसानों के बैल और ऊंटों को बांधने के लिए कोई स्थान बनाया जाएगा?

श्री अध्यक्षः यह सैपरेट सवाल है।

श्री निहाल सिंहः स्पीकर साहब, सारे हरियाणा प्रांत में पांच एयर कंडी ांड रैस्ट हाउसजि है जो मार्किट कमेटियों ने बनाए हुए है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन रैस्ट हाउसिज में किसानों को ठहरने के लिए फैसिलिटिज दी हुई है या नहीं, क्योंकि हरियाणा के अंदर सारे रैस्ट हाउसिज एयर कंडी ांड नहीं है?

चौधरी सुरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा में पांच रैस्ट हाउसिज एयर कंडी ांड बनाए हुए है और इन पांच रैस्ट हाउसिज में सारे कमरें एयर कंडी ांड नहीं है, कुछ कमरे एयर कंडी ांड है। किसानों के लिए कुछ कमरे ऐसे बनाए हुए है जिनका रैट दो रूपए और चार रूपये हैं। इसके अलावा किसान

के ठहरने के लिए वहां पर दूसरे रैस्ट हाउसिज के मुताबिक फ्री रहने का भी प्रबंध किया हुआ है।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, इन पांच एयर कंडी ांड रैस्ट हाउसिज में कमरों का किराया 20, 25 और 100 रूपये तक बताया गया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या ये वही कमरे है जिनमें किसान ठहरते है?

चौधरी सुरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, अब हम यह इंस्ट्रक ांज इ ू कर रहे है कि इन पांचों रैस्ट हाउसिज में एयर कंडि ांड कमरों को छोड़कर बाकी कमरों में किसानों के ठहरने का प्रबंध फ्री आफ कौस्ट किया जाए।

श्रीमती चंद्रावतीः स्पीकर साहब, किसान लोग जब मंडियों में अपना अनाज वगैरह बेचने के लिए आते है, उस समय वे कार में तो बैठ कर नहीं आते, वे अपने ट्रक या ट्रैक्टर में अपना अनाज वगैरह लाते है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या किसानों के लिए मंडियों में उनकी बैलगाड़ी, ट्रक और ट्रैक्टर वगैरह को खड़ा करने के लिए, उन रैस्ट हाउसिज के पास कोई जगह बनाने के बारे में सरकार विचार कर रही है?

चौधरी सुरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो किसान ट्रक या ट्रैक्टरों में अपना अनाज वगैरह बेचने के लिए मंडियों में आते है वे आमतौर पर भााम को अपने घर चले जाते है, उनको अपना ट्रक या ट्रैक्टर मंडी में खड़ा करने की जरूरत महसूस ही नहीं

होती। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि दादरी और दूसरी मंडियों में ट्रक और ट्रैक्टर वगैरह खड़ा करने के लिए पार्किंग की जगह होती है।

श्री बीरेंद्र सिंहः मंत्री जी ने बताया कि बड़े सुंदर रैस्ट हाउसिज इन्होंने बना रखें है, क्या उनके आगे यह लिखा देंगे कि यह रैस्ट हाउस किसानों के ठहरने के लिए है, क्योंकि रैस्ट हाउस इतने बढ़िया बने हुए है कि उनमें आम किसान घुसते हुए भी डरता है?

चौधरी सुरेंद्र सिंहः वीरेंद्र सिंह जी का बड़ा अच्छा सुझाव है। हमने यह हिदायतें जारी कर दी कि तमाम रैस्ट हाउसिज के सामनै लिख दिया जाए कि यहां पर किसान ठहर सकते है। हमने यह भी हिदायतें जारी की है कि बाहर यह भी लिख दिया जाए कि किसानों को सवा तीन या तीन रूपए में खाना दिया जा रहा है और चाय का एक कप 45 पैसें में मिलेगा।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Supply of Kerosene Oil in the Rural Areas

***177. Smt. Basanti Devi:** Will the Minister for Food & Supplies be pleased to state-

(a) the district-wise names of the agencies/depots, if any, from which the Kerosene oil is supplied to the rural areas in the State;

(b) the district-wise quantity of Kerosene oil supplied by the said agencies/depots during 1981-82, separately; and

(c) whether it is a fact that most of the agencies/depots, mentioned in part (a) above, are owned by the proprietors of petrol pumps; if so the steps, if any taken or proposed to be taken to check adulteration of petrol with Kerosene oil by such agencies/depots?

Chief Minster (Chaudhri Bhajan Lal):

(a) There are no agencies/depots through which Kerosene oil is supplied exclusively to rural areas. However, district wise list of names of the agencies/depots from which Kerosene oil is supplied is laid on the Table of the House as Annexure I.

(b) Information is laid on the Table of the House as Annexure II-

(c) No.

ANNEXURE I

List of Names of Wholesale K. Oil Agencies/Depots

Ambala Circle

Sr. No.	Name of the wholesale K. Oil Agency
1	M/s Verma Oil House, Ambala City.
2	M/s Aggarwal Oil Co., Ambala City.
3	M/s Jagtar Singh & Co. Ambala City.
4	M/s Paul & Co., Ambala Cantt.
5	M/s Sharma Oil House, Ambala Cantt.
6	M/s Sharma Oil Co., Ambala Cantt.
7	M/s Star Oil Traders, Ambala Cantt.
8	M/s Ambala Filling Stattion, Ambala Cantt.
9	M/s Parkash Oil Store, Ambala Cantt.
10	M/s Haryana Oil Traders, Panchkula.
11	M/s Verma Oil House, Ambala Cantt.
12	M/s Gainda Mal Hem Raj, Kalka.
13	M/s Wazir Chand Brij Lal, Kalka.
14	M/s Joginder Singh & Sons, Ambala Cantt.
15	M/s Jagdamba Oil House, Jagadhri.
16	M/s Gupta Oil Store, Jagadhri.
17	M/s Nanak Chand Banarsi Dass, Yamuna Nagar.

18	M/s Dayal Oil Store, Yamuna Nagar
19	M/s B.K. Oil Agency, Yamuna Nagar.
20	M/s National Corporation, Sadhaura.
Bhiwani Circle	
1	M/s Coop. Consumers Stores, Bhiwani.
2	M/s Gupta Bros. Bhiwani.
3	M/s Ram Kumar & Co., Bhiwani
4	M/s Anand Bros. Bhiwani
5	M/s Mital Auto Service, Charkhi-Dadri.
6	M/s Girdhari Lal Ram Sarup,Charkhi-Dadri.
7	M/s Ganeshi Lal Prabhu Dayal, Charkhi-Dadri.
8	M/s Sanaik Randhi Singh, -do-
9	M/s Kansi Ram Goel & Sons, Siwani.
10	M/s Deepak Filling Station, Siwani.
Faridabad Circle	
1	M/s Auto Supply Co., Faridabad
2	M/s Singla Brothers, Palwal.
3	M/s Surinder Oil Co., Faridabad.
4	M/s Keshar Motors, Faridabad.

5	M/s Tara Chand Saluja & Sons, Faridabad
6	M/s Vijay Oil Co., Faridabad.
7	M/s Chaliya Oil Co., Faridabad
8	M/s Jeet Oil Co., Faridabad
Gurgaon Circle	
1	M/s Anand Parkash & Co. Gurgaon.
2	M/s Rajesh Oil Corporation, -do-
3	M/s Kirpa Ram Jagan Nath, Haily Mandi.
4	M/s Ghasi Ram Panna Lal, Gurgaon.
5	M/s Ashish Service Centre, Barkhaji (F.P. Jhirka).
Hissar Circle	
1	M/s Haryana Petroleum Store, Hissar.
2	M/s Onkar Mal Rattan Lal Mandi Adampur.
3	M/s Banwari Lal Durga Parshad, Hissar.
4	M/s Hav. Amrit Singh, Hissar.
5	M/s Hissar Filling Service Station, Hissar.
6	M/s Kailash Chand Raj Kumar, Hansi.
7	M/s Gian Petrol Supply Co., Hansi.
8	M/s Amar Singh Sham Sunder Fatehabad.

9	M/s Kushi Ram Parma Nand, Fatehabad.
10	M/s Ashok Oil Co., Ratia.
11	M/s Vijay Kumar Ashok Kumar, Hansput (Ratia).
12	M/s Des Raj Prem Paul Modi Ratia
13	M/s Jagan Nath Bansal, Tohana.
14	M/s Chaudhry Service Station, Tohana.
15	M/s Dharam Chand Sant Lal, Tohana.
16	M/s Kishan Lal Lakhi Ram, Mandi Adampur.
17	M/s Manohar Lal Shiv Kumar, Uklana.
Jind Circle	
1	M/s Amrit Singh Chander Bhan, Jind.
2	M/s Jitendra Oil Co., Jind.
3	M/s Charanji Lal & Sons, Narwana.
4	M/s Goel Trading Co. Julana.
5	M/s Hira Oil Co., Pilukhera.
6	M/s Moti Ram Dhan, Safidon.
7	M/s Shadi Ram Bhagwan Dass, Narwana.
8	M/s Sumer Chand Mohinder Kumar.
Karnal Circle	

1	M/s New Karnal Trading Co., Karnal
2	M/s Nawal Kishore Oil Co., Karnal
3	M/s Sushil Kumar Ashok Kumar, Karnal.
4	M/s Chuhan Traders, Karnal.
5	M/s Sita Ram Kushal Chand, Panipat.
6	M/s Lakshri mal Satish Chander, Panipat.
7	M/s Malik Lal Chand, Panipat.
8	M/s Lajpat Rai & Sons, Assandh.
9	M/s Matu Ram Puran Chand, Samalkha.
10	M/s Jai Jawan Oil Co., Karnal
11	M/s Bharat Oil Traders, Karnal
12	M/s Inder Singh Sulekh Chand, Karnal.
13	M/s Jai Hindustan Oil Co., Karnal.
14	M/s Hari Chand Roshan Lal, Panipat.
15	M/s National Trading Co. Panipat.
Kaithal Circle	
1	M/s Tara Chand Oudh Behari, Kaithal
2	M/s Banarsi Dass & Sons, Kaithal
3	M/s Kishan Oil Company, Kaithal

4	M/s Sita Ram Kushal Chand, Kaithal
5	Madhia Oil Company, Pehowa
6	M/s Rajiv Oil Traders, Pehowa
7	M/s Manchanda Oil Company, Pehowa
8	M/s Neel Kanth & Sons, Pehowa
9	M/s Aruna Filling Station, Kaithal
10	M/s Monga Filling Station, Pundri
Kurukshetra Circle	
1	M/s Kurukshetra Oil Traders, Kurukshetra
2	M/s Sarswati Traders, Kuruksherta
3	M/s Neel Kanth & Sons, Pipli
4	M/s Haryana Filling Station, Ismailabad
5	M/s Surinder nath Sarwan Kumar, Sahabad
6	M/s Prem Nath Om Parkash, Shahbad
7	M/s Surinder Nath Sarwan Kumar, Ladwa
8	M/s Amir Chand Ram Lubhaya, Sahabad
Narnaul Circle	
1	M/s Bharat Oil Store, Narnual
2	M/s Shiv Oil Store, Narnual

3	M/s Haryana Oil Traders, Rewari
4	M/s Yadav Oil Store, Rewari
5	M/s Hemand Oil Company, Rewari
6	M/s Gori Shanker Jagdish Parshad, Rewari
7	M/s Bhawani Sahai Bishamber Dayal, Rewari
8	M/s Dhanna Mal Sumer Chand, Rewari
9	M/s Girdhari Lal Ram Sarup, Mahendergarh
Rohtak Circle	
1	M/s Kapoor Chand Fateh Chand, Rohtak
2	M/s Shadi Ram Udami Ram, Rohtak
3	M/s Vijesh Oil Co., Rohtak
4	M/s Perma Nand Nirankar Dev, Rohtak
5	M/s Parkash Dev & Bros., Rothak
6	M/s Rohtak Oil Co., Rohtak
7	M/s Kishan Oil Co., Badli
8	M/s Haryana Sales Corp. Jhajjar
9	M/s Suresh Oil Co., Sampla
10	M/s Balbir Singh Pehlad Singh, Bahadurgarh
11	M/s Dhingra Automobile, Kalanaur

12	M/s Shiv Oil Com., Jhajjar.
13	M/s Bansal Petroleum Products, Rohtak.
14	M/s Naresh Oil Co., Rohtak
Sonepat Circle	
1	M/s Desh Arpan Oil Agency, Sonepat.
2	M/s Batra Oil Co., Sonepat.
3	M/s Rup Oil Co., Sonepat.
4	M/s Om Service Station, Sonepat
5	M/s Rup oil Co., Bahalgarh.
6	M/s Haryana Agro Service, Ganaur.
7	M/s Ram Sarup Tara Chand, Gohana.
8	M/s Chandan Lal Paras Ram, Gohana.
9	M/s Ashoka Oil Co., Sonepat
10	M/s Verma Oil House, Ambala City.
Sirsa Circle	
1	M/s Mehta Brothers, Rania.
2	M/s Ram Lal Radha Krishan, Sirsa.
3	M/s Saink Balraj & Bros., Sirsa
4	M/s Udmi Ram Pirthi Chand, Sirsa

5	M/s Ratti Ram Murli Dhar, Sirsa.
6	M/s Ram Sarup Bansal & Sons, Sirsa.
7	M/s Suraj Bhan Hazari Lal, Ellenabad.
8	M/s Arjan Dass Banarsi Dass, Dabwali.
9	M/s Hans Raj Sudarshan Kumar, Dabwali.
10	M/s Kansi Ram Gurdita Ram, Dabwali.
11	M/s Gupta Motor Oil Co. –do-
12	M/s Bal Chand Siri Ram, Kalanwali.
13	M/s Bhagwat Rai Darshan Kumar, Kalanwali.
14	M/s Sukhija Brothers, Sirsa.

ANNEXURE II

Circlewise quantity of Kerosnes Oil supplied by the Agencies/depots during 1981-82 in the rural areas

Sr. No.	Name of the circle	Quantity supplied in Kilo liters
1	Ambala	5052
2	Bhiwani	3220
3	Faridabad	803
4	Gurgaon	2396

5	Hissar	3120
6	Jind	2662
7	Kaithal	3245
8	Karnal	4543
9	Kurkushetra	2593
10	Narnaul	2784
11	Rohtak	5225
12	Sirsa	2415
13	Sonepat	1760
	Total:	**39818**

Payments of salary through treasury to private college teachers

***176. Dr. Bhim Singh Dahiya:** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to make payment of salary to the teachers of private colleges through treasury in the State; if so, the time by which the said proposal is likely to materialize?

Minister of State for Education(Shri Jagdish Nehra): No. The question does not arise.

Construction of Bridge on the Barwala Branch Canal

***194. Shri Inder Singh Nain:** Will the Minister of State for Public Works (B&R) be pleased to state the progress, if any, made in the construction of the bridge over Barwala Branch Canal on Jind Barwala Road togetherwith the time by which it is likely to be completed?

लोक निर्माण राज्य मंत्री (चौधरी गोवर्धन दास चौहान): पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है और Piers तथा Abutments पर Bed Plates तक कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जैसे ही सिंचाई विभाग नहर को रोक सकेगा, स्लैब ढालने इत्यादि का भोश कार्य पूरा किया जा सकेगा।

Export by Agro-Industries Corporation

***186. Prof. Sampat Singh, Chaudhri Om Parkash:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether any export of goods was made by the Haryana Agro-Industries Corporation, on credit basis, during the year 1980-81; if so, the total value of such goods togetherwith the names of the countries and firms to whom such export was made; and

(b) whether any amount is presently outstanding agaisnt any of the countries and firms, as referred to in part (a) above; if so, details thereof

Agriculture Minister (Chaudhri Surender Singh):

(a) Yes. During the year 1980-81 (July, 1980 to June, 1981 being the financial year of the Corporation) a consignment valuing Rs. 15,153.60 was exported to M/s Brit Afri Ltd. London.

(b) Yes. The amount referred to in part (a) above is still outstanding. It became due on the 5th May, 1981.

Construction of Mini-Secretaria at Rohtak

***205. Chaudhri Om Parkash:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to constuct Mini-Secretariat Building at Rohtak; if so, the proposed location thereof togetherwith the time by which the said building is likely to be completed?

Revenue Minister (Chaudhri Phool Chand): Yes, Sir. The matter is under the consideration of Government. It is not possible at this stage to indicate the time by which the construction will be taken up.

Authoriese Homeopathic Dispensaries at Chandigarh

***320. Chaudhri Bhagamal:** Will the Minister for Healthbe pleased to state-

(a) whether the State Government employees are authorised to receive medical treatment in any of the Government Homeopathic Dispensaries located at Chandigarh; is fo, the names of such dispensaries; and

(b) whether the State Government employees can claim reimbursement of the cost of medicines prescribed by the dispensaries, referred to in part (a) above?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) नहीं।

(ख) नहीं।

Naggal Lift Irrigation Scheme

***308. Shri Nirmal Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the Naggal Lift Irrigation Scheme of Naggal constituency has been completed according to the original plan; and

(b) if reply to part (a) above is in the negative the time by which the said scheme is likely to be completed togetherwith the details of the new areas likely to be covered by it after its completion?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला):

(क) और (ख) नग्गल चुनाव क्षेत्र की नग्गल उठान सिंचाई योजना के पहले चरण का कार्य निर्धारित प्लान के अनुसार बन कर समाप्त हो चुका है। नग्गल उठान सिंचाई योजना के दूसरे चरण, जिसकी 1982 में स्वीकृति हुई थी, का कार्य जुलाई,

1984 में बन कर समाप्त हो जायेगा। जिन गांवो ंको नग्गल लिफ्ट इरिगे ान स्कीम दूसरा चरण से लााि पहुंचेगा उनकी सूची सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूची

क0 संख्या	गांव का नाम
1	ि ाधा वाला
2	निजामपुर
3	भोरगढ़
4	घेल
5	धुरक्ड़ा
6	देवीनगर
7	अनकपुर
8	डंगडेहरी
9	मुनकपुर
10	सुलतानपुर
11	लोहगढ़

12	सादोपुर
13	मंढौर
14	खतौली
15	दलीपगढ
16	रामगढ
17	भारीफपुर
18	बोह
19	बुबियाल
20	टुन्डली, टुन्डला
21	कलारहेड़ी
22	जनेतपुर
23	गरमाला
24	पनजोखरा
25	धन्कौरा
26	बरनाला

27	पट्टी अचरजा
28	पट्टी कलालां
29	पट्टी रांगरा
30	पट्टी भोखां
31	पट्टी जटां
32	खुरमपुर माजरी
33	काकरू

अतारांकित प्र न एंव उत्तर

53. Chaudhri Kulbir Singh Malik: Will the Minister of State for Public Works (B&R) be pleased to state.

(a) whether any road is being constucted to connect village Samar Gopalpur, district Rohtak with Jind-Rohtak road; if so, the lenght thereof;

(b) whether there is any link road from Bhagwatipur to Jind-Rohtak road; and

(c) if so, whether the road under construction mentioned in part (a) above is proposed to be diverted and connected through Bhagwatipur?

लोक निर्माण राज्य मंत्री (चौधरी गोवर्धन दास चौहान):

(क) समर गोपालपुर तथा जींद रोहतक को कि0मी0 110.10 पर मिलाती हुई एक 2.40 कि0मी0 लम्बी सड़क पहले ही है। इन दो स्थानों को कि0मी0 115 पर मार्फत भगवतीपुर मिलाने के लिए एक दूसरी 5.20 कि0मी0 लम्बी सड़क मंजूर की जा चुकी है।

(ख) हां।

(ग) जैसा कि बताया जा चुका है, पैरा (क) में वर्णित दूसरी लिंक सड़क भगवतीपुर से गुजरेगी।

Number of Hospitals, Dispensaries and P.H.C.s' in District Ambala

49. Chaudhri Bhag Mal: Will the Minister for Health be pleased to state the number of Hospitals, Dispensaries and P.H.C.s' alongwith the names of places of their location in Ambala district as on 28-2-1983?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्ना देवी):

हस्पतालः 8	
1	अम्बाला भाहर
2	अम्बाला छावनी
3	यमुनानगर

4	नारायणगढ़
5	जगाधरी
6	जगाधरी, ईः एसः आईः
7	कालका
8	छछरौली
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रः 8	
1	सढौरा
2	चोड़मस्तपुर
3	मुस्तफाबाद
4	बिलासपुर
5	रायपुर रानी
6	पिंजौर
7	खिजराबाद
8	मुलाना
औशद्यालयः 27	

1	महिला औशद्यालय, सढौरा।
2	भाहरी औशद्यालय, बलदेव नगर, अम्बाला भाहर।
3	ग्रामीण औशद्यालय, भाहजादपुर।
4	ग्रामीण औशद्यालय, कोट।
5	ग्रामीण औशद्यालय, पंचकूला।
6	ग्रामीण औशद्यालय, नूरपुर।
7	ग्रामीण औशद्यालय, मोरनी।
8	ग्रामीण औशद्यालय, कलानौर।
9	ग्रामीण औशद्यालय, बराड़ा।
10	ग्रामीण औशद्यालय, कलेसर।
11	ग्रामीण औशद्यालय, नाहरपुर।
12	ग्रामीण औशद्यालय, भााहपुर।
13	भाहरी सम्पदा औशद्यालय, सैक्टर–8, पंचकुला।
14	एम0 एल0 ए0 होस्टल औशद्यालय, चंडीगढ़
15	ईः एसः आईः औशद्यालय, अम्बाला भाहर।

16	ई: एस: आई: औशद्यालय, अम्बाला छावनी।
17	ई: एस: आई: औशद्यालय, जगाधरी 1 तथा 2
18	ई: एस: आई: औशद्यालय, यमुनानगर 3 से 6
19	ई: एस: आई: औशद्यालय, धूलकोट।
20	ई: एस: आई: औशद्यालय, एच: एम: टी: पिंजौर।
21	ई: एस: आई: औशद्यालय, कालका।
22	नहरी औशद्यालय, दादूपुर।
23	नहरी औशद्यालय, ताजेवाला।

Residential Quarters for the Chandigarh Dispensary Staff

50. Chaudhri Bhag Mal: Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) the categorywise number of residential quarters for staff as on 28-2-1983 at Chhachhrauli dispensary;

(b) whether it is a fact that the said quarters have been declared unfit for residence: and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new quarters in

place of the old ones, if os, the time by which it is likely to be done?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) एक चिकित्सा अधिकारी एक औशद्यकारक, एक नर्स, दाई और दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, नए रिहाय ाी भवनों का निर्माण जारी औपचारिकताएं पूर्ण होने तथा धन उपलब्ध होते ही भाुरू किया जाएगा।

Bifurcation of Naraingarh Block

51. Chaudhri Bhag Mal: Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state-

(a) the number of B.D.Os in Ambala district as on 28-2-1983 alongwith the names fo the places of their Headquarters:

(b) the date of posting of each of the said B.D.Os at their present headquarters; and

(c) whether there is any proposal to bifurcate the Naraingarh Block to create a new block with Headquarter at Sadhaura?

विकास मंत्री (श्रीमती भाारदा रानी कंवर):

(क) तथा (ख) अम्बाला जिला में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के आठ पद है बाकी सूचना निम्न प्रकार है:—

क्रमांक	खण्ड का नाम	मुख्यालय	नियुक्ति की तिथि	नाम सहित सर्व श्री
1	अम्बाला	अम्बाला	6.9.82	जरनैल सिंह
2	बराड़ा	बराड़ा	24.6.82	राजपाल
3	पिंजौर	पिंजौर	9.8.82	कुलदीप सिंह
4	जगाधरी	जगाधरी	16.8.82	पंचम सिंह
5	छछरौली	छछरौली	19.8.82	राजे ावर दयाल
6	बिलासपुर	बिलासपुर	17.11.82	कर्ण सिंह
7	नारायणगढ़	नारायणगढ़	22.7.78	भोरजंग मल्हन
8	रायपुर रानी	रायपुर रानी	26.8.82	औमप्रका ा कादयान

(ग) मामला अभी विचाराधीन है:

Police Station in Ambala District

52. Chaudhri Bhag Mal: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the number of Police Stations existing at present in Ambala district togetherwith their head-quarters;

(b) the date of construction of the buildings of each of the said Police Station:

(c) whether any of the buildings, out of those referred to in part (b) above have been declared unfit for use; if so, the names thereof togetherwith the date/dates on which the same were declared as such; and

(d) if reply to part (c) is in the affirmative, whether the Government proposes to construct new buildings in replacement of the ones referred to in part (c) above?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(ए) 17.

यह थाने अम्बाला भाहर, अम्बाला छावनी, सदर अम्बाला, मुल्लाना, कालका, पंचकूला, पिंजौर, चंडीमंदिर, नारायणगढ, रायपुर रानी, सढौरा, भाहर यमुनानगर, सदर यमुनानगर, जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर और छप्पर में स्थित है।

(बी) भवनों का निर्माण निम्नलिखित वर्शों में किया गया था:—

क्र. सं.	पुलिस स्टे ान का नाम	निर्माण का वर्श
1	अम्बाला भाहर	1922
2	अम्बाला छावनी	1939
3	सदर अम्बाला	1929
4	मुल्लाना	1867
5	कालका	सही वर्श की जानकारी नहीं है किन्तु भवन लगभग 100 वर्श पुराना है
6	पंचकूला	यह जनवरी, 1983 से किराए के भवन में स्थित है।
7	पिन्जौर	1865
8	चंडीमंदिर	1865
9	नारायण गढ़	1865
10	रायपुर रानी	1913

11	सढौरा	1865
12	भाहर यमुनानगर	1983
13	सदर यमुनानगर	यह पुलिस स्टे ान आई0टी0आई0 भौड में 1970 से स्थित है।
14	जगाधरी	1887
15	छछरौली	सही वर्श उपलब्ध नहीं है। यह लगभग 150 वर्श पुराना है।
16	बिलासपुर	1865
17	छप्पर	1867

(सी) हां जी। लोक निर्माण विभाग ने पुलिस स्टे ान चंडीमंदिर के भवन को 24.8.77 को असुरक्षित घोशित किया था।

(डी) हां जी। परियोजित किस्तों में।

Appointment of Untrained Science Teachers

54. Shri Mangal Sein: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether any untrained Science teachers were appointed in the State during the year 1971-1972; if os, the number thereof;

(b) the number of Teachers, if any, out of those referred to part (a) above, who have passed B.Ed; and

(c) whether the services of all the Teachers referred to in part (b) above have been regularised?

Minister of State for Education (Shri Jagdish Nehra)

(a) No.

(b) & (c) The question do not arise.

विभिन्न विशयों को उठाया जाना

श्री हीरा नंद आर्य: स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैन ान नोटिस दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि उसके बारे में आपने क्या फैसला लिया है।

श्री अध्यक्ष: मैं उसे अभी कंसीडर कर रहा हूं।

(1) राज्य में सिविल विमानन पट्टियों में कुप्रबंध संबंधी

प्रोफेसर सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मेरा एक काल अटैं ान नोटिस सिविल हवाई पट्टियौं से संबंधित था। नारनौल हिसार या जो दूसरी हवाई पट्टी है, इन पट्टियों पर कुल्लू और राजस्थान से ऐंटी सो ाल एलिमैंटस अफीम, गांजा आदि की तस्करी करते है। स्पीकर साहब, तस्करी वहां पर बढ़ती जा रही है, उनकी रोकथाम के लिए कोई प्रबंध नहीं है।

श्री अध्यक्षः आपका नोटिस मुझे लेट मिला है, उसे मैं अभी कंसीडर कर रहा हूं।

(2) सहकारी बैंक सरसा में हरिजनों की नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैं ान नोटिस सहकारी बैंक सिरसा के बारे में दिया था कि वहां पर नियुक्तियों के समय हरिजनों के साथ ज्यादती हुई है। हरिजन लड़कों को न रख कर राजस्थान और हिमाचल के बि ानोई लड़कों को रखा गया है और हरिजनों के लिए रिजर्वे ान का ख्याल नहीं रखा गया। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे काल अटैं ान नोटिस को क्या मंजूर कर लिया गया है या नहीं।

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाइए। उसकों मैंने डिस–अलाउ कर दिया है और यह इन्फर्मे ान आपको मिल जायेगी।

वाक आउट

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, यह तो हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए मैं वाक आउट करता हूं।

(इस समय श्री भागी राम वाक आउट कर गए)

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, यह माईक मेरे से अढ़ाई फुट छोटा है। इसको जरा ऊंचा करने का कुछ न कुछ प्रंबध कर दें तो अच्छा रहेगा। स्पीकर साहब, मैंने महेंद्रगढ़ अस्पताल के बारे में एक काल अटैं ान नोटिस दिया हुआ है, उसका क्या हुआ।

श्री अध्यक्षः उसको मैंने एडमिट कर लिया है। वह 21 तारीख को लगेगा।

अध्यक्ष द्वारा रूलिंग–

बजट के अभिकथित लीक होने के बारे में ब्रीच आफ प्रिविलिज के प्र न संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members on the 14th instant, at the time of presentation of Budget, Dr. Mangal Sein, MLA had alleged breach of privilege on account of leakage of Budget to the newspapers to the effect that taxes to the tune of Rs. 40 crores will be imposed in the Budget. However, as required under Rule 262 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, the members did not give any notice in writing and attach the news-papers in support of the notice. Moreover, there were no tax

proposals to the above said extent in the Budget presented later as alleged by the Hon'ble Member.

However, as per page 234 of the Book "Practice and Procedure of Parliamen" by Kaul and Shakdher, it has been stated as under:-

"Leakage of Budge proposals or official secrets does not form any basis for a breach of privilege.

On March 3, 1956, when notices of Adjournment motion were given by two members in connection with an alleged leakage of budget proposals, another member contended that it constituted an express breach of Privilege of the House. In this connection, the Speaker gave the following ruling:-

The precedents of the United Kingdom should guide us in determining whether any breach of privilege was in fact committed in the present case. So far as I can gather, only two cases occurred in which the House of Commons took notice of the leakage of the budget proposals. They are known as the Thomas case and the Dalton case. In neither of these cases was the leakage treated as a breach of Privilege of the House nor were the cases sent to the Committee of Privileges for inquiry. The prevailing view in the House of Commons is that until the financial proposals are placed before the House of Commons, they are an official secret. A reference of the present leakage to the Commitee of Privileges does not, therefore, arise."

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, जब मैंने प्वायंट आउट किया था, उस समय तक बजट स्पीच पढ़ी नहीं गई थी। यह बात अखबारों में छपी है। मैंने वह बात आपके नोटिस में लाई थी। यदि ऐसी कोई बात होती तो मैं बकायदा लिख कर आपको देता।

Mr. Speaker: I have done my duty.

Shri Mangal Sein: I also did my duty, Sir.

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव–

महिला आश्रम, करनाल में रह रहे बंगला दे ा के भारणार्थियों की मांगों संबंधी

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे डा0 मंगल सैन, एम0एल0ए0 की तरफ से महिला आश्रम करनाल में जो बंगला दे ा के रिफ्यूजी ठहरे हुए है, उनके बारे में एक काल अटैं ान मो ान का नोटिस मिला था, मैं उसे एडमिट करता हूं। डा0 मंगल सैन अपना नोटिस पढ़ दें। उसके बाद यदि मंत्री महोदय आज जवाब देना चाहें तो दे सकते है।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मैं इस ध्यानाकर्शण सूचना द्वारा सरकार का ध्यान अत्याधिक लोक महत्व के इस विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि महिला आश्रम, करनाल के इनमेटस ने, जो कि बंगला दे ा के भारणार्थी है, जिलाधी ा के दफ्तर के बाहर धरना दे रखा है। उनकी मांग है कि उनको 50/– रूपये

के बजाए 100/– रूपये प्रतिमास प्रत्येक व्यक्ति सहायता डोलज दी जाए। जाहं वह रह रहे है उनके स्थानों को ठीक कराया जाए तथा बिजली भी ठीक कराई जाए। वर्शा के दिनों में उनकी कोठियों में पानी रिसता है।

मैं इस प्रस्ताव द्वारा सरकार का ध्यान उनकी दयनीय अवस्था के बारे में आकर्शित करना चाहता हूं। सरकार इस बारे में अपनी स्थिति स्पश्ट करें।

वक्तव्य

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती भाकुंतला भगवाड़िया): अध्यक्ष महोदय, इस का जवाब मैं अभी दे देती हूं।

यह बंगाली विधवा महिलाएं वर्श 1964 में बंगला दे ा से भारत में विस्थापित की गई। आरम्भ में इनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए माना कैम्प, जिला रायपुर (मध्य प्रदे ा) में रखा गया और बाद में वर्श 1969–70 में भारत सरकार ने इन परिवारों को महिला आश्रम, करनाल में तबदील करने का निर्णय लिया और तभी से यह परिवार अपने बच्चों के साथ इस आश्रम में रह रहे है।

2 महिला आश्रम को चलाने के लिए जो नियम भारत सरकार द्वारा बनाये गये थे, उनके अनुसार इन परिवारों के प्रत्येक सदस्य को, जो योग्य हो, निर्वाह तथा कपड़ा भत्ता 50/–रू0 तथा 10/–रू0 प्रति मास सवांसी की दर से दिया जाता है। इस

भत्ते को 50/– रू0 से बढ़ाकर 100/–रू0 प्रति मास, प्रति व्यक्ति करने के मामले पर विचार किया जा रहा है।

3 वर्श 1974 से इन सवांसयिों का पालन–पोशण का खर्चा केंद्रीय सरकार से बदल कर राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्श 1974–75 से लगभग 18.57 लाख रू0 महिला आश्रम, करनाल में रहने वाली सभी संवासियों पर खर्च हो चुका है, जिनमें से अधिकतर सवांसी बंगाली है।

4 समाज कल्याण विभाग आजकल प्र ि ाक्षण तथा उत्पादन केंद्र महिला आश्रम, करनाल में चला रहा है, जहां इन विधवााओं तथा इनकी लड़कियों को कई अन्य प्रकार की दस्तकारी का काम सिखाया जाता है ताकि वे अपने निर्वाह के लिये कमाने मैं सक्षम हो सकें। नि ाुल्क ि ाक्षा दसवीं के स्तर तक इन विधवाओं के बच्चों को दी जाती रही है और यह प्रथा उस समय से ही चली आ रही है, जिस समय से उन्हें माना कैम्प से महिला आश्रम, करनाल में तब्दील किया गया था।

5 इन परिवारों को बसाने के प्रयत्न में और इन विधवाओं की लड़कियों के विवाहों के लिये समाज कल्याण विभाग काफी समय से वित्तिय सहायता कर रहा है। संवासियों की लड़कियों के विवाह पर भी सरकार द्वारा 500/– रूपये का अनुदान दिया जाता है। अब तक 26 लड़कियों के विवाह सम्पन्न करवाये जा चुके है। पिछले वर्श अप्रैल, 1982 में सरकार ने 6

लड़कियों के विवाह किये है और प्रत्येक लड़की के विवाह पर 2500/– रूपये खर्च किये है। इन विवाहों पर पब्लिक ने बहुत सहयोग दिया है।

6 क्योंकि अब इन विधवाओं पर आश्रित लड़के 19 साल की आयु के हो चुके है और नियमों के अनुसार यह आश्रम में ठहरने के योग्य नहीं रहे। बंगाली परिवारों की संख्या इस समय 68 है जिनमें से 41 परिवार अनाधिकृत है।

7 पिछले कुछ महीनों से केंद्रीय सरकार, पुनर्वास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग से पत्र व्यवहार किया जाता रहा है। काफी प्रयत्नों के प चात समाज कल्याण विभाग ने पुनर्वास मंत्रालय से एक स्कीम प्राप्त की जिसके अनुसार इनको दोबारा से बसाया जा सकेगा। पुनर्वास मंत्रालय इस बात पर सहमत हो गया है कि इन्हें घर तथा दुकान के लिए 9000/– रूपये का कर्ज (8000/– रूपये मकान के लिये तथा 1000/– रूपये दुकान के लिये) प्रत्येंक विधवा को दिया जाये। इसके अतिरिक्त 5000/– रूपये की धनरा ि ा अलग से कर्जे के तौर पर इन्हें कोई व्यवसाय चलाने के लिए पुनर्वास मंत्रालय द्वारा दी जायेगी। ज्यों ही यह योजना निर्णायक रूप में पहुंचेगी, लाभ–पत्रों को बने बनाये कमान आवास बोर्ड से लेकर देने में सहायता की जायेगी।

8 ऊपर वर्णित तथ्यों से यह पता चल जायेगा कि राज्य सरकार ने हर सम्भव सहायता पिछले 12 वर्शों से की है और कोई भी कमी उनकी सहायता और सुविधाएं उपलब्ध करवाने में नहीं छोड़ी। इन कारणों से इस समय किय जाने वाले ऐजीटे ान जो यह परिवार कर रहे है, ठीक नहीं है तथा यह निंदनीय है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, बहन जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। क्या बहन जी बताने का कश्ट करेंगी, जैसा इन्होंने कहा कि भारत सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो महिलायें और लोग उजड़े हुए है और करनाल में इन लोगों को रखा हुआ है जिन्होंने वहां पर धरना दे रखा है और जिन के साथ आप बड़ी सहानुभूति दिखा रहे है, क्या केंद्रीय सरकार के साथ पत्राचार करके, कोई कौरेस्पौंडैंस करके इस बात की स्वीकृति सहमति, केंद्रीय सरकार से करवा ली है कि इन लोगों को आठ आठ हजार रूपया मकान के लिए और पांच–पांच हजार रूपया कर्जे के तौर पर दिया जायेगा यदि हां तो यह निर्ण कब तक लागू हो जायेगा? यह योजना कब तक लागू हो जायेगी?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़ियाः स्पीकर साहब, मैंने योजना तो मैम्बर साहब को बता दी है और इस पर जल्दी ही अमल हो जायेगा। इसक तामील के लिए समाज कल्याण विभाग के अधिकारी वहां पर जा रहे है। इससे पहले भी हमने बात कर ली है। वहां पर हरियाणा की विधवा औरतों के लिए विधव आश्रम बनाना है और इस आश्रम में रहने का हर एक विधवा महिला का

अधिकार है, लेकिन वहां पर हमे ाा के लिए इन को बसने देंगे तो हरियाणा की दूसरी महिलाओं के लिए आश्रम का साधन नहीं रहेगा। इस योजना को साकार रूप देने के लिए भारत सरकार से बातचीत कर ली है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, बहन जी ने बहुत अच्छा कहा है, मैं इनकी योग्यता की दाद देता हूं। अब मैं यही पूछना चाहता हूं कि जो कुछ आपने तय किया है उसको पूरा करने के लिए क्या आपने कोई अधिकारी उन बहनों के पास भेजा है यह जानने के लिए कि उनको क्या तकलीफ है, अगर भेजा है तो क्या वे मान गई है?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़ियाः मैं डा0 मंगल सैन जी को बता देना चाहूंगी कि मैंन उनसे पहले ही बात की है, अगर कोई भाक है तो ये स्वयं मनाने चले जाएं। अगर सरकार को उनके साथ सहानुभूति न होती तो इनको यह सहायता कैस देती? पिछलें दिनों 6 लड़कियों की भाादियां की है जिसमें इस संस्था के लोगों को भी भाामिल किया था। मैं स्वयं जाकर उनकी तकलीफ पूछती हूं, अधिकारियों पर डिपैंड नहीं करती।

श्रीमती चंद्रावतीः स्पीकर साहब, मैंने अखबार में भी स्टेटमैंट दी थी कि मानवता के नाते से विधवा औरतों की सहायता करना केवल सरकार का ही हक नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के हर एक सिटीजन का कर्तव्य है, धर्म है, लेकिन मैं बंगला दे ा

के रिफ्यजियों को हरियाणा स्टेट में बसाने के बिल्कुल खिलाफ हूं और हम चाहते है कि हरियाणा में बंगला दे ा का कोई रिफ्यूजी नहीं होना चाहिएं

श्रीमती भाकुंतला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, यह भारतवर्श की परम्परा रही है कि जो भी भारत के अंदर दुखिया हो, उसकी सहायता की जाए और भारत ने इनको हमे ाा भारण दी है। भारत सरकार का कोई भी व्यक्ति उनको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होने देता।

वर्श 1983–84 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनराम्भ)

श्री अध्यक्ष: अब बजट पर डिस्क ान भाुरू होगी। मास्टर ि ाव प्रसाद जो 16 तारीख को बोल रहे थे, वे अपनी स्पीच कंटीन्यु कर सकते है।

मास्टर ि ाव प्रसाद: (अम्बाला सिटी): अध्यक्ष महोदय, उस दिन बजट पर बोलते हुए मैंने सिर्फ एक ही विशय पर रो ानी डाली थी।

श्री अध्यक्ष: आप उस दिन दस मिनट बोल चुके थे। आप जल्दी खत्म करें।

मास्टर ि ाव प्र ाद: उस वक्त भाोर हो रहा था, टाईम सारा जाया हो गया था। खैर, मैं अब टू दी प्वायंट ही बोलूंगा और वहीं बतों कहूंगा जो सरकार के लिए फायदेमंद होंगी

और हरियाणा के लोगों के लिये फायदेमंद होगी। स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अपोजी ान की तरफ से टैक्स के बारे में कोई खास बात नहीं कही थी। मैंने तो अपनी स्पीच भुरू ही टैक्स से की थी। उन्होंने बजट में, मंडियों में आने वाले अनाज की खरीद पर एक रूपया सैंकड़ा का टैक्स लगाकर गरीब मजदूरों पर, कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर और छोटी आय वाले लोगों पर अत्याचार किया हैं इन लोगों के लिए तो एक जजिया है। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार को बताना चाहता हूं कि हरियाणा में किसी चीज पर दो परसैंट, किसी पर चार परसैंट, किसी पर छः परसैंट, किसी पर सात परसैंट किसी पर दस परसैंट टैक्स लगा हुआ है। भिन्न–भिन्न चीजों पर भिन्न भिन्न दर से टैक्स लगे हुए है और अब सरकार ने यह टैक्स सात परसैंट से आठ परसैंट कर दिया है, आठ से दस कर दिया है और दस से बारह कर दिया है। एय्या ाी की चीजों पर टैक्स बढ़ाते है तो अच्छी बात थी लेकिन इन्होंने मेहंदी पर टैक्स लगा दिया। मान लो किसी लड़की की भाादी पर कोई फ्री गिफ्ट देना है तो वह व्यक्ति यह गिफ ्ट हरियाणा से नहीं खरीदेगा बल्कि हरियाणा के साथ लगती हुई पंजाब स्टैट से खरीदेगा क्योंकि पंजाब स्टैट में टैक्स कम है। अम्बाला में रहने वाला आदमी राजपुरा से खरीदेगा, हरियाणा से खरीदकर वह बारह परसैंट टैक्स क्यों देगा? सिरसा जिले के लोग भठिंडा से चीजें लेंगें क्योंकि भठिंडा पंजाब का एरिया है और उनके नजदीक पड़ेगा। दिल्ली के आसपास बसने वाले लोग दिल्ली से खरींदेंगे। हरियाणा से

खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक अय्या ी के सामान का ताल्लुक है, इन्होंने महंदी को अय्या ी का सामान मान कर इस पर भी टैक्स लगा दिया। भाादी के बाद करवा चौथ का एक त्योहार होता है। उस दिन महंदी वगैरह लगाकर औरतें अपना श्रृंगार करती है। इन्होंने महंदी को अय्या ी के सामान में भाामिल कर दिया और दस परसैंट से बढ़ाकर बारह परसैंट कर दिया। स्पीकर साहब, आज मामूली से मामूली आदमी दातुन करता है। पहले कीकर वगैरह के वृक्ष होते थे, लोग दातुन कर लिया करते थे लेकिन अब ये द्रख्त इन्होंने कटवा दिये है और जो बचे है वह कटवा रहे है। कहीं पर दातुन मिलती ही नहीं इसलिए हर एक आदमी ब्रु ा खरीदता है, लेकिन इस पर भी दस परसैंट से बारह परसैंट टैक्स बढा दिया। ब्रु ा को भी अय्या ी के सामान में भाामिल कर लिया। इसलिए इन्होंने जो सात परसैंट से आठ परसैंट और दस परसैंट से बारह परसैंट टैक्स बढाया है, यह आम जनता के ऊपर ही बढाया है और छोटे व्यापारी को तबाह करके रख दिया है। हरियाणा खेती प्रधान प्रदे ा है। अगर यहां पर खेती नहीं होगी तो इंडस्ट्री नहीं पनपेगी, अगर इंडस्ट्री नहीं पनपेगी तो व्यापारी नहीं पनपेगा। खेतीबाड़ी को नुक्सान होगा तो यहां का व्यापारी उड़कर बराबर वाले प्रांत में चला जायेगा। स्पीकर साहब, सरकार किसान की हमदर्द बनती है लेकिन जब किसान अपने ट्रैक्टर के स्पेयर पार्टस खरीदने के लिए दिल्ली की मार्किट में जायेगा तो उसको चार परसैंट सैल्ज टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब हरियाणा से खरीदेगा तो उसको आठ परसैंट टैक्स

देना पड़ेगा। स्पीकर साहब, मैं इस विशय पर ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हरियाणा में पहले ही ज्यादा टैक्स लगे हुए है इसलिए सात परसैंट को सात ही रहने दीजिए, दस परसैंट को दस ही रहने दीजिए और भिन्न भिन्न चीजों पर जो सात, आठ, नौ, दस परसैंट कई तरह के टैक्स लगे हुए है इनको तीन, चार, पाचं परसेंट के आसपास ले आयें ताकि सैल्ज टैक्स की जो चोरी होती है वह खत्म की जा सके। ऐसा करने से कुरप्ान भी कम होगी, और जो नम्बर दो का पैसा कमाने वाले है, टैक्स की चोरी करते है ये भी कम हो जायेंगे। मेरी सरकार से दुख्र्वास्त है कि कुरप्ान को खत्म करने के लिए, रि वत को खत्म करने के लिए, सेल्ज टैक्स की चोरी को दूर करने के लिए टैक्स को घटाकर तीन, चार या पांच परसैंट ले आयें। दूसरी बात यह है कि जहां पर मौलिक रूप से चीजें तैयार होती है वहीं पर सैल्ज टैक्स लगना चाहिए ताकि बीच में कोई भी व्यक्ति चोरी न कर सकें। ऐसा करने से वित्त मंत्री, और एक्साईज एंड टैक्से ान मिनिस्टर की सिरदर्दी भी खत्म हो जायेगी और गरीब जनता को भी नौकर ााही के चुगल से बचाया जा सकेगा। मैं वित मंत्री महोदय से पुनः विचार करने के लिए कहूंगा कि सेल्ज टैक्स में बढाई हुई दरों को वापिस लिया जाये।

अब मैं थोड़ा सा ला एंड आर्डर के बारे में सरकार का ध्यान आकर्शित करना चाहूंगा। सरकारी बैंचिज की तरफ से मेरे दोस्त, श्री कुंदन लाल जी, जो बैकवर्ड क्लासिज के इकलौते

नुमांयदे है, हरिजन भाइयों के बारे में बड़ा राग अलाप रहे थे। हमें अच्छी बातों को अपनान चाहिए और बुरी बातों को त्यागना चाहिए। बीस सूत्री प्रोग्राम के आधार पर जो उन्होंने कार्य किया है उसकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं। ला एंड आर्डर को मेनटेन करने के लिए पुलिस के ये अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है। पुलिस के अधिकारी अगर ठीक काम करें तो उन्हें प्र ांसा पत्र मिलना चाहिए लेकिन जो लोग इस सरकार पर कलंक है और सरकार का इमेज खराब करते है, भ्रश्ट है, उनके खिलाफ केस चलाना चाहिए। भ्रश्टाचार के केस दर्ज किये जाते है लेकिन फिर कैंसिल कर दिये जाते है। धर्म सिंह डी0एस0पी0 जगाधरी ने नफे सिंह एस0आई0 संढौरा को ठेकेदार मोहम्मद तैयब खां की इंक्वायरी पर लगाया था। सीमेंट की हेराफेरी करने के बारे में मोहम्मद तैयब खां पर कई केस बने हुए है। ि ाकायत पर केस दर्ज हुआ था और इन्कवायरी हुई। इन्कवायरी होने पर उसके खिलाफ भ्रश्टाचार का केस दर्ज हुआ लेकिन एक्स फाइनैंस मिनिस्टर के रि तेदार होने के कारण उस केस को वापिस ले लिया गया। केस दर्ज होने के बाद भी यह सरकार केस वापिस ले लेती है यह गलत बात है। डी0एस0पी0 ने बाद में केस को वापिस लिया। ऐसे अफसरों के खिलाफ एक ान होना चाहिए। काइम दिन प्रति दिन बढ रहे है, कम नहीं हो रहे है। इसी तरह से जांडली गांव के अंदर झींवर की लड़की के साथ चार बदमा ाों ने रेप किया। इनमें से दो बदमा ाों को पकड़ लिया गया और दो पकड़े नहीं गये। डी0एस0पी0 ने बताया कि केस ठीक दर्ज हुआ

है लेकिन उन बदमा ाों में एक कांग्रेस लेडी वर्कर का भाई था। पुलसि पर दबाव पड़ा और जिस ए0एस0आई0 ने केस दर्ज किया था उसकी ट्रांसफर करवा दिया गया। जो अफसर अच्छे होते है उनके ट्रांसफर कर दिये जाते है। इसी तरह से माडल टाउन में हुआ। भााहपुर गांव के एक पुल के नीचे एक महिला की ला ा मिली है लेकिन इस केस का भी कोई पता नहीं चला। यह हालत है इस सरकार की। अब मुख्य मंत्री महोदय भी बड़े परे ाान है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में 36 लोग भाामिल हुए है। भाुरू भाुरू में तो वे मान गये कि हम कांग्रेस की मदद करना चाहते है लेकिन अब नाजायज काम करवा रहे है। इसी तरह से संढौरा की बाल्मीकि लड़की के साथ आठ मार्च को दो लड़कों ने रेप किया। दोनों लड़के आज तक पकड़े नहीं गये। केस दर्ज है। कांगेस बैंचिज पर जो बैकवर्ड या हरिजन भाई बैठे है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसी तरह से आप लोग सरकार की मदद कर रहे है आपकी औरतों की इज्जत लूटी जा रही है और आपका भला होगा लेकिन जनता का भला नहीं होगा। आप लोगों की इंकम तो बढ़ेगी लेकिन बैकवर्ड या हरिजनों का भला होने वाला नहीं । हरिजन औरतों या बैकवर्ड क्लास की औरतों की इज्जत और सुरक्षा की जिम्मेदारी आ लोगों पर है।

इसी प्रकार से मैं सरकार का ध्यान रिकवरी की ओर भी दिलाना चाहता हूं सरकार कहती है कि सन् 1983–84 में 180 करोड़ रूपये के ऋण सहकारिता विभाग द्वारा दिये जायेगें। पहले

भी मैंने सहकारिता विभाग के केसिज बताये है। अब भी मैं सहकारिता मिनिस्टर महोदय के नोटिस में कुछ केस लाना चाहता हूं आज एडमिनिस्ट्रे ान को सतर्क करने की आव यकता है। जिस केस का मैं जिक करना चाहता हूं वह डी0सी0 साहब के नोटिस में भी आया है। दलजीत सिंह ने अपने पिता जगीर सिंह के प्रार्थना पत्र पर 73–74 हजार रूपया लोन सहकारिता विभाग से लिया है। वह कांग्रेस वर्कर है। इंट्रैस्ट पड़ने पर यह लोन एक लाख तिहतर हजार हो गया। उसके वारंट इ ाू हुए, तहसीलदार ने गिरफतार किया लेकिन फिर केस को ढीला करदिया गया। कांग्रेस के प्रैजीडैंट ने उसे दुड़वा दिया। उसके बाद फिर वारंट इ ाू हुए लेकिन फिर फूलचंद मौलाना जो कि मिनिस्टर है ने उसे छुड़वा दिया। जिस आदमी के खिलाफ वारंट इ ाू हों और फिर उसे छोड़ दिया जाये कितनी बुरी बात है। इसके दूसरी तरफ गरीब आदमियों को तंग किया जाता है। इसी तरह से मेहर सिंह रिकवरी इंसपैक्टर पीटा गया उसे कोई सरंक्षण नहीं मिला इन हालात में रिकवरी कैसे होगी? गरीब आदमी को लोन का पैसा मिलना चाहिए ताकि वे ऊपर उठ सकें। मुख्य मंत्री भाांताकुमार और श्री भोखावत के नक ोकदन पर इस सरकार को चलान चाहिए।

स्पीकर साहब, ि ाक्षा के विशय को ले कर मैंने अपनी स्पीच भाुरू की थी और उसी पर मैं समाप्त करना चाहता हू। दो करोड़ रूपया स्कूल की ि ाक्षा के लिये आया है। लेकिन वह

स्कूल–ि ाक्षा पर खर्च न करके रोहतक यूनिवर्सिटी को दे दिया गया? यह स्कूलों पर ही खर्च होना चाहिए था। इसी प्रकार से प्राईवेट स्कूलों के लिए तीस–चालीस लाख रूपया रखा गया लेकिन वह भी खर्च नहीं हुआ। मिनिस्टरों को तो करोड़ों रूपये का भत्ता दे दिया गया लेकिन वह भी खर्च नहीं हुआ। मिनिस्टरों को तो करोड़ों रूपये का भत्ता दे दिया जाता है लेकिन प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता। सरकारका फर्ज बनता है कि उन गरीब अध्यापकों का भी ध्यान रखे और प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों की डिमांड को पूरा करे। इन भाब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री सागर राम गुप्ता(भिवानी): स्पीकर साहब, सदन में सन् 1983–84 का बजट पे ा हुआ है। हमारे फाइनैंस मिनिस्टर महोदय ने बजट पे ा किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और उन्हें मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रांत के लिए एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बजट पे ा किया है।

स्पीकर साहब मैने पंजाब और हिमाचल प्रदे ा के बजट को देखने की कोि ा ा की। तीनों स्टेटस का बजट देखने के बाद, मैं इकोनोमिक्स का स्टूडैंटस होने के नाते यह कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने जो बजट पे ा किया है, वह तीनों प्रांतों से अच्छा है। लोगों के हितों का बजट है। मैं क्यों कहता हूं? मैं इसलिए नहीं कहता कि हमारे फाइनैंस मिनिस्टर या हमारे चीफ

मिनिस्टर बहुत काबिल और पढ़े–लिखें है। मैं इसलिए कहता हूं कि वाकई ही सही मानों में एक ऐसा बजट पे ा किया गया है जिससे आने वाले सालों में हरियाणा की जनता का और खासतौर पर गरीब लोगों का बैकवर्ड का, हरिजन, मजदूर और किसानों का भला होगा। मेरे विरोधी दल के भाई जो इस बजट की निंदा करते है उसके दो ही कारण हो सकते है, तीसरा कारण नहीं हो सकता। एक तो यह हो सकता है कि उन्होंने बजट को पढ़ा ही न हो और दूसरा कारण यह हो सकता है कि उन्होंने विरोध ही करना है, चाहे वह सही है या गलत है, यानी न मानू वाली बात है मैं इस बजट को बहुत अच्छा इसलिए मानता हूं कि हमारा जो पिछले साल का अनुअल प्लान था वह 300.7 करोड़ का था लेकिन इस साल 406.79 करोड़ का है, यानी 26.8 परसैंट बढौतरी हुई है। मैं इस बात के लिए भी फाईनैंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और सरकारी अफसरान को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने सैंट्रल प्लानिंग कमी ान से इतना बढ़ा कर आउट–ले मंजूर करवाया है। आप सब मुबारिकबाद के मुस्तहिक है। मैं भी कुछ समय तक हरियाणा में वित विभाग का राज्य मंत्री रहा हूं। **(11.00 बजे)** मुझे मालूम है कि प्लानिंग कमी ान कितनी सरकार की जान खाता है और किस कठिनाइ से वह प्लान को मंजूर करता है। स्पीकर साहब, इतनी बढौतरी प्लान–आउट–ले में मंजूर करना, इस बात को साबित करता है कि प्लानिंग कमी ान आज इस बात को मानकर चलता है कि हरियाणा सरकार की इकोनोमी साउंड लाईंज पर है, वरना वह इतनी बढौतरी अलाउ कभी न करता। आज

प्लानिंग कमी ान इस बात को मानकर चलता है कि हरियाणा के रिसोर्सिज की पोजि ान काफी एंकरेजिंग है और भविश्य में और भी अच्छी होने के संभावना है। इसलिये उसने इस साल की इतनी बढ़ी हुई प्लान आउट–ले को मंजूर किया है। इसके बाद आप इस प्लान आउट–ले में यह देखिये कि एलोके ान कितनी बढ़िया कर रखी है। आज हमारे विरोधी पक्ष वाले भाई कि टिसाइज तो करते है लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे बजट को जरा अच्छी तरह से एनेलाईज करें। इस बात को सब जानते है कि हरियाणा का तकारों का प्रांत है। एग्रीकल्चर हमारा बेस है जोकि यहां की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और हकिरयाणा की तकरीबन सत्तर प्रति ात जनता एग्रीकल्चर पर आधारित है। एग्रीकल्चर के लिये इरीगे ान और पावर दोनों साधन बहुत जरूरी है। हमारी सरकार ने इस टोटल 406.59 करोड़ रूपये के प्लान आउट–ले में से इस साल 235.24 करोड़ रूपया केवल इरीगे ान और पावर पर खर्च करने के लिये रखा है। यह हमारी सरकार कितना कुछ करना चाहती है। यह रा ि ा पिछले साल के मुकाबले में 31.35 प्रति ात से ज्यादा इस आईटम पर है। आप अंदाजा लगाइये। मेरी पार्टी की सरकार कितनी को ि ा ा कर रही है कि इस स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले और इसके फलस्वरूप जो जनता एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसिज के लिए स्पीकर साहब, पिछले साल के मुकाबले में 18.43 प्रति ात ज्यादा रा ि ा इस साल की प्लान आउट–ले रखी गयी है। इंडस्ट्रीज के लिये 27.25 प्रति ात ज्यादा है।

सो ाल एंड कम्युनिटी सर्विसिज और इकोनौमी सर्विसिज में तो पिछले साल के मुकाबले में 25.79 प्रति ात और सर्विसिज और इकोनौमी सर्विसिज में तो पिछले साल के मुकाबले में मोर दैन डबल है। इतनी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद भी अगर इस बजट को निरा ाजनक कहें तो आप जानते है कि यह तो अनपढों वाली बात होगी, कोई समझदारी की बात नहीं होगी। (व्यवधान व भाोर) मैंने तो यह कहा है कि जो इसका विरोध करते है, वे अनपढ़ है, इन्होंने इसको अच्छी तरह से पढ़ नहीं हैं अब एक और नजरिये से देखें। जो हमारी प्रधान मंत्री का बीस प्वायंट प्रोग्राम है जिसकी हमारी विरोधी पक्ष के एक भाई तारीफ कर रहे थे। इस प्रोग्राम से गरीबों का या हरिजनों का देहातों में उत्थान होगा। इस बीस प्वायंट प्रोग्राम से देहात के गरीबों, हरिजनों और बैकवर्ड भाइयों का भला होगा जिसके लिए अस्सी प्रति ात रूपया प्लान आउट–ले में नि चत किया गया है। आप अंदाजा लगाइयें कि यह सरकार कितनी कोि ा ा कर रही है ताकि गरीब हरिजनों का, बैकवर्ड भाइयों का और गरीबों का उत्थान हों। उनको ज्यादा नौकरियां मिलें, वे ज्यादा इंडस्ट्रीज लगा सकें, उनको मकान मिलें और उनकों जमीन वगैरह दूसरी सुविधायें मिलें। गांवों के उत्थान के लिए सरकार ने रूरल डिवैल्पमैंट फंड क्रियेट करने का फैसला किया है। स्पीकर साहब, अगर कोई यह चाहे कि हल्दी लगे न फटकरी और रंग चौखा हो जाये तो वह बात तो होने वाली नहीं है। अगर इसके लिये हमने एक परसैंट सैंस लगा दिया है तो कोई गुनाह नहीं किया है,

इससे अगर देहात की लोकल मु कलात और छोटे मोटे मसले वहीं पर ही हल हो जाया करेंगे तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? मैं यह समझता हूं कि यह बहुत अच्छा कदम है। यह सारे दे ा में पहला प्रांत है जिसने ऐसा किया है कि देहात को ऊपर उठाने के लिये यह कदम उठाया है। (व्यवधान व भाोर) स्पीकर साहब, मैं यह तीन–चार बातें ही मोटे तौर पर अर्ज करना चाहता था। स्पीकर साहब, जहां हमारी इकोनौमी साउंड लाईंज पर है, वहां मैं सरकार को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं जिनसे सरकार के रिसोर्सिज की पोजी ान बैटर हो सकती है। मुझे आ ाा है सरकार मेरे सुझावों को मानेगी और अपनी पोजी ान बैटर करने की कोि ा ा करेगी। उसके लिए एक तरीका तो मैं यह समझता हूं जो मैं अब बताने वाला हूं। सरकार आज कल केवल एडमिनिस्ट्रे ान करने वाली एजेंसी ही नहीं रह गई है। केवल कानून बनाने वाली या उसको लागू करने वाली एजेंसी ही नहीं रह गई है। मेरा मतलब यह है कि जैसे पिछले जमाने में स्वर्ण लोग राज करते थे, वैसा फंक ान इसका नहीं रह गया है। सरकार आज व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन गई है। आज सरकार आम लोगों के फायदे के लिए बहुत सी इंडस्ट्रीज भी चला रही है। सो ाल सर्विस के लिए स्पीकर साहब, हरियाणा में बहुत से बोर्डज और कारपोरे ांज बने हुए है। मैं यह चाहता हूं कि उनकी वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए सरकार को कोि ा ा करनी चाहिए ताकि उनके रिसोर्सिज की पोजी ान अच्छी हो सके। (व्यवधान व भाोर) कमी तो हर जगह पर होती है यदि

उसमें सुधार कर लिया जाये तो कोई बुरी बात नहीं होती। मेरी समझ में एक बात यह आती है कि जितने भी हमारे बोर्डज और कारपोरे ांज है, उनको अच्छे मैनेजमैंट की जरूरत हैं। मैं खास तौर पर यह कहूंगा कि बोर्डज या कारपोरे ांज में, जो मैनेजिंग डायरैक्टर्ज हों, वे ऐसे लोग हों जिनको इकोनोमिक्स का, कौमर्स का और एकाउंटस का तजुर्बा हो। अगर हम ऐसा करेंगो तो बोर्डज और कारपोरे ांज अच्छी चल सकती है। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि इनमें जो औवर–हैडज है वे कम किए जायें। अगर ऐसा हो जाये तो कारपोरे ांज और बोर्डज ज्यादा अच्छे तरीके से चल सकते है। स्पीकर साहब, इसके बाद मैं लेबर डिपार्टमेंट के बार में भी कुछ कहना चाहता हूं। मुझे इस बात की खु ाी है कि सरकार लेबर के उत्थान के लिए बजट में पहले से ज्यादा प्रोवीजन रख रही है। 1974–75 के अंदर केवल लेबर एंड एम्पलायमैंट के लिये 1.56 करोड़ का बजट था लेकिन इस साल यह 5.25 करोड़ रूपया है। यह बात काफी प्राउड के लायक है क्योंकि हमारी सरकार यह चाहती है कि लेबर्ज की पोजी ान अच्छी हो। ओवर आल लेबर की सिचुए ान स्टेट के अंदर बेहतर है। (घंटी) स्पीकर साहब, मैं दो चार मिनट ही लूंगा जल्दी ही समाप्त कर दूंगा। हालांकि हमारे यहां लेबर की बहुत अच्छी पोजी ान है लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा ताकि मजदूरों का ज्यादा भला हो सके। मैं ऐसे सुझाव दूंगा जिन से सरकार को बहुत ज्यादा दिक्कत पे ा नहीं आयेगी। पहला सुझाव मेरा यह है जैसे कि आप बौर बहुत से माननीय सदस्य भी जानते होंगे

कि एक ई0एस0आई0 स्कीम होती है जिसमें मजदूर की सो ाल सिक्योरिटी का प्रोवीजन होता है। बीमारी की हालत में, एक्सीडैंट की हालत में और मौत की हालत में मजदूर को रिलिफ देने के लिए इं योरैंस किया जाता है। तकरीबन–तकरीबन हरियाणा में सारे ही मजदूर इस स्कीम के तहत कवर्ड है। इस बात के लिए ई0एस0आई0 कारपोरे ान के पास करोड़ों रूपया है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सिवाये फरीदाबाद के हरियाणा में ई0एस0आई0 अस्पताल नहीं बनाए गए है। मजदूरों को दवाई लेने के लिए सिविल अस्पताल, छोटी डिस्पैंसरी या पैनल डाक्टर्ज के पास जाना पड़ता है। सिवाए फरीदाबाद के ई0एस0आई0 अस्पताल सारे हरियाणा में नहीं है। मेरी सरकार सै यही अर्ज है कि ई0एस0आई0 अस्पताल हरियाणा में बनाए जाएं। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि ई0एस0आई0 का अगर कोई अस्पताल बनाया जाता है तो उसका नब्बे प्रति ात रूपया कारपोरे ान देती है और सरकार को केवल दस प्रति ात देना पड़ता है। मैं सरकार से पुरजोर प्रार्थना करूंगा कि इस मौके का फायदा उठाकर मजदूरों के लिए अच्छे इलाज का प्रावधान करने के लिए सारे प्रदे ा में, जहां–जहां इंडस्ट्रियल मजदूर पांच हजार से ज्यादा है,वहां पर ई0एस0आई0 अस्पताल जल्दी से जल्दी बनाने की कोि ा ा की जाए। स्पीकर साहब, भिवानी में एक प्रोपोजल चल रही है (घंटी)। स्पीकर साहब, बोलने के लिए तो अभी बहुत था लेकिन अगर आप कहते है तो मैं बैठ जाता हूं।

राज्यपाल से संदे ा

श्री अध्यक्षः साहेबान, मुझे गवर्नर साहब की तरफ से एक चिट्ठी आई है मैं उसे पढ़कर सुना देता हूं–

"I write to acknowledge with thanks the receipt of your demiofficial letter No. HVS-LA-18/83/8071, dated 11th March, 1983, forwarding a copy of the Motion of Thanks passed by Haryana Vidhan Sabha at its meeting held on the 11th March 1983. Please convey to the members of the Haryana Vidhan Sabha my thanks and appreciation for this kind thought in acceptin the Motion.

वर्श 1983–84 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनराम्भ)

श्री कंवल सिंह (घिराई): स्पीकर महोदय, चौधरी कटार सिंह ने जो बजट पे ा किया है, उसकी खामियां बताने के लिए और उसका विरोध करने के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। स्पीकर साहब, कंज्यूमर्ज प्राइस इंडैक्स 1970 में सौ का बेस मानकर 1977 तक 146 था। 1978 में 151 हुआ, 1979 में 159 हुआ। उसके बाद सरकार का बीस सूत्री कार्यक्रम आया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1981 में एकदम 196 हो गया और 31 दिसम्बर, 1982 को 213 हो गया। स्पीकर महोदय, अब इन्होंने कंज्यूमर आइटम्ज पर सात करोड़ रूपए के टैक्स लगाएं है और आठ करोड़ रूपए के टैक्स, मार्किट कमेटीज से जो माल खरीदा जाएगा, उस पर लगाए है। मास्टर ि ाव प्रसाद ने भी सदन में बताया था कि सब लोगों के इस्तेमाल की चीजो ंपर इस सरकार

ने टैक्स लगाया है। (इस समय सभापतियों की सूचि में से एक सदस्य, चौधरी ई वर सिंह पदासीन हुए) चेयरमैंन साहाब, चौधरी कटार सिंह को पता होगा कि बीयर पर 1981–82 में दो करोड़ बाईस लाख की एक्साईट डयूटी लगती थी लेकिन अब आप सिर्फ 66 लाख रूपया ले रहे है। दो करोड़ की छूट आपने दी है। भाराब के मुकाबले आप टुथ पेस्ट और दुसरी चीजों को खराब मानते है इसलिए टुथपेस्ट पर टैक्स लगाया है। आपकी सरकार भाराब पिलाने वालों को प्रोत्साहन दे रही है और यह प्रोत्साहन किसी पीने वाले को नहीं दिया जा रहा है बल्कि उन को दिया जा रहा है जो बीच में देकर जाते है। कमि र्यिल डीनेचर्ड सपिरिट से 1981–82 में आपको 64.82 लाख रूपए की आमदनी थी लेकिन 1983–84 में सिर्फ 22 लाख रूपया ले रहे है। अगर आप 64.82 लाख रूपया ही वसूल कर लेते तो आपको दूसरे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा अगर आप ठीक से टैक्स की रिकवरी कर लें तो भी टैक्स न लगाने की समस्या हल हो सकती है। आपको पता होगा यह पोजी ान आपकी सरकार आने के बाद हुई है। पिछले सयै ान में भी आप फाइनैंस मिनिस्टर थे । आपको मालूम है कि एक सिनेमा घर पर रेड हुआ और यह साबित हो गया था कि बगैर टैक्स लगाए टिकट बेची जा रही है। लेकिन एक ान कुछ नहीं हुआ। उसका कोई ईलाज नहीं हुआ क्योंकि आपके मंत्रीगण उसके साथ भाामिल है। कृपया करके यही काम कर लीजिए आपको और टैक्स लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। चेयरमैन साहब, बडे बडे पूंजीपतियों को राहत दी जा रही है।

भाूगरकेन पर टैक्स कम करके हरियाणा के सब से बड़े पूंजीपति श्री डी0डी0 पुरी को 75 लाख रूपए की छूट दी गई है। चेयरमैन साहब, इसी प्रकार जिंदल ग्रुप है। बीस साल पहले यह बहुत ही साधारण आदमी था और आज वह बहुत बड़ा आदमी बन गया है। एक एस0डी0ओ0 ने थोड़ी ईमानदारी दिखलाई। उनकी बिजली की चैकिंग की और दो लाख रूपए से सात लाख रूपए का बिल हो गया लेकिन ऐसा करने का नतीजा क्या हुआ। लूपहोल तो बंद हो गया लेकिन उस एस0डी0ओ0 के खिलाफ एक्स0ई0एन0 ने ि ाकायत की ओर उसको वहां से बदल दिया गया। भाम ोर सिंह की क्या मजबूरी थी, यह तो इनको ही पता होगा, लेकिन ऐसे ईमानदार आफिसर को यह प्रोटैक्ट नहीं कर पाए। इनकी खुद की मजबूरी है। चौधरी भजनलाल लगे हुए है कि किसी तरह से इनकी पैटी ान कामयाब करा दें। ये अपने डिपार्टमैंट की देखभाल कैसे कर सकते है? चेयरमैन साहब मैं एक बात और बताना चाहता हूं । एक एंफोंसमैंट इंस्पैक्टर बलवान सिंह ने बीस बाईस फैक्टरीज को चैक किया। उसने दस लाख का सरचार्ज लगाया। कुछ दिनों के बाद एक इंडस्ट्रियलिस्ट चानन मल बंसल के घर पर पंचायत हुई और तीसरे दिन के अंदर उसकी हिसार से ट्रांसफर के आर्डर आ गए। क्या यह इस प्रदे ा के लिए भार्म की बात नहीं है। हरियाणा के अंदर चेयरमैन साहब, मजदूरों के साथ जुल्म हो रहा है। हिसार में जिंदल फैक्टरी है। उस फैक्टरी के गेट बंद कर दिए गए है। दो बंदूक धारियों को गेट पर खड़ा कर दिया गया और मजदूरों को लोहे की छड़ों से पीटा गया।

चेयरमैन साहब, वहां पर लेबर यूनियन को रिकगनाईज नहीं किया जा रहा है क्योंकि मंथली रूपया मिल जाता हैं इनकी मजबूरी है। चेयरमैन साहब, जो मैंने बात बताई है उसके बारे में मुख्य मंत्री के पास कम्पलेंट आई लेकिन कुछ नहीं किया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि इनकों कुछ काम करना चाहिए। चेयरमैन साहब स्टेट के अंदर वर्कर्ज यूनियन का काफी हंगामा रहा। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने बड़ी डिटेल्ड कम्पलेंट मंत्री जी को और मुख्य मंत्री को दी। मुख्य मंत्री जी ने तो आंख का बहाना बना लिया। मैं कहना चाहता हूं कि दूसरी आंख से भी तो वे काम करते हैं। अगर मान भी लिया जाए कि मुख्य मंत्री जी की मजबूरी थी तो दूसरे मंत्री जी की क्या मजबूरी थी। कुछ समय निकाल कर इस काम में लगा लेते। चेयरमैन साहब मैं कहना चाहता हूं कि अगर डिपार्टमैंट को ठीक करने की कोि ा ा करें तो प्रांत का काफी भला हो सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी मजबूरिया है।

चेयरमैन साहब, अब आप पुलिस को ही ले लीजिएगा। परसों की बात है अखबार में भी आया है कि कुछ बदमा ाों ने एक ए0एस0आई0 को मार दिया है, लेकिन उन बदमा ाों को कोई पूदने वाला नहीं हैं एक और बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। पटौदी के एक एस0एच0ओ0 को करप ान के केस में पकड़ लिया गया और उसके खिलाफ जिस डी0एस0पी0 ने कार्यवाही की, बजाये इसके कि उस एस0एच0ओ0 के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता, उल्टा उसी डी0एस0पी0 के खिलाफ कार्यवाही की, बजाये

इसके कि उस एस0एच0ओ के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता उल्टा डी0एस0पी0 के खिलाफ कार्यवाही चालू की गई क्योंकि वह एक वि ोश जाति के साथ ताल्लुक रखता था। मामला यहां तक आ पहुंचा कि भाायद वह डी0एस0पी0 अपनी नौकरी से भी हाथ ने धो बैठे। वह बेचारा डी0एस0पी0 इसी चक मे फिर रहा है। दूसरे इसका भाई लोकदल का प्रधान है इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही उल्टी चल पड़ी, हालांकि वह ईमानदारी से काम कर रहा है। इसी तरह से मैं आपको इस सरकार के ऐफीि ाएंट मिनिस्टर्ज की बात भी बतलाना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, मैंने एक मंत्री जी से रिकवैस्ट की कि फलां फलां सरपंच है उसको नाजायत तौर पर सस्पैंड कर रखा है। इनके इलैक ान भी भाायद, चेयरमैन साहब दोबारा हो जाएं और वह जीत कर दोबारा भी आ जाएगा। मैंने कहा कि उस सरपंच को आप बहाल कर दीजियेगा। आगे से मंत्री महोदय मुझे यह कहने लगे कि आपकी कौन सी पार्टी है? मैंने अपनी पार्टी का नाम बता दिया। चेयरमैन साहब, मुझे यह सुनकर बड़ा दु:ख हुआ कि ऐसे ऐसे मिनिस्टर्ज भी है जिनको इस हाउस में रहते हुए मैम्बर्ज के बारे में यह नहीं मालूम कि कौन–कौन मैम्बर किस किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। यह सोचकर चलना कि यह आदमी फलां पार्टी से ताल्लुक रखता है, इसका काम करना है या नहीं और यह आदमी हमारी पार्टी से ताल्लुक रखता है, इसलिए इसका काम कर दिया जाए। यह इस सरकार के मिनिस्टर के सोचने का स्तर है, सोचने का नजरियां है। आप इस बात से इनके स्तर का खुद भी अंदाजा

लगा सकते है। इसके साथ–साथ चेयरमैन साहब, मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार बहुत सारे नाजायज खर्चे कर रही है। इस वक्त हमारे कितने बड़े–बड़े अहम प्रोजैक्टस चल रहे है लेकिन कोई भी प्रोजैक्ट अभी तक सिरे नहीं चढ पाया है। आप नाथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट को ही ले लीजियेगा। आजतक उसकी क्लीयरैंस सैंटर से नहीं हुई है। चेयरमैन साहब, अगर हम अपने प्रांत की तरक्की चाहते है तो हमें यहां पर इंडस्ट्रीज को बढावा देना चाहिए और इंडस्ट्रीज को बढावा देने के लिए इलैक्ट्रीसिटी को पूरी तरह से जनरे ान करना चाहिए।

इससे आगे चेयरमैन साहब, मैं एक बात और बताना चाहता हूं। सरकार ने एक नया फारैस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाया है और उसका चेयरमैन भी इन्होंने अपना चहेता लगाया है, नाम तो उनका नहीं लेना चाहता हूं कि जितनी कारपोरे ानज है वे सभी पहले से ही घाटे में चल रही है। न जाने कितने प्रोजैक्टस कितने प्लांटस पहले से ही चल रहे है और कितने और जुटाने का प्रावधान सरकार कर रही है। मेरा यह कहना है कि जो प्रोजैक्टस और प्लांटस पहले से ही चल रहे है, वे तो पूरी तरह से चल नही ंरहे है और ये नये प्रोजैक्टस लगाने जा रहे है, यह तरीका ठीक नहीं है यूं ही सरकार फिजूल का खर्चा कर रही है। सरकार को पहले चल रहे प्रोजैक्टस की तरफ ही सारा ध्यान देना चाहिए।

चेयरमैन साहब, हांसी के अंदर एक धागे की मिल है उस मिल की रैपुटे ान भी अच्छी है। म ीनरी भी बहुत अच्छी है और काम भी वह बहुत अच्छा कर रही थी लेकिन जब से भजन लाल जी ने उसमें दखल अंदाजी करनी भुरू की है तब से उस प्लांट का ना ा हो गया है। सरकार का काम तो आजकल ला एंड आर्डर को देखने का नहीं रहा, बल्कि व्यापार देखने का ही रह गया है। व्यापार में जाने के बाद यह सरकार ला एंड आर्डर को तो बिल्कुल ही भूल गई है। यह सरकार तो व्यापार के सिर पर ही टिकी हुई है।

अब इसके बाद मैं हिसार के बारे में भी कुछ रो ानी डालूंगा। वहां पर पुलिस विभाग वालों से निजी काम लिये जा रहे है। स्टेट में ला एंड आर्डर तभी बेहतर होगा जबकि पुलिस को आप अकेला छोड़ देंगे। अगर आप पुलिस के बीच दखल–अंदाजी करेंगे तो काम बिगड़ैगा ही और पुलिस अपनी मर्जी से निश्पक्ष होकर काम नहीं कर सकेगी। आदमपुर के एस0ए0ओ0 को 10–11–82 को आई0जी0 साहब ने कम्पलसरी रिटायर कर दिया और उसको रिटायरमैंट के आर्डर दे दिये गये। मैं आपके द्वारा इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि एस0एच0ओ0 ठाकुर दास को 10–11–82 को कम्पलसरी रिटायर करदिया गया। चेयरमैन साहब, उसे कम्पलसरी रिटायरमैंट के आर्डर बकायदा रपट नम्बर 17, दिनांक 10–11–82 के आधार पर दिये गये और वह उन आर्डरों को रिसीव किये बगैर भागा भागा मुख्य मंत्री साहब के

पास आया। होता यह है कि उसको दोबारा एक्टैं ान देकर यह आर्डर दे दिये जाते है कि टिल फरदर आर्डर वह कंटीन्यू करे। आप देखें किसी को भी सही टाईम नहीं दिया जाता रहा हैं । इस सरकार के वक्त में टिल फरदर आर्डर की तरह के आर्डर्ज होते है। ऐक्सटैन ान तो उस आदमी को दे दिया लेकिन रूलज की उलंघना की गई। किसी आदमी की ट्रांसफर हो जाए, वह तो विद होल्ड हो सकती है लेकिन अगर किसी को सेवा से निवृत कर दिया जाए तो उसे कौन से कानून के तहत ऐक्सटें ान दे सकते है? रीइंस्टेट हो जाए तो भी ठीक है लेकिन इस आदमी को तो रिटायर कर दिया गया था इसे कैस एक्सटैं ान मिल सकती थी? इस तरह कानून की धज्जियां इस सरकार के वक्त में उड़ायी जा रही है। (घंटी) चेयरमैन साहब, मैं एक दो बातें ही कहकर समाप्त करूंगा।

चेयमैन साहब, आदमपुर का एक आदमी पूनप चंद है जिसने इलैक ान में भजन लाल की मुखालफित की थी। इन्होंने उसको अपने घर में बुलाया लेकिन वह नहीं आया उसने भजन लाल के पास जाने से इंकार कर दिया। उस आदमी को गधे पर बैठाकर जलूस निकाला गया, यह इन्होंने कितनी गलत बात की? (ोम भोम की आवाजें) उस पर झूठा मुकदमा बनाकर उसका चालान किया गया। मजिस्ट्रेट ने उसका जुडीि ायल रिमांड कर दिया। उसके बाद भी मुख्य मंत्री महोदय जी को तसल्ली नहीं

हुई, यह कितने खेद की बात है?..... (ाोर व व्यवधान)

Mr. Chairman: Whatever has been said about 'Judiciary' should be expunged.

श्री कंवल सिंहः चेयरमैन साहब,.....(ाोर व व्यवधान)

Mr. Chairman: This may also be expunged.

श्री कंवल सिंहः .....(ाोर)

Mr. Chairman: Since it has no relevancy with the budge. it may be expunged.

श्री सागर राम गुप्ताः चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। क्या हम कांग्रेस पार्टी वालों को इस बात की सजा दी जा रही है कि हम डिसिप्लंड है?..... (ाोर एवं व्यवधान)

(इस समय कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

चेयरमैनः अब चौधरी निर्मल सिंह जी बोलेंगे।

श्रीमती चंद्रावतीः चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। चेयरमैन साहब, जो बात इनके मन में आ जाती है उसके बारे में कह देते है कि इसको एक्सपंज कर दिया जाए। एक्सपंज करने के लिये हमारे रूल्ज बने हुए है। आप तो बहुत

पुराने पार्लियामैंटेरियन है, हर चीज एक्सपंज नहीं हो सकती। जुडि ियरी का हम सबसे ज्यादा रिगार्ड करते है। ऐसी बात कहने में क्या हर्ज है? यह बात अनपार्लियामैटरी या डैरोगेटरी नहीं है। (ाोर)

Mr. Chairman: Then what does he mean to say by this? (Noise & Interruptions). Please take you seat and let the hon. Member hav his say.

श्री निर्मल सिंह (नग्गल): चेयरमैन साहब, हमारे फाइनैंस मिनिस्टर चौधरी कटार सिंह जी ने जो बजट पे ा किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं ऐसे अच्छे बजट के लिये कटार सिंह जी को मुबारिकबाद देता हूं। इन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स न लगाते हुए एक बहुत ही सुंदर बजट पे ा किया है। इसके लिये इनकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। विरोधी पक्ष के भाइयों ने, हमारे वित्त मंत्री जी जो कि एक सुलझे हुए भाख्स है, को कटार सिंह की संज्ञा दे दी। मैं तो यह कहता हूं कि जैसे ये सुलझे हुए आदमी है इन्होंने वैसा ही बजट पे ा किया है। सभापति जी, मैंन यह सुना था और यह सच भी है कि इस सदन की कोई गरिमा होती है, मान होता है लेकिन यहां पर देखने में आया कि विरोधी पक्ष के भाइयों ने किस तरह से सदन की गरिमा की धज्जियां उड़ाई है।..... यह बड़ी खेद की बात है। (ाोर)

श्री बीरेंद्र सिंहः चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। चेयरमैन साहब, एक्पंज करने वाली बात तो यह है।..... .....के रिमार्कस एक्सपंज होने चाहिए। (ाोर) चेयरमैन साहब मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये रिमार्कस गुड टेस्ट में है? स्पीकर साहब, सरदार तारा सिंह जी ने कल जब मैं बोल रहा था तो किसी रिमार्कस के बारे में रूलिंग दी थी कि यह एक्सपंज कर दिया जाए क्योंकि वह गुड टेस्ट में नहीं था। इसी प्रकार इन्होंने जो यह कहा है कि विरोधी सदस्यों ने सारे सदन को..... .बना दिया, क्या यह गुड टेस्ट में है? आप इस पर कैटेगरीकल रूलिंग दे। यह चीज रिकार्ड पर आ जाए कि आप इसको कार्यवाही में रखना चाहते है अगर नहीं तो आप इसको एक्सपंज करवाएं।

श्री मंगल सैनः चेयरमैन साहब, आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या सदन में कोई आनरेबल मैम्बर इस सदन को..... ...कह सकता है? (ाोर)

श्री निहाल सिंहः चेयरमैन साहब, सदन को..... .....कहना अच्छे टेस्ट में नहीं है। अगर हम इनको कहें कि आप धर्म ााला में बैठे हो, कभी जाएं कभी आएं तो क्या यह अच्छी बात होगी। इसलिये आप इस पर रूलिंग दें। (ाोर)

Mr. Chariman: He has said it is just like a dramatisation.

श्री निर्मल सिंहः चेयरमैन साहब, मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि ये खिलवाड़ कर रहे है। (ाोर)

श्रीमती चंद्रावतीः चेयरमैन साहब, यह विधान सभा का अपमान है। (ाोर)

श्री निर्मल सिंहः चेयरमैन साहब, मैंने यह बात कई बार नोट की है कि यहां पर कई मैम्बर सिर्फ हीरो बनने के लिये ऐसी बात कहते है। (ाोर)

श्री सभापतिः निर्मल सिंह जी, आप इन बातों को छोड़ियें और बजट पर बोलिये। (ाोर)

श्री हीरा नंद आर्यः चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं। जैसे मेरे दूसरे साथियों ने भी प्रार्थना की, क्या विधान सभा को कोई सदस्य.....कह सकता है क्या यह सारे सदन का अपमान नहीं है? (ाोर)

Mr. Chairman: You have also been speaking in the lighter tone. He has said that it was a dramatisation (Noise & Interruptions).

श्री बीरेंद्र सिंहः चेयरमैन साहब, हम आपकी कैटेगरीकल रूलिंग चाहते है कि क्या आप इन भाब्दों को पब्लि ा करने की इजाजत देंगे? (ाोर)

Mr. Chairman: These words were spoken in a loghter mood. (Noise & Interruptions).

Shri Verender Singh: Do we understand that you have allowed, Sir?

श्री निर्मल सिंहः सभापति जी, यह बड़ी हैरानी की बात है कि ये सदन में ऐसा माहोल पैदा कर रहे है। (ाोर)

श्री हीरा नंद आर्यः चेयरमैन साहब, आपने इनको ये बातें कहने की इजाजत दे दी। ऐसे तो ये किसी की भी पगड़ी उछाल देंगे। यह बात कहां तक भाोभा देती हैं? (ाोर)

Mr. Chairman: Mr. Nirmal Singh, you also keep restrain on saying such words (Noise & Interruptions).

श्री निर्मल सिंहः चेयरमैन साहब, मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जो हम रूलिंग पार्टी के लोग है, को और अपोजी ान के लोगों को अपनी मान–मर्यादाओं और परम्पराओं से बाहर नहीं जाना चाहिए। (ाोर)

Mr. Chairman: Please do not repeat those words. You will take only five minutes.

श्री निर्मल सिंहः चेयरमैन साहब, हमारे विरोधी पद के सदस्यों ने बजट के बारे में बहुत बातें कहीं और नाराजगी जाहिर की।

श्री सभापतिः आपका समय हो गया है इसलिये अब आप वांइड–अप करें।

श्री निर्मल सिंहः सभापति जी, मैं तो बिल्कुल बोला ही नहीं हूं। ये लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे है और बोलने नहीं दे रहे है। चेयरमैन साहब, बजट में जो 57.13 करोड़ रूपये का घाटा दिखाया गया है, उस पर विरोधी साथियों ने बहुत कुछ बोला। मैं तो यह कहता हूं कि सरकार को इस बात का कैडिट जाना चाहिए कि उसने किसी लम्बे चौड़े टैक्स के बिना यह बजट पे ा किया है इस सरकार की नीयत काम करने की है, तभी यह घाटा दिखाया गया है। इसमें 31 करोड़ रूपये खुले छोड़ दिये गये है। जिस सरकार की नीयत काम करने की न हो वह क्या खर्च करेगी और क्या घाटा दिखाएगी। हमारा पिछला प्लान 326 करोड़ रूपये का था लेकिन अब उसको बढ़ा कर 407 करोड़ रूपये का कर दिया है जो कि 27 प्रति ात के लगभग बढौतरी है। इससे जाहिर होता है कि हमारी सरकार की नये प्रोजैक्टस को बहुत जल्द पूरा करने की नीयत है। यह बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा मैं अपने विरोधी पक्ष के भाइयों को और बातें भी बताना चाहता हूं कि जोकि रिकार्ड पर है। उन्हें ये भी जानते है और हम भी जानते है। सन् 66 में जब हरियाणा बना, उस वक्त हरियाणा का हर निवासी जानता था कि हरियाणा की क्या हालत थी। लोग यहां तक चर्चा करते थे कि हरियाणा सरकार अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को तनखवाह तक नहीं दे सकेगी। 1966 और 1977 में हरियाणा सारे हिंदुस्तान में पर केपिटा इंकम के हिसाब से दूसरे नम्बर पर था। सभापति जी 1977 के बाद दो साल के लिये जब इनकी हकूमत आई तो इन्होंने सारी स्टेट के कार्यकम को

बिगाड़ दिया। उस समय स्टेट पर–कैपिटा इंकम के हिसाब से सातवें नम्बर पर चली गई। यह विरोधी भाइयों की, इनके टाईम की कारगुजारी है। किसानों का रोना यह था कि उनका गन्ना चार रूपये किवंटल के हिसाब से बिका। यह कितने अफसोस की बात है। किसानों ने अपने खेत में गन्ना जलाया इसकी हजारों मिसालें मिल सकती है। सभापति जी, उसके बाद एक बात और है कि 1966 में हरियाणा के पास 27,589 ट्यूबवैल्ज थे। 1977 में 1,35,60 के करीब हो गये थे और आज दो लाख से भी ज्यादा टयूबवैल्ज है। इसी तरह से 1966 में जब 27,589 टयूबवैल्ज थे बिजली की पर–कैपिटा खपत 57 यूनिट थी। इसी तरह से 1977 में जब 1,35,600 टयूबवैल्ज थे बिजली की पर–कैपिटा खपत 113 यूनिट थी। सभापति महोदय, हमारी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के मजबूत नेतृत्व की बदोलत हरियाणा ने इतनी तरक्की की है। इसके अलाव मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बीस सूत्री प्रोग्राम या अन्य प्रोग्राम जो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार के पास है, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम है। उन प्रोग्राम के माध्यम से गरीब जनता की बहुत भलाई होगी और बेरोजगारों को बहुत लाभ होगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पानीपत और फरीदाबाद के जो थर्मल प्लांटस है उनमें जो म ाीनरी लगी हुई है वे कई बार खराब हो जाती है जिसके कारण बिजली उत्पादन में बाधा पड़ती है। उन थर्मल प्लांटस में जो म ाीनरी लगी हुई है उनको मद्देनजर रखते हुए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार

यमुनानगर में जो थर्मल प्लाट लगाने जा रही है, उसके लिए म ाीनरी इम्पोर्ट करें ताकि म ाीन अच्छी लगे और जल्दी खराब न हो। पानीपत व फरीदाबाद के थर्मल प्लांटस में जो म ाीनरी लगी हुई है वह हर रोज खराब रहती है जिसके कारण बिजली उत्पादन में बाधा पड़ती है और किसानों को बिजली पूरी नहीं मिल पाती है। यदि यमुनानगर के थर्मल प्लांट में अच्छी म ाीने लगाई जाएंगी तो बिजली उत्पादन में बाधा नहीं पड़ेगी। यदि हमारे थर्मल प्लांटस ज्यादा बिजली का उत्पादन करेंगे तो हमें पड़ौसी राज्यों से बिजली नहीं लेनी पड़ेगी। हमारे थर्मल प्लांटस में बिजली का उत्पादन अच्छा न होने के कारण हमें पड़ौसी राज्यों से बिजली लेनी पड़ती है जोकि काफी महंगी पड़ती हैं। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि यमुनानगर में जो थर्मल प्लांट लगाया जा रहा है उसके लिए म ाीनरी इम्पोर्ट की जाए ताकि बिजली उत्पादन में बाधा न पड़े। सभापति महोदय, अब मैं एस0वाई0एल0 नहर के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। एस0वाई0एल0 नहर के पानी के लिये हरियाणा का बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक यह आ ाा लगाए बैठा है कि एस0वाई0एल0 नहर का पानी हरियाणा में आएगा और हमारे यहां खु ाहाली आएगी। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा और अपोजी ान से भी दरख्वास्त करूंगा कि पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठ कर, एकजुट होकर उस नहर के काम को पूरा करने में लग जाएं और जितना जल्दी हो, इस काम को पूरा करें ताकि हरियाणा प्रांत के लोगों को उस नहर का पानी मिल सके। सभापति

महोदय, पंजाब के पास लगभग एक करोड़ सात लाख एकड़ भूमि सिंचाई करने योग्य है और हरियाणा के पास 97 लाख एकड़ भूमि सिंचाई करने योग्य है। हरियाणा में एस0वाई0एल0 नहर का पानी आने के बाद हरियाणा के लोग पंजाब से भी ज्यादा पैदावार करके दिखाएंगे। इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि जो लाइन लौसिज है, वे 30–35 परसैंट के करीब है। इन लाइन लौसिज की रिस्पोंसीबिलिटी जिन–जिन अधिकारियों के जिम्मे है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन लाइन लौसिज की तरफ भी ध्यान दिया जाए। सभापति महोदय, अम्बाला जिले की भूमि बहुत उपजाऊ है लेकिन देखने में यह आया है कि अम्बाला जिलें में इरीगे ान के लिए पानी की प्रौपर व्यवस्था नहीं है इसलिए अम्बाला जिला कृशि उत्पादन में बहुत पीछे है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अम्बाला जिले में इरीगे ान के लिए पानी की प्रौपर व्यवस्था की जाए। (ाोर एवं विघ्न)

प्रौफेसर सम्पत सिंहः सभापति जी, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अभी चौधरी निर्मल सिंह जी अपनी सरकार की बहुत प्र ांसा कर रहे थे और कह रहे थे कि फलां टाईम में इतने ट्यूबवैल्ज थे और पर कैपिटा बिजली कर इतनी यूनिटस थी। मैं इनको बताना चाहता हूं कि इनके हल्के के लडाना गांव में आज से सात साल पहले किसी मंत्री ने एक भवन की कंस्ट्रक ान के लिए पत्थर रखा था। आज उस पत्थर की यह हालत है कि

उसके चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए है और उस पर कुत्ते पे ाब कर रहे हैं। मेरे पास उस जगह की फोटो है जो मैंने चौधरी निर्मल सिंह जी को दिखा दी है। (ोर एवं विघ्न)

श्री निर्मल सिंहः सभापति महोदय, प्रोफैसर सिंह यह तस्वीर पता नहीं कहां से उठाकर लाए है और पता नहीं किस जगह की है। मैं अपने हल्के में जाता रहता हूं, मुझे तो इस बारे में किसी ने नहीं बताया। ये पता नहीं यह तस्वीर कहां से उठा कर लाए है। इनको कम से कम यह तो बताना चाहिए कि फलां पेपर में यह तस्वीर छपी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एस0वाई0एल0 नहर का पानी अम्बाला जिले में, यदि बहाव से नहीं लग सकता तो लिफ्ट इरीगे ान स्कीम लागू करो। लिफ्ट इरीगे ान स्कीम वहां बहुत कामयाब हो सकती है। लिफ्ट के जरिए अम्बाला जिले को एस0वाई0एल0 नहर का पानी दिया जा सकता है। इन भाब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपने फाइनैंस मिनिस्टर को मुबारिकबाद देता हूं और बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री निहाल सिंह (अटेली): चेयरमैन साहब, जो बजट पे ा किया गया है इस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, हमारे यहां एक धारणा सी बन गई है कि टैक्से ान तो प्री–बजट होता है और स्कीमज पोस्ट बजट होती है जो कि बजट प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। इन्होंने बसों का भाड़ा भी पहले बढ़ा दिया और डीजल का रेट भी पहले बढ़ा दिया जोकि

बजट में जिक्र नहीं किया गया है, वे बाद में सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस के जरिए आएंगी, यह भी बजट प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। चेयरमैन साहब, मैं एक बात जरूर कहूंगा, चौधरी कटार सिंह जी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत भले आदमी है। मुझे इन पर रहम आता है क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने इनको फाइनैंस मिनिस्टर बना दिया। लेनि इनको फाइनैंस के बारे में इतना ज्ञान नहीं हैं। इनसे पहले चौधरी खुर ाीद अहमद जी फाइनैंस मिनिस्टर हुआ करते थे वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दफा हम दोनों को इक्ट्ठे ही सफर करने का मौका मिला। हम एक टैक्सी में जा रहे थे तो रास्ते में हमें मंजिल से पहले ही उतरना पड़ गया। मैंने उनसे पूछा कि आप यहां क्यों उतर गए, उन्होंने कहा कि मैने टैक्सी का मीटर देख लिया है और मेरी जेब में उतने ही पैसें है जितने मीटर में आए है। इसलिए चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि चौधरी कटार सिंह जी बहुत नेक और भले आदमी है इनको अगर किसी दूसरे महकमें का मंत्री बना दिया जाता तो ये बहुत अच्छा काम करते और ज्यादा काम करते। चेयरमैन साहब, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहते हूं कि फाइनैंस डिपार्टमैंट में जितने भी आफिसर लगे हुए है, वे सारे महेंद्रगढ डिस्ट्रिक्ट के है। वे सारे आफिसर बहुत ईमानदार और हार्ड वर्कर है, उन्होंने बजट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि फाईनैंस का महकमा श्री सागर राम गुप्ता को सौंप दिया जाता तो बजट पे ा करने में कोई दिक्कत

न होती। ये फाइनैंस का महकमा बहुत अच्छी तरह से संभाल लेते।

चेयरमैन साहब, इसके अलावा मैं ट्रांसफर्ज के बारे में कहना चाहता हूं। इस सरकार की जो ट्रांसफर पालिसी है, उसमें सरकार कर्मचारियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टीचर्ज की जो ट्रांसफर की जाती है, वह वैके ांज में होनी चाहिए। यदि वैके ांज के दौरान उनकी ट्रांसफर कर दी जाए तो न वे गैरहाजिर होगे की पालिसी है उससे एजुके ान पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है । इसके साथ साथ मै यह भी कहना चाहता हूं कि टीचर्ज की ट्रसफर्ज की लिस्ट मंत्रियों के पास इस तरह से जाती है जिस तरह से रबी कहीं फसल तैयार होती है, क्यौंकि जब रबी की फसल तैयार हो जाती है तो किसान अनाज किकालने के लिए बहुत इन्तजार करता है और अपनी आमदनी के बारे में सोचता है। .....(ाोर एवं विघ्न)

Irrigbation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Sir, it is wild allegation and should be expunged.

Mr. Chairman: It can be replied at the appropriate time. Rao Nihal Singh ji, please resume your speech.

श्री निहाल सिंहः..... ..... चेयरमैन साहब,

सरकार के जितने भी सीनियर आफिसर है उनके पास हमारे मिनिस्टर्ज ट्रांसफर का नोट भेज दें कि यह ट्रांसफर कैंसिल करना है तो उस ट्रांसफर को कैंसिल कर दिया जाता है। वे आफिसर अपनी तरफ से कोई एनीसिएटिव नहीं लेते। इस तरह से ये ट्रांसफर्ज गलती होती है, इन पर चैक होनी चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक थानेदार, हवालदार या इंसपैक्टर की जब परमो ान हो तो उसको परमो ान के बाद उस कर्मचारी को उसी जिलें में नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार से नायब तहसीदार या तहसीलदार की जब परमे ान होती है और परमो ान होने के बाद जब वे तहसीलदार या एस0डी0एम0 लगे तो उनको भी दूसरी जगह लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरी श्रेणीयों में जो लोग काम करते है, जब उनकी परमो ान हो तो उनको भी दूसरे जिले में स्थानांत्रित कर देना चाहिए। क्योंकि जिस समय वे नायब तहसीदार या तहसीलदार या इंसपैक्टर या हवालदार होते है तो उनकी अपने इलाके के लोगों के साथ अच्छी तरह से जान पहचान हो जाती है। पुलिस वालों को तो पता होता है कि इलाके में कौन चोर है किसके पास कितना धन है इसलिए मेरी गुजारि ा है कि जब इनका परमो ान हो तो दूसरे जिले में लगा दिया जाये ताकि वे वहां पर निश्पक्ष होकर काम कर सकें। इसके अलावा, एक और बात कहना चाहता हूं। आजकल हाउस रैंट एलांउस, अगर मियां बीबी दोनों सर्विस में हो तो दोनों को दिया जाता है। इस संबंध में मेरा सरकार को सुझाव है कि टीचर और हैल्थ डिपार्टमैंट में जो कर्मचारी काम

करते है उनके कपल केसिज को देहात में लगाया जाना चाहिए। होता यह है कि कपल केस होने के कारण वे अच्छा स्टे ान भी चाहते है और हाउस रैंट अलाउंस भी लेते है। सरकार को इस पर पूरी गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, अगल बात मैं टैक्से ान के बारे में कहना चाहता हूं। आज इन्होंने सेल्ज टैक्स सात प्रति ात से आठ प्रति ात बढ़ा दिया है। इन्होंने एग्रीकल्चर पर भी मार्किट फीस एक प्रति ात लगा दी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो टैक्स इन्होंने पहले ही लगा रखे है यदि उनको ठीक प्रकार से वसूल करें तो और टैक्स लगाने की आव यकता नहीं है। आज मार्किट कमेटियों की तरफ से पूरी फीस इक्टठी नहीं की जा रही। आधे से भी ज्यादा केसिज का जानबूझ कर नोटिस नहीं लिया जाता। अगर ये सारी मार्किट कमेटीज की फीस इक्ट्ठी कर लें तो इनको और टैक्स नही ंलगाने पड़ेंगे।

सभापति महोदय, आज हमारा टौप हैवी एडमिनिस्ट्रे ान है। सरकार को इसे कम करना चाहिए। प्रधान मंत्री के बीस सूत्री कार्यक्रम का बार–बार इनकी तरफ से हवाला दिया जाता है। इस संबंध में मैं इनके नोटिस में लाना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री का बीस सूत्री कार्यक्रम में एक सूत्र यह होना चाहिए कि गैर–जरूरी खर्चें बंद किए जायें। यहां पर इन्होंने एक की काम के लिए कई कार्पोरे ान बनाई हुई है इनको कम करना चाहिए। मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि सोसल वैल्फेयर डिपार्टमैंट के अधीन

तीन कार्पोरे ान है एक हरियाणा इकोनोमिकली वीकर सैक ान कार्पोरे ान, एक ि ाड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासिज कार्पोरे ान तथा हरियाणा हरिजन कल्याण निगम। इन तीनों का काम सिर्फ लोन देना है और लोन वसूल करना है। यह सारा काम बैंकिग डिपार्टमैंट का सैल भी अच्छी तरह से कर सकता है। जब हम इनसे पूछते है कि आपने क्या काम किया तो ये कहते है कि हमने इतने करोड़ रूपये लोन दिया है और इतना लोन वापिस लिया है। इस संबंध में मेरा सरकार को सुझाव है कि सो ाल वैल्फेयर डिपार्टमैंट का काम वाइड होना चाहिए। सो ाल वैल्फेयर डिपार्टमैंट को एजूकेटिड पर्सन मुकर्रर करने चाहिए जो गांव में जा कर लोगों को सो ाल बाते बताएं और सो ाल वैल्फेयर की एक्टीविटीज से परिचित करवायें।

सभापति महोदय, इसी प्रकार एस0एस0एस0 बोर्ड के बारे में यहां पर खूब चर्चा चल रही है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आज एस0एस0एस0 बोर्ड के अंदर इन नौजवानों की कोई सुनवाई नहीं होती और न ही मैरिट के आधार पर सिलेक ान होती है, जिसके कारण नौजवानों में असंतोश बढ़ता जा रहा है। यदि इस बोर्ड में इसी प्रकार से काम चलता रहा तो हरियाणा का नौजवान गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जायेगा। फिर वह समाज के लिए, सोसायटी के लिए और एडमिनिस्ट्रे ान के लिए गलत साबित होगा। मैंने इस संबंध में पहले भी मुख्य मंत्री जी से कहा है कि एस0एस0एस0 बोर्ड का

चेयरमैन नान–औफि ियल होने की बजाये कोई आई0ए0एस0 ओफिसर होना चाहिए। आज दो साल के लिए कोई नान–ओफि ियल व्यक्ति बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया जाता है। वह जो भी इरगुलेरिटी करे, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। यदि कोई आई0ए0एस0 आफिसर इस बोर्ड का चेयरमैन होता तो वह यह ध्यान रखेगा कि उसे अभी पांच साल या दस साल और हरियाणा में सर्विस करनी है इसलिए वह कोई गलत काम करने से हमे ाा बचने की कोि ा ा करेगा। इसलिए मेरा सरकार से सुझाव है कि इस बोर्ड का चेयरमैन आई0ए0एस0 लगा दिया जाये और मैम्बर्ज बे ाक नान–ओफि ियल लगा लिये जाएं।

सभापति महोदय, हरियाणा के लोगों को अपनी ि ाकायतों के लिए चंडीगढ आना पड़ंता है हमारे हर जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट ग्रिवैंसिज कमेटियां बनी हैं। वे उतनी प्रभाव ााली नहीं है जितनी होनी चाहिए। लोगों को अपनी ि ाकायतों के बारे में चंडीगढ आना पड़ता है इन कमेटीज में अधिकतर मैम्बर रूलिंग पार्टी के होते है। यदि कोई अपनी ि ाकायत करना चाहे तो उसकी ि ाकायत पर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि इन्हीं का बहुमत होता है यही सुनने वाले है और यही कहने वाले है अगर कोई ि ाकायत करना चाहे तो वह कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन ग्रिवैंसिज कमेटियों में वेरियस पार्टियों के मैम्बरों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

सो ाल अदायरे के जो व्यक्ति है, उनको भी इन कमेटियों में बराबर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से लोन के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार किसानों को जब कोई लोन या सबसिडी देती है तो वह पूरी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। सबसिडी की रकम को बैंक के या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमैंट के कर्मचारी लोन देते है, वे किसानों तक सबसिडी का एक चौथाई हिस्सा भी पहुंचने नहीं देते। ज्यादातर पैसा बीच में ही खा लिया जाता है। सरकार की तरफ से जितना भी लोन किसानों को दिया जाये, उसके लिए एक लोकल लोगों की कमेटी बनाई जानी चाहिए लोकल लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस किस्म की अनेक ि ाकायतें आती है कि लोगों को पूरा लोन नहीं मिला। सरकार को मेरा सुझाव है कि लोन देने के मामले में जो गड़बड़ी होती है, उसको दूर करने की कोि ा ा करनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं अब रोडज के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे हरियाणा प्रांत की जो इंटर स्टेट सड़कें है उनकी बहुत ही खराब हालत है। पंजाब से या राजस्थान के साथ जो हमारी सड़कें जुड़ी हुई है यदि उनका आपस में मुकाबला किया जाये तो इनमें इतना इंतर नजर आयेगा जितना बंसी लाल और फूसा राम में है। जितना इन दोनौं के मुकाबले का फर्क है। उतना ही इन सड़कों का फर्क है। जब बंसी लाल के समय में हरियाणा से बाहर के लोग हरियाणा में दाखिल होते थे तो लोग

कहते थे 'जय बसी लाल की' इसी प्रकार एक दिन हम राजस्थान से आ रहे थे। जब हम जयपुर से नारनोल में दाखिल हुए तो हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे थे, वे कहने लगे 'जय फूसा राम की'। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज उन सड़कों की हालत बहुत खराब है। उनकी मैंटीनैंस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसलिए इस संबंध में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन सड़कों की मुरम्मत भीघ्रता ीघ्र की जाये। इसके इलावा महेंद्रगढ के लोग कहते है कि महेंद्रगढ तो यूनियन टैरिटरी है **(12.00बजे)** क्योंकि यहां पर यूनियन गवर्नमैंट का हुक्म चलता है। (घंटी) चेयरमैन साहब मैं एक मिनट में खत्म करता हूं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितन सरपंच सस्पैंड किये है, इतने किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सस्पैंड नहीं हुए है। किस ढंग से सस्पैंड किये है, इसकी मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूं। एक सरपंच जिसने अपनी जेब से अढ़ाई लाख रूपया खर्च किया है। सारे गांव का चूल्हा टैक्स जो पिछले आठ सालों का बनता था, वह सारे का सारा उस सरपंच ने अपनी जेब से भरा है क्योंकि इस गांव की अठारह हजार की आबादी इस टैक्स को देने की हैसियत नहीं रखती थी। गांव के ग्रामसेवक से रजिस्टर में डबल एंटरी करवाकर इस सरपंच के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया और मुअतल करवा दिया। जिस सरपंच ने गांव की भलाई के लिए अढाई लाख रूपया अपनी जेब से खर्च किया हो उसके खिलाफ केस बनाकर सस्पैंड कर दिया। हमने कहा था कि इसका कोई कसूर नहीं है, इसकों बहाल किया जाए, लेकिन हमारी एक न

सुनी। चेयरमैन साहब, गवर्नमैंट आफ इंडिया से मिनिस्टरी आफ एग्रीकल्चर के सैक्रेटरी यहां पर आये और कई सरपंचों को सस्पैंड करवा दिया। यह कहा गया है कि इस सरपंच ने एन0आर0पी0 का पैसा गबन किया है, लेकिन जब सरपंच से पूछा गया तो उसने कहा कि उसने एन0आर0पी0 का एक पैसा भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी सस्पैंड कर दिया। मिनिस्टरी आफ एग्रीकल्चर के सैक्रेटरी ने दिल्ली जाकर डी0ओ0 लिखा कि इस सरपंच को सस्पैंड किया जाए। अगर उनसे पूछा जाए कि मिनिस्टरी आफ एग्रीकल्चर के सैक्रेटरी किस तरह हरियाणा की पंचायत के सरपंच को सस्पैंड कर सकता है, कैसे सस्पैंड करने के लिए आथोराइज्ड है तो क्या जवाब होगा? (घंटी) मैं हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस तरह से बहुत से सरपंच पोलिटिकल विक्टेमाईजे ान की वजह से सस्पैंड किये जा रहे है। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री सभापतिः अब श्री इंद्रजीत जी बोलेंगे।

श्री बीरेंद्र सिंहः चेयरमैन साहब, आपने आज हमारी पार्टी के किसी मैम्बर को बोलने के लिए एक मिनट का टाईम भी नहीं दिया है। लोकदल को टाईम दिया है, कांग्रेस पार्टी के मैम्बरों को टाईम दिया है लेकिन हमारी पार्टी को नहीं दिया है। (व्यवधान)

श्री सभापतिः आपको भी टाईम मिलेगा। (व्यवधान)

श्री बीरेंद्र सिंहः कब मिलेगा जी। पहले मुझे बोलने दें, इसके बाद ये बाल लेंगे।

श्री सभापतिः ठीक है, आपको भी टाईम मिलेगा लेकिन इनके बाद मिलेगा।

श्री बीरेंद्र सिंहः आपने क्या काइटेरिया अपना रखा है? आपने हमारी पार्टी के किसी भी मैम्बर को आज बोलने का टाईम नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी को भी टाईम दे दिया है, लोक दल को भी दे दिया लेकिन हमें नहीं दिया।

Mr. Chairman: Speech on the budget is a continuous process and your members have already spoken. लोकदल वालो की स्ट्रैंथ आपकी पार्टी से डबल है। (व्यवधान) पहले आप श्री इंद्रजीत सिंह को बोलने दीजिए, मैं इनका नाम बोल चुका हूं। इसके बाद आप बोल लेना।

राव इंद्रजीत सिंह (जाटूसाना): चेयरमैन साहब, राव निहाल सिंह ने अपनी स्पीच में सरपंच के बारे में जिक्र किया था उसके बारे में सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि किसी भी सरपंच को आपसी रंजि ा की वजह से न मैंने सस्पैंड करवाया है और न ही मेरे पिता जी ने किया है। अगर कोई सरपंच सस्पैंड हुआ है तो वह अपने कारनामें की वजह से सस्पैंड हुआ है। चेयरमैन साहब, मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले दो दिनों से बजट पर चर्चा चल रही है और चर्चा करते समय खस तौर पर 20–प्वायंट प्रोग्राम पर सदस्यों ने कई बातें कहीं।

बार–बार अपोजी ान के भाइयों की तरफ से यह बात आई कि बीस सूत्रीय प्रोग्राम को जानते भी हो या नही। मैं आपकी मारफत अपने भाईयों को बताना चाहता हूं कि जो भी प्रोग्राम हरियाणा प्रांत के अंदर चल रहा है, यानी जो भी प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान में और हरियाणा में भुरू किए है वे सब के सब प्लान के मुताबिक किये हैं। हिंदुस्तान आज डिवैल्पिंग ने ांज की लाईन में आता है और सबसे ज्यादा प्रगति ील दे ा कहलाया जाता है। इस हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा प्रगति ील प्रांत है तो वह हरियाणा प्रांत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को सारा दे ा मानता है। यह स्थिति कैसे आई? इसका कारण यह है कि हरियाणा प्रांत के विकास के कार्य प्रोग्राम के मुताबिक किये गये। 1977 से 1980 तक तीन साल के अर्से को छोड़कर बाकी सब सालों में जो भी कार्य हुआ है, वह प्रोग्राम के मुताबिक, प्लान के मुताबिक हुआ है। श्रीमती इंदिरा गांधी की लीडर ाप में इस प्रांत ने भारी तरक्की की है इसकी पुश्टि के लिए मैं आपको कुछ फिगर देना चाहूंगा।

चेयरमैन साहब, 1980–81 में हमारा प्लान आउट–ले 246 करोड़ रूपये था, अगले साल 1981–82 में 288 करोड़ बढ़ा दिया और करंट ईयर 1982–83 के लिए जो मौजूदा साल चल रहा है, इसमें हमारा प्लान आउट–ले 319 था और बाद में रिवाईज करके 332 करोड़ का प्लान आउट–ले बनाया गया। अगले साल के लिए, जैसे कि मुझे बताया गया है, 406 करोड़

रूपया अगले साल के अंदर खर्च किया जाएगा। इसी तरह से पांचवी फाईव ईयर प्लान में प्लान आउट ले 600 करोड़ था लेकिन अब 1980 से 1985 तक की छठी 5 पंचवर्शिय योजना के लिए 1800 करोड़ रूपया प्लान डिवैल्पमैंट के ऊपर खर्च किया जाएगा। चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से अपोजी ान साईड को बताना चाहता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम की बात रटने से कोई बात नहीं बनती। अगर आपकों इसके अंदर वि वास हो तब बात बनेगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ट्रेजरी बैंचिज के जो भई बजट पर बोले है, उनको हमारी सरकार पर और बीस सूत्री कार्यक्रम पर पूरा वि वास है। इन्होंने खुले तौर से एक्सैप्ट किया है। अगली पांच साला योजना के अंदर किस तरह से हरियाणा प्रांत तरक्की करेगा, इस बात को जानने के लिए सबसे पहले आपको बीस सूत्री कार्यक्रम को जानना होगा। अपोजी ान बैंचिज के दो चार भाई, अगर इस कार्यक्रम को जानते है और वि वास रखते है तो इधर आ जाएं हमारे चौधरी साहब दिल के खुले आदमी है, आपको भी एक्सैप्ट कर सकते है। पर वहां पर डिप्टी लीडर की जो पोजी ान मिली हुई है, वह यहां नहीं मिलेगी, जो आपकी असल जगह है, वह मिलेगी। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्रीमती चंद्रावतीः वहां तो आप ही फालतू हो रहे है।

राव इंद्रजीत सिंहः कांग्रेस पार्टी में अगर इधर उधर से छोटे मोटे आदमी आ जायेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। जो

लोग श्रीमती इंदिरा गांधी पर पूरा वि वास रखते है, उनको हम पूरी तरह एक्सैप्ट करने के लिए तैयार है। (व्यवधान) स्पीकर साहब, मैं आपकों कुछ आंकड़ें बता रहा था। इस प्लानिंग की वजह से 1979–80 में हमारी सालाना पर कैपिटा इंकम 1923 रूपये थी, 1980–81 में 2335 रूपये और 1981–82 में बढ़ कर 2574 रूपये तक पहुंच गई। यह पर–कैपिटा इंकम कैसे इंक्रीज हुई? यह इंक्रीज डिवैल्पमैंट प्रोग्राम की वजह से हो रही है और अगर कोई यह कहे कि इन्फले ान की वजह से यह न्युट्रलाइज हो गयी है तो यह गलत बात है। आप 1971 की बैकग्राउंड को देखें। 1971 के रूपये की वैल्यु के मुताबिक जो मनी वैल्यु 1971 में थी उसके हिसाब से पर–कैपिटा इंकम 1979–80 में 957 रूपये थी। यह डिवैल्पमैंट के कारण बढ़ कर 1980–81 में 1051 रूपये हो गई है। सन् 1981–82 में भी बढ़ी और पर–कैपिटा इंकम 1074 रूपये तक हो गई। इससे साफ जाहिर है कि इतनी इन्फले ान होते हुए भी इन–इफैक्ट पर–कैपिटा इंकम और रूपये की बाइंग पावरप्लानिंग कीवजह से किसान की, बढ़ी ही है। आगे आने वाले सालों में पर–कैपिटा इंकम और भी बढेगी। अपोजी ान के भाइयों ने हमारी नीतियों और बजट के गुड प्वायंटस की ओर ध्यान नहीं दिया और बजट की बेतुकी मुखलफत करनी आरम्भ कर दी। आप पिछले तीन सालों के बजट को पढें तो उसमें पायेंगे कि तीन सालों में हरियाणा प्रांत में कोई टैक्स नहीं लगा है परंतु टैक्स ने लगने के बाद भी हरियाणा प्रांत दिन प्रति दिन उन्नति करता जा रहा है। हर गांव को रोड से मिलाया गया है और

डबल लिंक रोड बना कर अधिक से अधिक रोड़ज की सुविधायें प्रदान की जा रही है। बिजली के बारे में भी यह पोजी ान है। हर गांव में बिजली पहुंचायी गई है और हर हरिजन बस्तियों में भी बिजली की सुविधा प्रदान की जा रही है। सरकार ने वर्श 1983–84 के दौरान यानी छठी योजना के भोशकाल के लिए सरकार ने उन गांवों की हरिजन बस्तियों तक सड़क पहुंचाने का निर्णय लिया है जहां हरिजनों की आबादी पचास परसैंट है। इसी प्रकार से इरीगे ान की फैसिलिटी प्रोवाइड करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सरकार ने वर्ल्ड बैंक से एग्रीमैंट किया है जिस के तहत सन् 1983 में 250 मिलियन सुकेयर फीट कैनालज और 23 मिलियन रनिंग फीट वाटर कोसिर्ज को पक्का किया जायेगा। इन दोनों चीजों पर 205.22 करोड़ रूपया खर्च होगा। यह कितनी खु ाीर की बात है कि हमारी सरकार ने एग्रीमैंट पर साइन कर दिये है ताकि नहर के पानी का ठीक प्रकार से यूटिलाइजे ान हो सके।

मैं अपनी सरकार को इस बात के लिए मुबारिकबाद देता हूं कि हरियाणा में केंद्रीय सरकार से बातचीत करके आयल रिफायनरी लगवाने जा रही है। पानीपत में 800–900 करोड़ रूपये की लागत से केंद्रीय सरकार आयल रिफाइनरी लगाने जा रही है जिसमें कम से कम 2000 लोगों को रोजगार दिया जायेगा। हिंदुस्तान के अंदर 36 परसैंट लोग गरीबी की रेखा के नीचे आते है। इसमें 36 परसैंट हरियाणा के चालीस परसैंट लोग ऐसे है जो

हरिजन जाति से ताल्लुक रखते है। उनके उत्थान के लिए सरकार ने 1983–84 में 28.45 करोड़ रूपया खर्च करेन का प्लान बनाया है और यह उम्मीद है कि सन् 1983–84 में 64123 फैमिली को गरीबी की रेखा से ऊपर उठायेंगे। अगर एक फैमिली में 6 आदमी हों तो अपना अंदाजा लगा लेंकि छठी पंचवर्शिय योजना में कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सकेगा। अब तक छठी पंच वर्शीय योजना के पहले तीन साल मे सरकार आलरेडी 193155 फैमिलिज को हैल्प कर चुकी है और before the closing of the current year these many families will have been brought above the poverty line. हिंदुस्तान की सरकार को सब लोगों को गरीबी की लाईन से ऊपर उठाने में कम से कम दस साल लगेंगे लेकिन हमारे राज्य के लोग और सरकार प्रयत्न ील है कि पांच वर्श के अंदर गरीबी की लाईन से ऊपर सब लोग उठ जायें। कांग्रेस पार्टी की नीति से आम गरीब जनता का भला होता है। इन भाब्दों के साथ में फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने जनता की भलाई का बजट पे ा किया है।

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, हमारी पार्टी की ओर से कोई भी मैम्बर नहीं बोला है। इसलिए आज हमारी पार्टी के मैम्बर को भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के मैम्बरान बोल चुके है। पहले आप हमारे मैम्बर को मौका दें, रूलिंग पार्टी के मैम्बर को बाद में मौका दे देना।

श्री भागी राम (ऐलनाबाद–एसी0सी0): स्पीकर साहब, कांग्रेस सरकार ने जो बजट पे ा किया है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हाउस में बजट पे ा करने से पहले ही यह सरकार डीजल, बिजली और बसों का किराया बढ़ा चुकी है। अब जब बजट पे ा किया गया तो उसमें भी सेल्ज टैक्स सात परसैंट से आठ परसैंट कर दिया और उसके साथ एक परसैंट उपकर लगा दिया। उधर दूसरी ओर लगजरी गुडज पर दस से बारह परसैंट तक टैक्स लगा दिया। सरकार ने यह बात कही है कि उपकर आखिरी खरीददार पर पड़ेगा। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आखिरी खरीददार कौन होगा। आखिरी खरीददार हरिजन है, कमजोर वर्ग का व्यक्ति या मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, जिन्होंने मजदूरी करने के प चात पांच–दस या बीस किलों आटा या अनाज खरीदना है। ये हाउस में डींग मार रहे है कि गरीब किसान हरिजन और बैकवर्ड कलासिज के लोगों को ऊपर उठाने का बड़ा भारी प्रयत्न कर रहे है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या बसों में बिड़ला और टाटा सफर करेंगे जिनका आपने किराया बढाया है बसों में गरीब मजदूर किसान और हरिजन लोग ही सफर करेंगे। डीजल के रेट्स बढाये है, उसे कौन खरीदेगा? उसे किसान ट्रैक्टर के लिए खरीदेगा। किसान को बिजली की आव यकता है, उसके भी रेट्स बढा दिए। किसानों से जो बिजली की दर ली जाती है उससे कम दर फैक्टरी वालों से ली जाती है। जितने बिल किसानों के बढाये है, उससे कम फैक्टरी वालों के बढाये है। घर

के अंदर और ट्यूबवैल्ज के लिए किसान ही अधिक बिजली इस्तेमाल करता है। स्पीकर साहब यह सरकार किसानों और मजदूरों का नाम ले कर लोगों को लूट रही है। यह सरकार केवल डीजल में ही गड़बड़ नहीं कर रही है बल्कि कीड़ेमार दवाइयों में भी गड़बड़ कर रही है। किसानों की हमदर्द सरकार तो वह थी जिसने ट्रैक्टर पर टोकन टैक्स माफ किया था, खाद की कीमतें कम की थी। यह किसानों की हमदर्द कैसे हो सकती है जो दिन प्रतिदिन किसानों का गला घोटे जा रही है और बिजली खाद के रेटस बढाये जा रही है?

स्पीकर साहब, हमारी सरकार के समय में हरिजन लोगों को चौपालों के लिए पैसा दिया गया, धर्म ाला आदि भी बनवाई गई लेकिन इस सरकार ने हरिजन चौपालों के लिए एक पैसा भी नहीं रखा है। यह सरकार तो ऐसी है जैसे पहले जमाने में जब कोई ि ाकारी ि ाकार करने जाया करते थे। वे जंगली जानवर को बैल दिखाकर और बैल की आड़ लेकर बैल के पैरों के नीचे से गोली मारते थे। भजन लाल जी भी ऐसा ही करते है। जिस तरह से ि ाकारी बैल को दो किलो चने डाल कर उसकी आखें बांध देता है और बांधने के बाद बैल चुपचाप खड़ा रहता था उसी प्रकार ये भी अपने मैम्बरान को दाना डाल देते है और उनकी आड़ में ि ाकार करते है। इन लोगों के सिर पर यह सारा काम करते है।

डा0 ओम प्रका ा भार्मा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। यह लोग तो खुद इन–डिसिपलिंड है और हमारे बारे में ऐसी मिसालें देते है। इनमें खुद तो कोई डिसिपलिन है नहीं। हमारी पार्टी में डिसिपपलिन है। हमारे नेता चौधरी भजन लाल है हमारी पार्टी में तो डिसिपलिन बना हुआ है। हम आपकी तरह से बिखरे नहीं पड़े है। जनाब, जनता पार्टी को राज मिला था और वह आपस में ही लड़कर बिखर गये। हम लोग तो पूर्णरूप से चौधरी भजन लाल जी को अपना नेता मानते है। चौधरी भजन लाल हमारे लीडर है। हम पार्टी डिसिपलिन में रहते है। (व्यवधान व भाोर) आपको ऐसी बात हाउस के अंदर नहीं कहनी चाहिए थी। (व्यवधान व भाोर)

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, मैं अब सरकार का ध्यान सिरसा जिले की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे सिरसा जिले में एक आटू लेक है। बरसात के टाईम पर घग्घर मे ंपानी आने से वहां पर फसल का बहुत बुरा हाल होता है। वहां पर फसलें खराब होती है और किसान बेचारे बेकार में मरते है। वहां पर बहुत सारा रकबा गवर्नमैंट ने एक्वायर कर रखा था। जिसके लिए चौधरी देवी लाल जी ने अपने समय में एक स्कीम बनवाई थी। उस स्कीम के लिये कुछ पैसा भी मंजूर हो चुका था। मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से यह अर्ज करना चाहूंगा कि उस स्कीम को दोबारा चालू करने की कृपा करें ताकि उस एरिया को ओटू लेक की खुदाई करवा कर पानी इक्ट्ठा किया जा सके और इस पानी

से खेतों में जरूरत के वक्त सिंचाई की जा सके। अध्यक्ष महोदय इसके अलावा हमारे यहां ओटू घग्घर के ऊपर एक रैस्ट हाउस या टूरिस्ट काम्पलैक्स बनना था। वह मंजूर भी हो चुका था, जगह वगैरह सब कुछ तय हो चुकी थी अध्यक्ष महोदय, आपके सामने इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था। ठाकुर बहादुर सिंह जी एक रि तेदार है जिसका नाम सज्जन सिंह है जो खुद सरपंच है। उन्होंने अपनी जमीन को .....(व्यवधान व भाोर)

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, इन्होंने यही बात पता नहीं कितनी बार पहले भी सदन में कह दी है। आखिर बार बार वही बात कहने में तुक क्या है? (व्यवधान व भाोर)

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि वे सरपंच हैं। उन्होंने सरपंच होने के बावजूद अपनी घटिया जमीन को पंचायत की बढिया जमीन से बदल लिया है। इसक अलावा इन्होंने अपने एक भानजे को टूरिस्ट कम्पलैक्स में लगवा दिया है। अब मैं सिरसा के बारे में एक दो बाते कहना चाहता हूं । वहां का जो बस–डिपों बन हुआ है, वह चौधरी देवी लाल जी के टाईम पर बना था। वहां पर न तो कोई वर्क ाप है और न ही इसका कोई प्रबंध है। वहां पर इतना बुरा हाल है कि जब कभी बरसात हो जाती है तो कीचड़ हो जाता है और कोई आदमी जा नही ंसकता। बसो ंकी हालत यह है कि किसी बसे के अंदर भी ो नहीं है किसी के अंदर खिड़की नहीं है और किसी के अंदर सीटें

नहीं है। कई बसों में तो भाायद आपने भी देखा होगा बीच में गार्डर सा लगाया हुआ है ताकि कहीं पीछे वाला हिस्सा चलते समय पीछे ही न रह जाये और आगे वाले हिस्सा आगे न निकल जाये। यह हरिजनों की हालत के बारे में बड़े बड़े दावे करते है। मैं आपको सिरसा जिले के एक क्षेत्र रानियां के बारे में बताना चाहता हूं। वहां पर म्युनिसिपल कमैटी भी है। वहां पर आप जाकर देख्यि या किसी को भेज कर पता करवा लीजिये, बाजार का इतना बुरा हाल है जिसको ब्यान नहीं किया जा सकता। आज यह हरिजनों की दुहाई देते है। आप हरिजनों के मोहल्ले में तो जाकर देखिये आप को खुद ही पता लग जायेगा। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। न लाईट है और न ही दूसरे साधन हैं। वहां पर बहुत बुरी हालत है। एक बात, स्पीकर साहब मैं आपकी मार्फत चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या स्टेट में बदले की भावना से ही काम होंगे? इसी बदले की भावना से वहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा सरपंच सस्पैंड किये है। मैं मुख्य मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इसी किस्म की बदले की भावना से काम होन है तो इसका नतीजा पता नहीं क्या होगा? (घंटी) बहुत अच्छा जी, धन्यवाद।

श्री मंगल सैन(रोहतक): अध्यक्ष महोदय, सदन में वित मंत्री जी ने जो बजट वर्श 1983–84 के लिये पे ा किया था, उस पर चर्चा चल रही हैं इस चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने भाग लिया है। मैंने इनके विचारों को बड़े गौर से सुना है।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री अमर सिंह): आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, बात यह है कि मास्टर ि ाव प्रसाद को 16 तारीख को दस मिनट और आज ग्यारह मिनट, कुल मिलाकर 21 मिनट का समय दिया है। कंवल सिंह जी को बारह मिनट और निहाल सिंह जी को 15 मिनट दिये गये है।

श्री अध्यक्षः ठीक है, आप बैठिये!

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, भिवानी के विधायक महोदय हमें सर्टीफिकेट देते है कि यह विपक्ष के लोग अनपढ़ है और बजट पढ कर नहीं आए है, इसलिये एप्रीि ायेट नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि हम उनकी तरह एम0ए0 एल0एल0बी0 नहीं है, उन के बराबर हमारी पढाई नहीं है। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, टाईम थोड़ा है। आप अपनी बात कहिये।

श्री मंगल सैनः आप मुझे इतना बता दीजिये कि कितना टाईम देंगे, मैं उसी के मुताबिक एडजस्ट कर लूंगा।

श्री अध्यक्षः दस मिनट।

श्री मंगल सैनः आप मुझे 15 मिनट दे दीजिये। मैं समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्षः अच्छा, ठीक है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इस बजट को पढने के बाद हमें ऐसा लगता है कि this is just a balance-sheet of a company presided over by Chaudhri Bhajan Lal, and there is no direction in it. इसमें कोई दि ाा नहीं है। बीस सूत्री कार्यक्रम की चर्चा तो इन्होंने बहुत की है लेकिन उसका आधार क्या है, यह नहीं बताया। बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंदर यही बातें भाामिल है। जरा कटार सिंह जी, मैमोरैंडम ऐक्सपलेनेटरी के पृश्ठ 6 पर आप देखिये, इसमें आपने यह फरमाया है–

"Taxes and duties on Electricity (-Rs. 7.60 crores). The decrease is mainly due to less than anticipated generation of power and concessions given to industrialists."

क्या आप बतायेगे कि 7 करोड़ 60 लाख रूपये का घाटा क्यों हुआ, कम वसूल क्यों हुई? इसका कारण यह है कि बिजली की वसूली का जो इनका अनुमान था, उस अनुमान से कम बिजली वसूल हुई और इन्होंने बड़े–बड़े उद्योगपतियों को जो रियायतें दीं, उनकी वजह से इनको 7 करोड़ 60 लाख रूपये की कम वसूली हुई है। स्पीकर साहब, बीस सूत्री कार्यक्रम में करोड़पतियों और पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान हैं। स्पीकर साहब, इस बजट को मैं बहुत एप्रीि ायेट करता अगर इसमें औस्टैरिटी नजर आती, कोई सादगी नजर आती। वैसे भजन लाल जी की सादगी पर तो मैं बलिहार जाउं। इन्होंने मंत्री परिशद के सदस्य कम नहीं किये। स्पीकर साहब, मैं सीरियसली इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जिन साहेबान को कांग्रेस हाई

कमान्ड ने टिकट नहीं दिया था, आप उनको चेयरमैंन क्यों बनाने लग रहे हो? टूरिज्म कारपोरे ान का चेयरमैंन आपने उनको बनाया है, एक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड आपने बनाया है। स्पीकर साहब, मेरा काल अटैं ान मो ान तो आपने रिजैक्ट कर दिया इस बेस पर कि यह प्राईवेट मसला हैं। स्पीकर साहब, में जानता हूं यह कोई प्राईवेट मामला नहीं है। मैं रूल्ज पढा हुआ हूं। मैंने कोि ा ा की कि मैं आपके द्वारा हाउस हाउस का ध्यान आकर्शित करूं कि यह प्रिंसीपल का मामला है। पब्लिक लाईफ का कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर एक चपड़ासी के खिलाफ भी कोई किमीनल केस हो जाये तो उसको इम्मीजीयेटली सस्पैंड कर दिया जाता है, लेकिन आप के डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ अदालत के अंदर क्रिमिनल केस चल रहा है, फिर भी वह डिप्टी चेयरमैन के पद पर बना हुआ है।

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, बीच में मुझे टोकना पड़ गया। कोई प्राईवेट आदमी अगर किसी के खिलाफ कोई इस्तगासा कर दे तो क्या किया जा सकता है? अगर कोर्ट किसी के खिलाफ फैसला दे दे फिर तो अलग बात है। मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई चीज नहीं हैं। अगर कोई प्राइवेट आदमी किसी के खिलाफ इस्तगास कर दें तो कोर्ट कार्यवाही करेगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारि ा यह है कि यह भाब्द एक्सपंज कर दिए जायें।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने जो एक्सपंज करने के लिए कहा है, उसके बारे में आप बैटर जज है। क्लीन पब्लिक लाई का जो तकाजा है मैंने वह बताया है। पंजाब नै ानल बैंक जो गवर्नमैंट आफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग है उनकी तरफ से वह मुकदमा दर्ज है। स्पीकर साहब, यह किमिनल केस दफा 420 और 406 के तहत दर्ज है। (ाोर एवं व्यवधान) भजन लाल जी, मैं आपको बाध्य नहीं करता, आप विचार कर लें। स्पीकर साहब, ला एंड आर्डर के बारे में इन्होंने मेरे एक सवाल के जवाब में बताया कि हरियाणा में चार सौ पुलिसमैन डिसमिस कर दिये और सैंकड़ों लोग सस्पैंड कर दिए। क्यों कर दिये, इसका आपके पास कोई स्पश्टीकरण नहीं है। बात इतनी सी है कि आपको वे पसंद नहीं थे। स्पीकर साहब, उनको एक ही गुनाह था कि उन्होंने फरियाद की थी कि उनको यह तकलीफ है, उसको दूर कर दीजिए। स्पीकर साहब, श्रमिक आंदोलन में यह कहने का अधिकार है। आप अपने आपको समाजवादी कहते हो, बीस सूत्री प्रोग्राम का प्रचार करते हो, फिर भी आपने उनके साथ ऐसा किया? उन्होंने सिर्फ यही तो डिमांड की थी कि हमारी कठिनाइयों को दूर कर दो। भजन लाल जी, आप पुलिस की तारीफ करते हो तो आपको पुलिस का मौरल भी ऊंचा करना चाहिए। स्पीकर साहब, बल्लभगढ़ तहसील में घोज एक गांव है। वहां पर गउ हत्या करके दिल्ली में मांस सप्लाई किया जाता है वहां पर मुकदमा दर्ज हुआ जब हवा बिगड़ने लगी तो.....

चौधरी भजन लालः बाकायदा गिरफतार किया है।

श्री मंगल सैनः लेकिन वह किसका साला है?

चौधरी भजन लालः किसी का भी साला हो, गिरफतार तो किया है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आज से पहले भी डिप्टी चेयरमैन के साले साहब, यह हरकत करते रहे है। स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि इनको कुछ सादगी बरतनी चाहिए। भजनलाल जी अब तो आपकी कुछ मजबूरी नहीं है मई 1982 तो अब है नही जब आपके साथ 36 आदमी थे.....

चौधरी भजनलालः आपके साथ तो 6 ही थे।

श्री मंगल सैनः यह ठीक है हमारे 6 आदमी थे लेकिन सरकार तो अपोजी ान की ही बननी थी। (ाोर एवं व्यवधान) उस वक्त सरकार लोकदल के साथ मिल कर बननी थी। स्पीकर साहाब, आपके द्वारा मैं इन से बड़े अदब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भजन लाल जी, आपकी कोई मजबूरी इस वक्त नहीं है। आप बीस सूत्र की बात कहते है, गरीबों के साथ हमदर्दी की बात करते है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इस भारी भरकम मंत्रिमंडल को कम कर दीजिए। स्पीकर साहब, फिर असली और नकली का झगड़ा पड़ जाएगा कि कौन असली कांग्रेसी है और कौन नकली कांग्रेसी है। (व्यवधान) किसको निकाला जाएं, किसको न निकाला जाए। सरदार लछमन

सिंह जी आपने और मैंने तो इक्ट्ठी जेल काटी थी, आप तो चुप रहें। स्पीकर साहब, एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरे ान की चर्चा तो मैं क्या करूं पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी है। मुख्य मंत्री जी आपको याद होगा जिनको आपने चेयरमैन बनाया था उन्होंने दो टी0ए0 वसूल किए थे। एक असैम्बली से और एक कार्पोरे ान से। क्या आपने कोई एक ान लिया है। स्पीकर साहब, वे साहब कार्पोरे ान की प्रोडक्ट को बेचने के लिए विदे ा में गए थे।

चौधरी भजन लालः जब बनाया था तो आपसे सलाह करके बनाया था।

चौधरी मंगल सैनः अगर आपने मेरे से सलाह की होती तो यह बात न होती। जब आप चीफ मिनिस्टर बने थे उस वक्त मेरे से सलाह की थी लेकिन इस मामले में नहीं की थी। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा इनसे बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि ये एडमिनिस्ट्रे ान को ठीक करें। मैं ला एंड आर्डर के बारे में कह रहाथा और वह बीच में ही रह गई। स्पीकर साहब, बल्लभगढ में लोकदल का एक उम्मीदवार था सुभाश सेठी। 7.3.1983 को उनके घर पर जाकर उनके भाई की गोली मारी गई। गोली मारने का कारण राजनैतिक था या कुछ और था, अच्छा होगा अगर इस पर भी रो ानी डाल दी जाए। स्पीकर साहब मारना था सुभाश सेठी को लेकिनवह घर पर नहीं मिला और उसके भाई को गोली मार दी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेटस में पंद्रह लाख रूपया मांगा है और वह इस बात के लिए मांगा है कि एि ायाड

के गेम्ज में डांस करने के लिए लोगों को भेजा गया। कितनी अजीब बात है? आपने खिलाड़ियों को भेजा, खिलाड़ियों को सम्मानित किया, उनकी हौसला अफजाई की, बहुत अच्छी बात है।

चौधरी भजन लालः हरियाणा की संस्कृति को दिखाने के लिए भेजा था।

श्री मंगल सैनः हरियाणा का नाम तो आपकी वजह से ऊंचा हो रहा है। जब कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि कहां के रहने वाले हो तो हम जवाब देते है कि हरियाणा के रहने वाले है। यह सुनकर लोग मुस्कराते है और कहते है कि और जगह तो परचून में बिजनैस होता है पर हरियाणा में तो होलसेल में होता है। स्पीकर साहब, अर्बन डिवैल्पमैंट के लिए इन्होंने रा ाी रखी है। वहां पर लिखा हुआ है कि जो इलको पिछड़े हुए है ये उन पर रूपया लगाना चाहते है, गांवों में रूपया लगाना चाहते हे सड़कें बनवाना चाहते है। मैं कहता हूं कि सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए लेनि कहीं ऐसा न हो कि आप आगे चले जाएं और पीछे का काम चौपट हो जाए। स्पीकर साहब, भाहरों में स्लम एरिया बने हुए है और वहां पर गंदी बस्तियां बन चुकी है। जब लोकल सैल्फ मिनिस्टर से बात की तो वह कहने लगे कि क्या करें, पैसा कम है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाशण पर बोलते हुए मैंने रोहतक के बारे में अपनी बात रखी है। वहां पर कोई सड़क पूरी नहीं मिलेगी। सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है। वहां की म्यूनिसिपल कमेटी के पास कोई पैसा नहीं है। इन्होंने

लाइसैंस की फीस बढा दी है। इन्होंने कहा है कि मैं उसको रे ानेलाइज कर रहा हूं लेकिन स्पीकर साहब, इन्होंने तो ऐसा कर दिया है कि मैं उसको रै ानेलाइज कर रहा हूं लेकिन स्पीकर साहब, इन्होंने तो ऐसा कर दिया है कि छोटे से दुकानदार को भी छः लाइसैंस लेने पड़ेंगे। सरकारी मुलाजिमों पर चौधरी कटार साहब ने कटार चला दी है। स्पीकर साहब, आजकल रोटी तो पूरी होती नहीं है, बचत क्या करेंगे। सेल्ज टैक्स सात परसैंट से आठ परसैंट कर दियाऔर लकड़ी गुडज पर दस परसैंट से बारह परसैंट कर दिया। स्पीकर साहब, लग्जरी गुडज की डैफिने ान चौधरी कटार सिंह ने बहुत अच्छी की है। लकड़ी के फर्नीचर को भी इन्होंने लग्जरी गुडज में लै लिया, टायर और टयूब, साईकिल और मौप्ड आदि चीजों को लग्जरी गुडज में भाामिल कर लिया है। स्पीकर साहब, लकड़ी का फर्नीचर वैसे तो नसैसिटी आफ लाइफ है। कम्फर्टस एण्ड नसैटिसी का डैफिने ान हमे ाा बदलती रहती है और मैन टू मैन डिफर करती है। एक चीज एक आदमी के लिए कम्फर्ट है तो दूसरे के लिए नसैसिटी है। एक वकील कै लिए कुर्सी नसैटिी है तो दूसरे के लिए कम्फर्ट है। मैं कह सकता हूं कि लकड़ी का फर्नीचर नैससिटी है। इस पर भी इन्हेांने बारह परसैन्ट टैक्स कर दिया। कल हमने इनको तार भी दिखा दिया है जिसमें व्यापरियों ने कहा है कि सारा व्यापार चौपट हो जाएगा। सारा व्यापार पड़ौसी राज्यों में ि ाफ्ट हो जाएगा। स्पीकर साहब, मौपड जिस पर हमारी बहने गांव में पढ़ाने जाती है, वह 3500 यसा 3600 रूपए में आता है। इसको मिड क्लास भी नहीं लोयर

मिडल क्लास का आदमी इस्तेमाल करता है। उस पर भी बारह परसैन्ट टैक्स लगा दिया हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली, यू.पी. , राजस्थान और पंजाब के साथ जो हरियाणा का इलाका लगता है उन इलाकों के व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा क्योंकि यहां के लोग दूसरे प्रान्तों से सामान खरीदेंगे। किसी एफसर ने मंत्री जी को कह दिया और इन्होंने नासम3झी के कारण ऐसा कर दिया। इसको मंत्री जी ठीक कर लें। मैं कहना चाहता हजूं कि टैक्स बढ़ाने से आपकी आमदनी कम हो जाएगी और आपका बहुत नुकसान होगा।

स्पीकर साहब, इन्होंने कहा है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत सी स्कीमें सरकार ने बनायी है। ठीक है बनाई है लेकिन जब तक रोजगार नहीं मिल जाता तक तब अन इम्पलायसड लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए।

स्पीकर साहब, जहां तक न ाबन्दी की बात है, हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी इस बात के बिल्कुल हक में थे लेकिन उनकी बात कौन सुनता है। आजकल तो उनका नाम भी नहीं लिया जाता। आजकल तो इन्दिरा गांधी का नाम ही हर तरफ लिया जाता है। स्पीकर साहब, आपने गांधी जी कि फिल्म देखी होगी, मुझे भी देखने का मौका मिला है, भाायद बनाने वाले ने गांधी जी की असलीयत को नहीं दिखाया है, भाायद काफी मिसटेक्स की है। मैं भी यह चाहता हूं कि पूरे राज्य में पूर्ण न ाबन्दी होनी चाहिए। (ाोर)

स्पीकर साहब, मेरे नौजवान साथी नेहरा साहब ऐजुके ान के इंचार्ज है उनका वास्ता ऐसे लोगों से है कि जब तक ये उनकी बातें मानते रहेंगे तब तक वे कहेंगे कि नेहरा साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं और जब ये उनकी बातें नहीं मानेगें तब वे कहेंगे कि नेहरा साहब, बुरे है। वे इनसे बिगड़े ही रहेंगे। रोहतक के वाइस चान्सलर को हटा दिया गया, उनको लगाया हमने था, इस गल्ती को मैं मानता हूं। जब उनको हटाया तो उन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया। (घण्टी) मैं भजन लाल जी से यह जानना चाहता हूं कि आप उस मुकदमें से क्यों डरे गयें, क्यों आपने उनको रीइंस्टेट कर दिया ?

स्पीकर साहब, यहां पर लेबर की बात भी आई। मेरे एक नौजवान साथी उस विभाग को लीड करते हैं ओर उनके पिता जी भी लेबर के मामले में काफी एक्सपर्ट रहे हैं और लेबर के हक में भी रहे हैं। हिसार टैक्सटाइल मिल के मजदूरों ने अपनी डिमांडज दी थी और सरकार ने उनसे प्रोमिस भी किया था कि आपकी बातें मानी जाएंगी लेकिन पूंजी पतियों ने सरकार से गठजोड़ करके उन मजदूरों की डिमांडज को ठुकरा दिया है। मेरा सरकार से यह कहना है कि अगर जीना चाहते हो तो पूंजीपतियों की बात न मानो और मजदूरों की बातों की सुनों और सुन कर उन्हें राहत दी।

स्पीकर साहब, अन्धों की बात भी यहां पर आयी। मैं मानता हूं कि भजन लाल जी को अव य ही अन्धों से हमदर्दी है।

इन्होंने प्रोमिस किया था कि उनकी ि ाकायतें दूर हो जाएंगी और उनको एडजस्ट कर लिया जाएगा। ट्रकों के नै ानल परमिट या कोई दूसरी एजेनसियां उन्हें नहीं दी गयी है, इस तरफ सरकार को अव य ध्यान देना चाहिए। (घण्टी)

स्पीकर साहब, एक दो बातें कह कर मैं समाप्त करूंगा, आपका हुकम सिर माथे पर। नाहड़ का इलाका चौधरी हुकम सिंह जी से सम्बन्धित है, वहां पर नील गायों की प्रोबलम है। श्री राम विलास भार्मा जी के प्र न के उत्तर में चौधरी भजन लाल जी ने इस बात के लिए आव वासन भी दिया था। वहां पर कोई 1000 के लगभग नील गायें हैं, उनके लिये बाड़ नहीं दी गयी है। यह 10 मील का रिजर्व फारैस्ट का एरिया है, यहां पर बाड़ का प्रबन्ध अव य होना चाहिए ताकि किसानों की फसल बरबाद होने से बचाई जा सके।

आखिरी बात यह है कि उस इलाके में वहां के डी.सी. ने लेवी का सीमेंट एक ही आमदी को अलाट किया है, जबकि दूसरे लोगों को भी सीमेंट बेचने का मौका मिलना चाहिए। यह बात अखबारों मैं भी आयी थी। मैं आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर महोदय से कहूंगा कि उन्होंने जो ग्रीवैन्सिज कमेटी बनायी हुई है, पता नहीं वह किस की ग्रीवैन्सिज मिटा रही है ? पिछली दिनों एग्रीक्लचर मार्किटिंग बोर्ड के 30 इम्पलाईज के बारे में कहा था कि आप इन्हें बहाल कर दो लेकिन ये नहीं माने लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हे बहाल कर दिया। (घण्टी) बस, इन

भाब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आपका हुकत सिर माथे पर, स्पीकर साहब, कहने को तो और बहुत सी बातें थी लेकिन फिर कभी मौका मिला तो कहूंगा।

श्री अध्यक्षः अब फायनैन्स मिनिस्टर साहब बोलेंगे।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरी पार्टी के केवल एक ही सदस्य बोले हैं, आपको यह चाहिए था कि हमारे कुछ लोगो को और समय देते जबकि दूसरी तरफ से कितने ही लोग बोल चुके हैं। सर, हमें भी समय मिलना चाहिए।

Mr. Speaker: I will compensat you when demands for grants will be discussed.

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से बजट पर चर्चा चल रही है। इस सदन के बहुत से पुराने और प्रतिश्ठित सदस्य डा. मंगल सैन जी ने घिसे पिटे भाशण में बड़े अन्दाज से अपनी बातें कही। कहना तो यह चाहिए कि भाशण ठीक ही था लेकिन अन्दाज वही पुराना घिसा पिटा था। इनके इलावा और कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार इस सदन में रखे और हमने उनके विचार ध्यानपूर्वक सुने। जो वितीय नीति हरियाणा सरकार ने इस सल तय की है, उस बारे में कोई वि ोश बात नहीं कही और ज्यादातर बातें सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों के बारे में ही कही है।

आने वाले साल के लिए जो वितीय ननीति बनायी गयी है, उसके बारे में जो मुख्य बातें कही गयीं हैं, मैं पहले उन बातो ंका जवाब दूंगा और उसके बाद जो कठिनाईयां जो परे ाानीयां सदस्यों को अपने अपने क्षेत्रों में महसूस हुई हैं या सामान्य प्र ाासन में महसूस हुई है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। अध्यक्ष महोदय जनरल सेलज टैक्स के बढ़ाने पर कुछ विरोधी पक्ष में माननीय सदस्यों ने एतराज किये हैं, लेकिन बाई एण्ड लार्ज विरोधी दल की तरफ से कुछ सदस्यो ंने और हमारे ट्रेजरी बैंचिज के साथियों ने या उसको सराहा है, या समर्थन दिया है या फिर उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। (ाोर एवं व्यवधान) कल भी यह बात सदन में आयी थी चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी बड़े ही मंजे हुए व्यक्ति, गरीबों के मित्र और किसानों के बहुत हिते ाी है, जिनको सारा सदन आदर की निगाह से देखता है। ये बहुत समय तक बोलते रहे। इन्होंने भी सेलज टैक्स बढ़ाने के प्रावधान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाही। इसके इलावा, हमारी बहुत ही आदरणीय और पुरानी पार्लियामेन्टेरियन बहन श्रीमती चन्द्रावती जी इस सदन में बोली। मैं उनका बड़ा आदर करताह ूं सभ लोग उनका आदर करते हैं लेकिन मैं सबसे ज्यादा आदर करता हूं। बहुत देर से मैं उनको जानता हूं और साथ भी रहा हूं। इन्होंने भी बहुत ही कैजुअल–वे में इसकी चर्चा की। वे जब बोल रही थी तो ऐसा लगता था कि कोई सुन न ले, लेकिन डाक्टर साहब ने बोलते हुए जरूर अपनी बातों पर बल दिया है और उनकी ओर से बढ़ चढ़ कर अव य बातें कही गयी है। रूरल डिवैल्पमैंट सैस की

बात की गई है लेकिन इस पर भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। इससे तो यह मान लेना चाहिए कि सारा सदन इससे सहमत है। यह अच्छी बात है लेकिन फिर भी जो बातें कही गई है, मैं उनका जवाब दूंगा और कोि ा ा करूंाग कि यह बात उनकी समझ में आ जाए। अध्यक्ष्ज्ञ महोदय, सेल्ज टैक्स के बारे में हमने बजट में बात कही है कि इसको 7 प्रति ात से 8 प्रति ात कर देंगे। यह एक बड़ी जनरल सी बात है क्योंकि हर आदमी यह महसूस करता है कि यह किस किस चीज पर लगेगा और कितना लगेगा। यह जो बढ़ौतरी की गई है यह एक न जानने की बात है और इसमें किसी की गलती भी नहीं है। इस बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स का एक्ट है, उसके अधीन चार ि ाड्यूल बने हुए हुए हैं यानी चार कैटेगरीज बनी हुई हैं – ए, बी, सी और डी कैटेगरी। ये मैयर्ज पहले ही लिए हुए हैं कि आम आदमी और गरीब के इस्तेमाल की जो जरूरी चीजें हैं, उन पर या तो सेल्ज टैक्स लगाया ही न जाए और अगर लगाया जाए तो वह इस हद तक न हो कि उसके ऊपर बोझा पड़े। ि ाड्यूल बी में 50 के करीब आइटम्ज हैं जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिन्दगी में इस्तेमाल होती है। उनके बारे में सरकार ने यह निर्णय लिया हुआ है कि इनके ऊपर सेल्ज टैक्स नहीं लगेगा। यह भ्रम निकल जाना चाहिए कि 7 प्रति ात से जो 8 प्रति ात किया गया है। यह ि ाड्यूल बी की आइटम्ज पर एप्लाई नहीं करता। मैं ि ाड्यूल बी की आइटम्ज आप को पढ़ कर सुना देता हूं ताकि आपका भ्रम दूर हो जाए:–

1. Vegetables, but not including red Chillies, dry or otherwise.
2. Shakkarkandi
3. Sugarcane
4. Milk Except (Milk liable to tax under section 9 and condensed and dried milk.)
5. Meat, fish and eggs except when sold in tins, bottles or cartoons.
6. Fresg fruits.
7. Common salt. Except when sold in sealed containers.
8. Flower.
9. Pan.
10. Books.
11. Periodicals.
12. Exercise and drawing books.
13. Writing slates and slates pencils.
14. Writing Chalks and Caryons.
15. Coloured pencils used for drawing but not ordinary graphic pencil popularly known as read pencils.
16. Foot rules of the usually used in schools.

17. All catagories of cotton, woollen or silken textiles including rayon, artificial silk or nylon whether manufactured by handloom or powerloom or otherwise but not including carpets, druggets (and dryer belts whether made from cotton wool or man made fibre.)

18. All varieties of textiles covered by item 14 of which knitting and embroidery work has been done.

19. Such varieties of convas cloth Tarpaulines and similar other products, manufactured with coloths as base as area manufactured in textile mills, powerloom factories and processing factories but not including transmission belts.

20. Leather cloth and inferior or imitation leather cloth ordinarily used in book binding, rubber used tissue or synthetic water proof fabrics whether single tentured or double tenture; and book binding fabrics.

21. Electric energy.

22. Motor spirit as defined in the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) Act, 1939.

23. Photographs including X-rays photograph.

24. Agricultural implements as may be specified by the State Government by Notification in the official Gazette.

25. All goods sold to the Indian Red Cross Society and St. John Ambulance Association and Hindu Kushet NivaraN Sangh and (Haryana State Council for Child Welfare and their respective branches.)

26. Spinning Whell (Charkha) and its parts.

27. All goods sold to the Central Puchasing Service, New Delhi, operated by the Catholic Hospital Association of India.

28. Country Liquor.

29. A Sale of foreign liquor (Indian made foreign liquor) foreign liquor purchased on payment of tax by retail foreign liquor licensees granted licence under the Punjab Excise Act, 1914, as applicable to the State of Haryana, from L-1 Licensees in the State.)

30. Judicial and non-judicial stamps, Entertainment Duty, Stamps passengers and Goods Tax stamps, (standard water marked petition paper and philatelic stamps)

31. Fertilizers but not including oi-cakes.

32. Hand-spun yarn.

33. Crudely tanned leather called half tanned leather usually tanned by villagers in villages (other than that tanned in a factory.)

34. Reori, Patashas, Gajjaks, Misri (Candy or Cooza), gollies, boora, Makhannans, Marunda and Phullian.

35. Articles ordinarily prepared by Halwais. (When sold by Halwais exclusively.)

36. Tobacco whether crude, uncrude or manufactured and all its products including bidis, Cigarettes, cigars.

37. Artificials hearing aids and their accessories.

38. Vegetable seeds and vegetables Saplings.

39. Fodder of every type (dry or green) but not including oi-cakes, Guar, giri (and Chhilka of foodgrains pulses and cotton seeds.)

40. Earthenware made by Kumahars.

41. Kikar bark.

42. Country-made shoes (Jooties)

43. Takhities used by students in schools.

44. Sugar.

45. Bakery goods prepared without using power at any stage.

46. Bardana (packing meterial) and containers.

47. Kuth.

48. Straw cover.

49. Edible oils produced from Sarson, Toria and til in indigenous Kohlus whether worked by animals or human beings.

50. Indian food preparations ordinarily prepared by Tandoorwalas and Dhabawalas.

51. Eatables and drinks.

52. Water (equapura) other than the aerated or mineral water or water sold in bottles or sealed containers.

53. Medicines.

54. Condoms.

55. All goods sold to the (serving military personnel and Ex-Serviceman by Canteen Stores Department) direct or through the authorised Cnatten Contractors or through Unit run conteens

56. Lottery tickets.

57. Poultry feed, that is to say, a mixture of proteins, salts and minerals, vitamins, antibiotics and co-cidiastats, whether such mixture contains carbonhydrates or not.

58. Machinery used in the Gobar Gas that is:-

    i. Gobar Gas Holder.

    ii. Guide frame for gobar gas holder.

    iii. Gober gas burner.

59. UNICEF Greeting Cards and Calendars.

60. Live Poultry Birds.

61. Janta Khana.

62. Curd.

63. Desi Ghee manufactured without the aid of electric power at any stage in its procees.

64. Food-grains sold by Food Corporation of India to Government of India supply to the State of Haryana

under the Food for Work National Rural Employment Programme on or after 1st April, 1978.

ये आइटम्ज ऐसी हैं जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं और इन पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। उसके बाद ि ाडयूल सी में दो आइटम्ज हैं जिनमें एक भाराब की आइटम भी है। ि ाड्यूल ए में लगजरी गुडज आती है। इनमें से मेरे साथियों ने परे ाानी पैदा करने के लिए दो आइटम्ज ढूंढी हैं – एक मेंहदी और दूसरी टुथ ब्र ा। इन्होंने यह बताने की कोि ा ा की कि ि ाडयूल ए की आइटम्ज पर टैक्स लगाने से बड़ी भारी परे ाानी हो जाएगी। आखिर में मंगल सैन जी ने वुडन फर्नीचर की बात कही। अध्यक्ष महोदय, जो ि ाडयूल ए में आइटम्ज हैं वह भी मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं कि आम आदमी को उससे क्या तकलीफ होगी। इन आइटम्ज पर 10 प्रति ात से 12 प्रति ात सेल्ज टैक्स बढ़ाने की बात है, उसका आम आदमी पर किसी तरह से भी असर नहीं पड़ता। ये आइटम्ज हैं:–

1. Motor Vehicles, including accessories and chesis of motor vehicles, motor tyres and tubes and spare parts of motor vehicles.

2. Motor Cycles and motor cycle combinations, motor, scooters, motorettes and accessories, tyres, tubes and spare parts thereof.

3. Refrigerators and air-condioning plants and component parts thereof.

4. Wireless reception instruments and apparatus, radio and radio-gramophones, electrical valves, hacummulators, amplifiers and loud speakers and spare parts and accessories thereof.

5. Cinemategraphic equipment including cameras, projectors and sound recording and reproducing equipments lenses, films, and part and acceseories required for use therewith.

6. Photographic and other cameras and enlargers, lenses, films and part, papers and cloth and parts and accessories required for use therewith.

7. All clocks, time pieces and watches and parts thereof.

8. All furniture of irion and steel including safes and almirahs.

9. All furniture other than that of iron and steel.

10. All arms and including rifles, revolvers, pistoals and ammunition.

11. Cigarettee cases and lighters.

12. Dictaphone and other similar apparatus for recording sound and spare parts thereof.

13. Sound transmitting equipment including telephones and loudspeakers and spare parts thereof.

14. Typewriters, tabulating machines calculating machines and duplicating machines and parts thereof.

15. Binoculars, telescopes and opera glasses.

16. Cramophones and compnent parts thereof and records.

17. Cosmatics, perfumerly and toilet goods put not including tooth paste, tooth powder, soap, kum-kum, Dhoop and Aggarbatie.

18. Electicla appliances excluding electric bulbs, electir motors, motor starters and monoblock pumping sets.

19. Pilecarpets.

20. Cutlery (Table).

21. Vacum Flasks.

22. Sanitary goods and fittings.

23. Leather goods but not including footwear.

24. Glassware, Clazedware and chinaware including crockery.

25. (Liquor, Foreign Liquor and Indian Made Foreign Liquor.)

26. Pecnic sets.

27. Foam rubber products.

28. Articles made wholy or principally of stainless steel but not including surgical instruments.

29. Perambulaters.

30. Furs and articles of personal or domestic use made from furs.

31. Plastic, Celluloid, Bakelie good and goods of similar substances (excluding Footwear) of the value exceeding ten rupees per piece.)

32. All tiles including Mosaic tiles (but not including roofing tiles) laminated sheets and sun mica sheets.

33. Generating sets and Transformers

34. Cement.

अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि इन आइटम्ज पर सेल्ज टैक्स बढ़ान से आम आदमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता हो।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इसमें घड़ी भी भाामिल है। एक आम आदमी जो एक सौ रूपये की घड़ी खरीदेगा, उस पर तो असर पड़ेगा ही।

चौधरी कटार सिंह छोकरः इस बढ़ोतरी से आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा। हां उधर जो एम.एल.ए. बैठे हैं उनको फर्क जरूर पड़ सकता है। (विघ्न) ि ाडयूल ए में 10 प्रति ात टैक्स तो पहले ही है। अगर एक आदमी पहले 110 रूपये की घड़ी खरीदता था, अब उसे 112 रूपये देने पड़ेगे। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यह भी नहीं कहा जा सकता कि जिनको यह

टैक्स देना पड़ेगा वे बिल्कुल ही गरीब आदमी होंगे या आम आदमी होंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब हम किसी काम को करने चलते है, चाहे वह घर का काम हो, चाहे स्टेट का काम हो, लोगों की तरह तरह की मांगें होती है। घर में एक बच्चा कहता है कि मुझे जूते भी चाहिएं, दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे कपड़ा चाहिए।

13.00 बजे

इसी तरह से स्टेट का हर वर्ग चाहता है कि इनके लिए हर तरह के काम हो, यानी सारे क्षेत्र अपने तरीके से तरक्की चाहते हैं। सरकार ने पानी और बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्टस एग्जीक्यूट करने हैं, यदि पैसा नहीं होगा तो उनका काम कैसे पूरा होगा ? इस बारे में यदि अपोजी ान का कोई सदस्य यह कहें कि सरकार अपने पास एक जादूगर बिठा ले, वह पैसे बनाता रहेगा, ताकि न सरकार को कोई टैक्स लगाना पड़े और न ही हरियाणा की जनता पर कोई बोझ पड़े। स्पीकर साहब, मैं अपोजी ान के भाईयों को बताना चाहता हूं कि यदि इस बारे में आप लोगों की कभी जिम्मेदारी आई तो आप लोग भी पैसा बनाने के लिए कोई जादूगर नहीं बैठा सके और न ही कोई जादूगर ऐसा है जो पैसा बनाकर सरकार को देता रहे और सरकार का काम चलता रहे। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ सदस्यों का यह कहना कि बगैर टैक्स लगाए यह काम कर दें, वह काम कर दें उनकी यह बात ठीक नहीं है। मैं आपोजी ान के भाईयों से यह कहना

चाहता हूं कि आप लोग जिम्मेदारियों से बहुत दूर है। खुदा न खास्ता अगर इनको ऐसा मौका मिला भी होता तो अब तक ये सब कुछ छोड़ गए होते। जब मेरे विरोधी भाईयों की सरकार बनी थी तो मुझे उस समय के तमा ाों को देखने का मौका मिला लेकिन सुनने मं जरूर आया है कि जिम्मेदारियों के बोझ से इनकी कुर्सी घुमा करती थी। कमरे की छत नीचे और जमीन ऊपर नजर आया करती थी। आफिस का नीचे का फलौर ऊपर और ऊपर का फलोर नीचे से नजर आया करता था और इनक रहनुमा न ाा करके आफिस में बैठा करते थे। स्पीकर साहब, मैं अपने अपोजी ान के भाईयों को बताना चाहता हूं कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। जिम्मेदारी निभाना बहुत मु कल होता है। स्पीकर साहब, न इन्होंने कभी कोई अच्छा काम किया और न ही कभी कोई अच्छी बात सोची है। इसलिए जनता इनको कभी भी याद नहीं कर सकती। यदि कोई सरकार अच्छे काम करती है तो जनता उसके कामों को उंगलियों पर गिना करती है। स्पीकर साहब, ये लोग कभी भी टिक कर नहीं बैठे और न ही इन्होंने कभी कोई अच्छी बात सोची है। यदि मेरे अपोजी ान के भाई टिक कर बैठें और अच्छी बात सोचें तो खुदा का यह नियम है कि सारे काम अच्छें होंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप अपने आप पर संयम रखें और भगवान पर वि वास रखें, लेकिन इनके पास काम कुछ नहीं रहा इसलिए ये टिक कर नहीं बैठ सकते। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं अपने लीडर चौधरी भजन लाल जी से कहूंगा, आपने भी देखा होगा, मेरे अपोजी ान के भाईयों ने भी

देखा होगा कि जो मनोवैज्ञानिक दबाव डाला था, वह काफी ढीला कर दिया गया अगर थोड़ा बहुत है तो वह भी ढीला कर दें। अब मुख्य मंत्री जी आप पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। स्पीकर साहब, इनकी तरफ से जो भी बातें कहीं गई है, उनका जवाब दिया जाएगा लेकिन इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था फिर भी जो कुछ कहा गया है वह इतना बुरा भी नहीं है। स्पीकर साहब, विपक्ष के सदस्यों को सरकार की कारगुजारी के बारे में अपने विचार प्रकट करने का पूरा हक है और सलाह देने का भी हक हैं। जिस समय ये अपने विचार सदन के समाने रखते है, उस समय इनके मुंह से कोई अच्छी बात भी निकल सकती है चाहे बोलने वाला कैसा ही हो। स्पीकर साहब, मेरे अपोजी ान के भाईयों ने जो कुछ कहा है हम उसमें से अच्छी बात ढूंढने की पूरी कोि ा ा कर रहे है। इन्होंने मेन बात सेल्ज टैक्स के बारे में कही है, उसके बारे में मैंने इनको बता दिया है। इनको सेल्ज टैक्स के बढने से ज्यादा परे ाानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस सेल्ज टैक्स के बढाने से आम आदमियों पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं भी साधारण आदमी हूं और साधारण आदमियों में रहता हूं मैं भी आम आदमी हूं और आम आदमियों में रहता हूं। आप भी आम और साधारण आदमी है और साधारण आदमियों में रहते है। ऐसे बहुत कम विधायक है जो भाहरी कांस्टीच्युएंसीज को रिप्रजैंट करते है। लगभग सारे विधायक देहात के गरीब लोगों द्वारा ही चुनकर आए है जहां पर अस्सी परसैंट आबादी रहती हैं। मैं भी देहात के गरीब तबके से चुनकर आया हूं। हम

उनकी जरूरतों को अच्छी तरह से समझते है लेकिन डाक्टर मंगल सैन जी देहात की गरीब जनता की जरूरतो ंको अच्छी तरह से नहीं समझते क्योंकि इनका आज तक देहात से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। डाक्टर साहब हमे ाा अपने भाहर की कांस्टीच्युएंसी से जीत कर आते है इसलिए देहात की तकलीफों के बारे में इनको बहुत कम ज्ञान है। (विघ्न) स्पीकर साहब, हमारे देहात के जमींदार इस बात को अच्छी तरह से समझते है कि यह सेल्ज टैक्स उनको प्रभावित नहीं करेगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह कुछ लोगों को भ्रम है कि यह टैक्स गरीब आदमियों को परे ाान करेगा। इसके अलावा हमारे प्रदे ा के कुछ लोगों को यह भ्रम है कि हमारे पड़ोसी राज्यों में कुछ चीजें हमारे प्रदे ा से सस्ती मिलती है और हमारे यहां पर मंहगी मिलती है। स्पीकर साहब, दूसरे प्रदे ाों में सेल्ज टैक्स की दर क्या है, वह मैं अपने साथ लाया हूं जिससे मेरे अपोजी ान के भाइयों को यह मालूम हो जाएगा कि हमारे प्रदे ा में दूसरे प्रदे ाों की बजाय सेल्ज टैक्स की दरें बहुत कम है। हमारे प्रदे ा में सात परसैंट जनरल सेल्ज टैक्स है और ि ाड्यूल 'ए' की लगजरी आइटम्ज पर दस परसैंट सेल्ज टैक्स है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विधान सभा के रिकार्ड को दुरूस्त कर दिया जाए क्योंकि लगजरी गुडज कहने की बजाय ि ाड्यूल ए की आइटम कही जानी चाहिए। मैने बजट स्पीच में भी लग्जरी गुडज ही बोला था। दूसरे प्रदे ाों में सेल्ज टैक्स की दरें इस प्रकार है:—

प्रदे ा का नाम	जनरल सेल टैक्स की दर	ि ाड्यूल ए की आइटम पर सेल टैक्स की दर
पंजाब	7 प्रति ात	10 प्रति ात
हिमाचल प्रदे ा	7 प्रति ात	10 प्रति ात
दिल्ली	7 प्रति ात	10 प्रति ात
उत्तर प्रदे ा	8 प्रति ात	10 प्रति ात, 12 प्रति ात, 14 प्रति ात
राजस्थान	8 प्रति ात	10 प्रति ात, 12 प्रति ात
गुजरात	6 प्रति ात, 7 प्रति ात और 8 प्रति ात	10 प्रति ात, 12 प्रति ात और 15 प्रति ात
महाराश्ट्र	7 प्रति ात और 8 प्रति ात	10 प्रति ात, 12 प्रति ात और 15 प्रति ात
केरला	6 प्रति ात और 8	10 प्रति ात, 12 प्रति ात और 15

	प्रति ात	प्रति ात
मध्यप्रदे ा	8 प्रति ात और 10 प्रति ात	12 प्रति ात और 13½ प्रति ात
तामिलनाडू	6 प्रति ात, 8 प्रति ात और 9 प्रति ात	10 प्रति ात, 12 प्रति ात और 15 प्रति ात
बिहार	7 प्रति ात और 9 प्रति ात	10 प्रति ात, 11 प्रति ात, 13 प्रति ात, 16 प्रति ात
कर्नाटका	6 प्रति ात, 7 प्रति ात, 8 प्रति ात	12 प्रति ात, 13 प्रति ात और 15 प्रति ात
आन्ध्रा प्रदे ा	6 प्रति ात और 8 प्रति ात	10 प्रति ात और 12 प्रति ात
उड़ीसा	7 प्रति ात और 10 प्रति ात	13 प्रति ात

स्पीकर साहब, जिन राज्यों की सेल्ज टैक्स की दरों की मैंने फिगर्ज दी है, इनका अच्छी तरह से अध्ययन करने पर अपोजी ान के भाइयों का भ्रम दूर हो गया होगा। इनको यह भी अच्छी तरह से ज्ञान हो गया हो गया होगा कि हमारे प्रदे ा में दूसरे प्रदे ाों की अपेक्षा जनरल सेल्ज टैक्स और ि ाड्यूल ए की आइटमज पर टैक्स की दरें बहुत कम है। हमने जो थोड़ा सेल्ज टैक्स बढाया है, यह कोई साधारण बात नहीं की है। यह बिल्कुल बर्दा त होने वाली बात है। इससे आम आदमियों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे प्रदे ा के मुकाबले में दूसरे प्रदे ाों में ज्यादा टैक्स लगे हुए है। दिल्ली की बात तो किसी हद तक ठीक है। दिल्ली के बारे में तो लोग कह सकते है कि वहां पर टैक्स बहुत ज्यादा नहीं है। दिल्ली सारे दे ा की राजधानी है। वहां पर सभी प्रदे ाों के लोग जाते है। कुछ लोग हेराफेरी से छोटा–मोटा सामान अपनी अटैची में या थैलों में डालकर ले आते है और अपनी–अपनी स्टेटस में जाकर बेच देते है। स्पीकर साहब, दिल्ली से हजारों आदमी आते है और हरेक का थैला चैक नहीं किया जा सकता और न ही हरेक की अटैची चैक की जा सकती है। ऐसी छोटी–मोटी चीजें होती रहती है, इनको अधिक महसूस नहीं करना चाहिए। जो लोग छोटी–मोटी चीजें ले आते है, उनको फुल प्रूफ भी नहीं किया जा सकता, because the sale takes place on every moment, every minute, every second and on every shop throughout the country. कोई एजैंसी या कोई तरीका ऐसा नहीं हो सकता जिसके तहत यह रोक लगाई जा

सके। यह भी संभव नहीं कि एक–एक दुकान के साथ एक–एक सरकारी कर्मचारी चैकिंग के लिए बैठा दिया जाए ताकि काम ठीक हो सके। यदि ऐसा कर भी दिया जाए तो फिर भी यह संभव नहीं है। इस तरह की काफी परे ाानियां है जिनकी वजह से हर चीज पर चैकिंग नहीं की जा सकती। मैं अपने सभी साथियों को और सारे प्रदे ा के लोगों को बता देना चाहता हूं कि टैक्स इवेजन के मामले में जब से चौधरी भजन लाल जी की कांग्रेस सरकार आई है, तब से यानी 1979–80 से लेकर आज तक सेल्ज टैक्स दो गुणा अधिक रिकवर किया गया है। 1978–79 में सेल्ज टैक्स की रिकवरी 70 करोड़ रूपए थी लेकिन अब सेल्ज टैक्स की रिकवरी 165 करोड़ रूपए की है। अब इनका यह भ्रम दूर हो गया होगा कि सेल्ज टैक्स की इवेजन बढी है, घटी नहीं।

श्री बीरेंद्र सिंहः यह इवेजन तो कीमतें बढने के कारण ज्यादा हुई है। रिकवरी कोई ज्यादा नहीं हुई।

चौधरी कटार सिंह छोकरः आप तत कुछ भी निकाल लें। यह अलग बात है।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः आपको तो एक्साईज डिपार्टमैंट मिलना चाहिएं।

चौधरी कटार सिंह छोकरः आप जो कुछ कह रहे है, उसे सी0एम0 साहब भी सुन रहे है। इसी प्रकार से राव निहाल सिंह जी ने भी मेरे बारे में काफी कुछ कहा था। वे मेरे बुजुर्ग

है। जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। यह ठीक बात है कि फाईनैंस के मामले में अधिक से अधिक ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए कुछ एक्सपीरिएंस भी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ हिसाब–किताब का नालेज भी होना चाहिएं उन्होंने जो कुछ कहा है, मैं उसे गलत नहीं मानूंगा। भाई बीरेंद्र सिंह जी बैठे–बैठे कुछ कह रहे है। आपकी बात को सी0एम0 साहब सुन रहे है। हम तो सी.एम. साहब का हुक्म मानने वाले है। वे मुझे जो ड्यूटी सौंपेंगे मैं उसी को पूरा करूंगा। जो एतराज कर रहे थे, वे सब समझ गए होंगे और डा0 मंगल सैन भी मेरी बातों से प्रभावित हुए होंगे।

श्री मंगल सैनः मैं आपसे कुछ प्रभावित नहीं हुआ।

चौधरी कटार सिंहः आप लौजिकली जरूर प्रभावित हुए होंगे। इल्लौजिक्ली न हुए हो तो बात अलग है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इन्होंने जो टैक्स बढाया है, उसे ये कम समझते है। ये इस टैक्स को 14 प्रति ात तक बढाना चाहते है।

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, सैंस पर जो एक प्रति ात लगाया गया है, उस पर भी काफी कुछ कहा गया है। मैं साथियों को बताना चाहता हूं कि हमने साफ–साफ लिखा है कि जो फसल मंडियों में जाएगी, उस पर एक प्रति ात के हिसाब से जो टैक्स लिया जाएगा, वह आढतियों से लिया जाएगा

न कि किसानों से। इससे जो धन इक्ट्ठा होगा, उससे गांव के अंदर ही डिपार्टमैंट के काम होंगे। हमें आ ाा है कि इस टैक्स से आठ करोड़ रूपए इक्ट्ठे होंगे। ज्यादा भी इक्ट्ठे हो सकते है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस टैक्स से जितना पैसा इक्ट्ठा होगा, उतना ही पैसा सरकार अपनी तरफ से लगाएगी। यह पैसा जिस इलाके से इक्ट्ठा किया जाएगा उसी इलाके की डिवैल्पमैंट के लिए खर्च किया जाएगा। मेरी इस बात को ये भाई अच्छी तरह से समझ गए होंगे। स्पीकर साहब, जब डिवैल्पमैंट का कोई काम करना हो तो उसके लिए पैसे भी चाहिए। पैसों के बगैर तो कोई काम किया नहीं जा सकता। इनको तो खु ाी होनी चाहिए कि इनके इलाके में भी डिवैल्पमैंट के काम होंगे। अपोजी ान के भाई कहते है कि उनके इलाकों में काम नहीं किया जाता। अब इस टैक्स से जो पैसा आएगा, उतना ही पैसा और देकर उन इलाकों में सरकार काम करेगी और इनके इलाकों में भी अब बराबर का काम होगा। इनको यह बात सुनकर तो खु ाी होनी चाहिएं।

श्री मंगल सैनः जो आप कहते है, वह करते नहीं है।

चौधरी कटार सिंह छोकरः अध्यक्ष महोदय, इन को यह भ्रम है कि यह बोझ किसानों पर पड़ेगा। यह बात मेरी समझ में तो नहीं आई। यदि आपकी समझ में आई हो तो अलग बात है। हमने साफ लिखा है कि इस पैसे को खरीदने वाला देगा। आढती जब अपनी फसल को आगे बेचेगा तो उससे यह टैक्स वसूल किया

जाएगा। अनाज के मामले में आज हम आत्म निर्भर ही नहीं रहे बलिक अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा कर के बाहर भी भेजते है। हमारे यहां किसी भी फसल को खरीदने में एफ0सी0आई0 को मेजर भोयर है। जब कोई फसल मंडियों में आती है तो उस फसल का अस्सी प्रति ात से ज्यादा भाग एफ0सी0आई0 ही खरीदती है। किसान लोग अपना खर्चा अपनी जरूरत के मुताबिक फसल की कटाई के समय ही रख लेते है। इसी प्रकार से जो भीरी है या लेबरर है जो फसल की कटाई के समय ही रख लेते है। वे सारी फसल को मार्किट में नहीं लाते।

श्री बीरेंद्र सिंहः एफ0सी0आई0 भी तो आगे किसी को फसल बेचेगा।

श्री मंगल सैनः आप यही प्रोवाइड कर दें कि जो एजेंसी हरियाणा से बाहर फसल ले जायेगी उससे यह टैक्स लिया जाएगा।

चौधरी कटार सिंह छोकरः हरियाणा से अनाज कहीं भी जा सकता है लेकिन अनाज का मेजर पो ार्न एफ0सी0आई0 खरीदता है। आप सब मैम्बर साहिबान को पता है कि मंडियों से एफ0सी0आई0 कितना ज्यादा अनाज खरीदता है, जो कोई भी मंडियों से अनाज खरीदेगा उसको यह सैस देना पड़ेगा, चाहे एफ0सी0आई0 हो, चाहे कोई दूसरा हो। (व्यवधान) डा0 मंगल सैन जी कह रहे थे कि परचेजिंग के दो नियम होने चाहिए। मैं

उन्हें बताना चाहता हूं कि दो नियम नहीं हो सकते। अगर दो नियम बना भी दिये जाएं तो ये स्टैंड नहीं कर सकते। अगर ऐसे कानून बना सकते है तो डा0 मंगल सैन ही किसी गवर्नमैंट में बना सकते है, ये तो किसी पर कुछ कानून लागू कर देंगे, किसी पर कुछ लागू कर देंगे। इसलिए लीगली यह साउंड नहीं है और न ही दो सिस्टम वाली बात कभी चलने वाली है। जहां तक सैस लागू करने के उद्दे य की बात है, यह सब समझते है। इसका उद्दे य नेक है कि देहातों में छोटे मोटे कार्यों को करने के लिए यह पैसा खर्च किया जाएगा। यह सैस सारे दे ा में भी लग सकता है लेकिन अभी तो यह एक भुरूआत है। अभी इसके तजुर्बे भी देखने है, इसके परिणाम भी देखने है। इसको आप तजुर्बे के तौर पर कहें, चाहे कुछ कहें, इसके लाभ है और लाभ के साथ साथ कुछ धन भी इक्ट्ठा होगा। स्पीकर साहब, हमारी एक परे ाानी है जिसका सब को पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूं। हाउस में जो चर्चा भुरू से चलती रही और जो बात बार बार दोहराई जाती रही वह यही है कि करंट ईयर खत्म हो रहा है, 31 मार्च को खत्म हो जायेगा, इस साल हरियाणा गवर्नमैंट ने विकास के कार्यों पर खर्चे किये और आने वाले साल में इससे ज्यादा बढचढ कर खर्चे करने का इरादा है। यह इरादा तभी पूरा हो सकता है अगर हम अपनी आमदनी बढायेंगे और यह आमदनी बढ़नी चाहिए। अगर हम खर्चा ज्यादा करेंगे तो कहां से करेंगे, क्या कोई बाहर का आदमी खर्चा दे जाएगा? कोई नहीं देगा, हमें अपने रिसोंसिज बढाने ही पड़ेंगे,

लेकिन हमारी इस योजना को मैम्बर बार बार क्रिटीसाईज करते रहे। चेयरमैन साहब, पिछले साल हमारी प्लान 320 करोड़ की थी लेकिन इस साल 407 करोड़ की है। अध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा कि 87 करोड़ की जो वृद्धि हुई है, यह सारे दे ा की प्रति ातता से ज्यादा है। कुल मिलाकर सारे दे ा की योजना सौलह परसैंट बढ़ी है लेकिन इसके मुकाबले में हरियाणा प्रदे ा की 27 परसैंट बढ़ी है यानी नै ानल लैवल पर जो वृद्धि हुई है, हरियाणा में इससे दस परसैंट ज्यादा वृद्धि हुई है। इसका मुकाबला आप पंजाब स्टेट से कीजिए, सारे आंकड़े देख लीजिए कि इस ख्याल से उनकी प्लान कितनी है। हमारे ख्याल के मुताबिक उनकी प्लान 20–30 करोड़ रूपये ज्यादा होगी, तकरीबन 440 करोड़ के करीब होगी। पंजाब स्टेट में कृशि के लिए उद्योग के लिए इतने ज्यादा साधन होते हुए भी हमारी प्लान और उनकी प्लान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप तुलनात्मक दृश्टि से देखें, कोई खास फर्क नहीं हैं। स्पीकर साहब, कुछ माननीय सदस्यों ने एक और भ्रम की बात कही है कि प्रदे ा में डिवैल्पमैंट के काम करने के लिए पैसे का कोई प्रोवीजन नहीं किया है। मैं हाउस को बता देना चाहता हूं कि प्लान ऐलोके ान में जो वृद्धि हुई है, इसके लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए चाहता हूं कि प्लान एलोके ान में जो वृद्धि हुई है, इसके लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए 57 करोड़ रूपये का घाटा है। इस 57 करोड़ के घाटे में से 15 करोड़ रूपया अधिक आय बढाकर वसूल किया जाएगा। आठ करोड़ रूपया रूरल डिवैल्पमैंट सैस से वसूल होगा और सात

करोड़ रूपये की सेल्ज टैक्स में वृद्धि होगी। इस तरह से 57 करोड़ में से 15 करोड़ रूपया प्रदे ा की आय बढाकर पूरा करेंगे जिसके लिए छोटा सा सैंस के रूप में टैक्स लगाया है, इसको बाखु ी मानना चाहिए। इसके अलावा सैस पर आनरेबल मैम्बर्ज ने कोई वि ोश आपति भी नहीं की, ये तो मानेंगे ही, लेकिन मैं जनता के लिए कह रहा हूं कि यह बहुत अच्छी बात है, हैल्दी साईन है, इस पर हमने विकास की नींव डाल रखी है। अगर हमने निरन्तर प्रगति की रफ्तार को चालू रखना है तो यह सैस होना ही चाहिए। अगर हम विकास नहीं करेंगे, विकास के लिए पैसा नहीं जुटायेंगे तो विकास की गति धीमी करनी पड़ेगी और यह बात किसी को भी मंजूर नहीं है। गति को ठीक रखने के लिए ही आय बढाने की बात की है और इसीलिए सैस लगाया है। अब दूसरी बात सेविंग की है। दस करोड़ रूपया सेविंग के साधनों से जुटाने की बात कहीं गयी है। हमारे कर्मचारी अपनी आमदनी में से कुछ सेविंग करके कुछ रूपया सरकार के पास जमा करवायेंगे ताकि उनको कुछ लाभ हो, अच्छा ब्याज मिले, उनकी जरूरत के मुताबिक वक्त पर रूपया मिले। इनके लिए मकान देने की एक स्कीम है। इस स्कीम के तहत ये 15 साल तक सरकार के पास पैसा जमा करवायेंगे ताकि मकान ले सकें, उस रूपये पर च्रकवृद्धि ब्याज ओर दूसरी सहूलियात ले सकें। स्पीकर साहब, प्रोविडैट फंड पर इस वक्त आठ परसैंट ब्याज ले रहे है। अगर सरकारी मुलाजिम अपनी आय का साढे 12 परसैंट तक जितनी रा ाी जमा होगी उतनी ही रा ाी उतना ही कंट्रिब्यू ान सरकार

मैचिंग ग्रांट के रूप में कर्मचारी के नाम पर जमा करवायेगी। इस प्रकार कर्मचारियों के कुछ पैसे सरकार के पास जमा हो जायेंगे। मेरे कुछ साथियों ने बोलते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी तो पहले ही दबे हुए है, इन पर बड़ा भारी बोझ डाल दिया गया है। कुछ साथियों को इस बात की समण् ही नहीं आई कि बात क्या है। मास्टर ि ाव प्रसाद जी यही कहते रहे कि यह कम्पलसरी है। और भी कई साथियों ने कहा कि मुलाजमों को मार दिया गया है। आपने डा0 मंगल सैन जी की आखिरी पुकार सुनी होगी कि एम्पलाईज को मार दिया है। मेरे हिसाब से तो डा0 साहब तीन चार दिन से मरे पड़े है जब इन्होंने 14 तारीख को कहा था कि मैं कत्ल हो गया हूं, कट गया हूं। (व्यवधान)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, पता नहीं इन्होंने कहां से सुन लिया, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। (व्यवधान)

चौधरी कटार सिंह छोकरः अध्यक्ष महोदय, यह प्रोविडैंट फंड कम्पलसरी नहीं है, यह इनका भ्रम है, कर्मचारियों को भ्रम में डालने के लिए ऐसा कह रहे है। (व्यवधान) यह तो सेविंग के लिए प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सदन में बार–बार यह बात आई कि मंत्रिमंडल घटा दो, बोर्ड तोड़ दो। डा0 साहब और श्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि बहुत बड़ा मंत्रिमंडल बना दिया है। डा0 साहब और बीरेंद्र सिंह जी भाायद जानते है कि कितना बड़ा मंत्रिमंडल होना चाहिए और कितना छोटा होना चाहिए। (व्यवधान) जहां तक बोर्डज का ताल्लुक है, ये तो बहुत अच्छी

संस्थायें है। बोर्डज को कुछ काम संभाले है और इनकी अपनी आउट–पुट है। इनके जमाने में चौधरी देवी लाल जी ने छः छः एडवाईजर लगा रखे थे और सारे ही मैंटली कमजोर थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह और श्रीमती चंद्रावती कहा करती थी कि ये सारे के सारे एडवाईजर बावले है। (व्यवधान) तो मैं इनका यह भ्रम दूर करना चाहता हूं कि यह प्रोवीडैंट फंड कर्मचारियों पर कम्पलसरी नहीं होगा, कर्मचारी वालंटरी, अपनी मर्जी से जमा करवायेगा। यह अपनी रा ि ा बढाकर प्रोविडैंट फंड में जमा करवाये या न करवाये, यह उसकी अपनी मर्जी पर निर्भार करता है। यह अनुमान लगाना कि यह कम्पलसरी होगा, गलत है, अगर कम्पलसरी होता तो इससे कम से कम 100 करोउ़ रूपये की आमदनी होती। अध्यक्ष महोदय फाइनें ि ायल नीति के बारे में या तो किसी ने एतराज ही नहीं किया और अगर किया है तो निराधार है। एक बात मैं हाउस के सामने फिर अर्ज करना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों से हम उम्मीद करते है कि वे अपनी पांच परसैंट साल के दौरान बचत करें इससे उन्हें भविश्य में लाभ होगा। पिछले साल सरकारी कर्मचारियों को एडि ानल डी0ए0 देने के कारण उनके वेतन में साढे बारह परसैंट की वृद्धि हुई है। अभी उनकी और कि तें बकाया है। (ाोर) स्पीकर साहब, यह तो ऐसी बातें कर रहे है जैसे किसी दफ्तर में यही लोग बैठते है और यही हिसाब–किताब करते हो। हमने सरकारी कर्मचारियों को पांच कि ते दी है जिससे बीस करोड़ रूपये का बोझा सरकार को उठाना पड़ा है। पांच कि तें देने से साढे बारह परसैंट की

बढौतरी हुई है। अगर इसमें से ये पांच परसैंट बचत कर लें तो इनका कुछ जाता नहीं है, इससे उन्हें भविश्य में लाभी ही होगा। आज कि स्थिति यह है कि जून में इनकी कि त ड्यू हुई है। इसी तरह से कि तें आती रहती है वे दी जाती रही है। जून की कि त दी जाने वाली है। वह भी दे देंगे। (व्यवधान)

स्पीकर साहब अभी एक मिनट में खत्म करता हूं। इन्होंने जो नीति की बातें कहीं और कम खर्च करने की बातें कही है, वे सभी नोट कर ली है। हमारे प्र ाासनिक सचिवों ने भी सभी बातें ध्यान से सुनी है और नोट की है। जो भी उचित बात होगी वह की जाएगी लेकिन जो निराधार है वे नहीं मानी जायेंगी। इन भाब्दों के साथ मैं हाउस से रिक्वैस्ट करूंगा कि यह बजट पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः अब सदन दिनांक 21–3–1983, बाद दोपहर 2.00 बजे तक के लिए एडजर्न किया जाता है।

(13.00बजे)

(तत्प चात सदन सोमवार, दिनांक 21–3–83, बाद दोपहर 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ)